



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2016/चैत्र 10, 1938

No. 95]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2016/CHAITRA 10, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2016

(अंतिम जांच-परिणाम)

विषय : चीन जन.गण. और रूस में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "मिथाइलीन क्लोराइड" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी अंतिम जांच-परिणाम के संबंध में

सं. 14/33/2014-डीजीएडी.—यतः, समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात पाटनरोधी नियमावली अथवा नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) को भारत में मिथाइलीन क्लोराइड (जिसे एतदपश्चात विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) कहा गया है) का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स कैमप्लास्ट संमार लिमिटेड और मैसर्स गुजरात फ्लूरोकैमिकल्स लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात याचिकाकर्ता अथवा आवेदनकर्ता कहा गया है) से एक लिखित आवेदनपत्र चीन जनवादी गणराज्य और रूस (जिसे एतदपश्चात सम्बद्ध देश कहा गया है) से संबद्ध वस्तु के पाटन का आरोप लगाते हुए प्राप्त हुआ है।

2. यतः, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ओर से आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर कथित पाटन की मौजूदगी उसकी मात्रा और उसके प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश पर विचार करने के लिए नियमावली के उपनियम 6(1) के अनुसार, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए दिनांक 07 अप्रैल, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया।

क. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में अधोलिखित वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है :

- (i) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उपनियम 5(5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरुआत करने से पहले आवेदकों से पाटन का आरोप लगाते हुए आवेदनपत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में स्थित संबद्ध देशों के राजदूतावासों को इसकी सूचना प्रेषित की।
- (ii) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच का प्रारंभ करते हुए दिनांक 07 अप्रैल, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- (iii) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों तथा (जिनके विवरण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) और उद्योग एसोसिएशनों को प्रेषित की और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।
- (iv) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में इस संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात आयातकों (जिनके विवरण आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को प्रेषित की और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का सुझाव दिया।
- (v) प्राधिकारी ने इस आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की एक प्रति पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों को राजदूतावासों और ज्ञात निर्यातकों को उपलब्ध कराई। इस आवेदनपत्र की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई।
- (vi) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली की प्रतियां प्रेषित की :

- क. शांडांग डोंग्यूई कैमिकल्स कंपनी लिमिटेड
- ख. जियांगसू मिलान कैमिकल कंपनी लिमिटेड
- ग. झेजियांग जुहुआ कंपनी लिमिटेड
- घ. जोएससी खिमप्रोम
- ङ. कांग लांग हाइट
- च. जैपिंग चांगशान जिफेंग फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड
- छ. डालियान रिचफार्च्यून कैमिकल कंपनी
- ज. टिआन्जिन युआनलांग कैमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड।

- (vii) प्राधिकारी को संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों से प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ :

- क. शांडांग लिआओचांग लुक्सी सिक्स्थ कैमिकल फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
- ख. लु एक्स आई कैमिकल (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड, हांगकांग (निर्यातक)
- ग. शांडांग डोंग्यूई फ्लू सिलिकान मैटीरियल्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
- घ. निंग्बो जुहुआ कैमिकल एंड साइंस कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
- ङ. झेजियांग कुहना फ्लोर-कैमिस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
- च. फार्मासिनो होल्डिंग (एचके) लिमिटेड, हांगकांग (निर्यातक)
- छ. एच के मोटेज इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड, हांगकांग (निर्यातक)
- ज. खिमप्रोय पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, रूस

- (viii) तथापि चीन जन.गण. के किसी भी निर्यातक ने न तो बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे का दावा किया और न ही निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी की गई बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली का प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया। इसके अतिरिक्त, शांटांग लाओचेंग लक्सी सिक्सथ कैमिकल फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण., खिमप्रोय पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, रूस और भारत में रूसी परिसंघ के व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने विधिक प्रस्तुतिकरण दायर किए।
- (ix) भारत में इस संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए प्रेषित कीं :
- क. वर्धमान ट्रेडिंग कारपोरेशन
 - ख. हर्ष कुमार एंड कंपनी
 - ग. हिटैरोलैब्स लिमिटेड
 - घ. डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड
 - ङ. अरबिंदो फार्मा लिमिटेड
 - च. कोवैलेंट लैबोरेटरीज लिमिटेड
 - छ. रेनबैक्सी लैबोरेटरीज लिमिटेड
 - ज. रालकेम लिमिटेड
 - झ. मोरपियन लैब्स
 - ञ. सूर्या मेडिकेयर लिमिटेड
 - ट. इंडसोल ड्रग्स लिमिटेड
 - ठ. मेघमणि आर्गेनिक्स लिमिटेड
 - ड. यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड
 - ढ. केडीएल बायोटेक लिमिटेड
 - ण. सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - त. रैलिस इंडिया लिमिटेड
 - थ. एलेम्बिक लिमिटेड
 - द. हिंदुस्तान कैमिकल्स इंडस्ट्रीज
- (x) मैसर्स अरबिंदो फार्मा लिमिटेड, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड, संदीप आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने आयातक प्रश्नावली/प्रस्तुतिकरण दायर करके इस जांच शुरूआत अधिसूचना का प्रत्युत्तर दिया।
- (xi) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली एक सार्वजनिक में उपलब्ध कराया।
- (xii) यह जांच अक्टूबर, 2013 से प्रारंभ करके सितम्बर, 2014 (जांच की अवधि) तक की जांच की अवधि के लिए की गई थी। तथापि, क्षति विश्लेषण के संदर्भ में वर्ष 2011-12, 2013-14 और जांच की अवधि को शामिल किया गया।
- (xiii) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया कि वह जांच की अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों का विवरण उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने इस जांच परिणाम में डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सौदेवार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।

- (xiv) आवेदक द्वारा सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बनाने तथा उसकी बिक्री करने की लागत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार किया जिससे कि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (xv) प्राधिकारी ने, पाटनरोधी नियमावली और अधिनियम को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में अनंतिम पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश अपनी दिनांक 30.10.2015 की प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/33/2015--डीजीएडी के तहत की थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशें वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर ली गई और दिनांक 08.12.2015 की अधिसूचना संख्या 58/2015 के तहत अंतरिम शुल्क का उदग्रहण छह महीनों से अनधिक समय के लिए किया गया था।
- (xvi) प्राधिकारी ने दिनांक 22.01.2016 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने इस सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त किए थे उनसे अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से अभिव्यक्त अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुतिकरण करें। लिखित प्रस्तुतिकरणों/प्रति-प्रत्युत्तरों में हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त तर्कों पर विचार किया गया है।
- (xvii) आवेदकों द्वारा और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना और आंकड़ों का सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। सहयोगकर्ता उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में उनके अभिलेखों की पुष्टि टेबल – स्टडी के आधार पर की गई थी।
- (xviii) संबंधित नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों वाले प्रकटन विवरण जो इस जाँच में अंतिम जाँच परिणामों का आधार होंगे को 17.02.2016 को जारी किया। हितबद्ध पक्षकारों ने उसके संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत की और संगत अनुरोधों का अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना में समाधान और जाँच की गई है।
- (xix) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए उन प्रस्तुतिकरणों का, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया, इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में समाधान कर दिया गया।
- (xx) इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में *** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है और प्राधिकारी ने नियमों के अंतर्गत उसे वैसा ही माना है।
- (xxi) जांच की इस अवधि के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डालर = 61.65/-रुपए है।

ख. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

घरेलू उद्योग के विचा

4. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किया है:

- क) मिथाइलीन क्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका आण्विक फार्मूला सीएच₂सी₂ होता है। यह एक रंगहीन द्रव होता है जिसका ईथर की तरह की सुहावनी सुगंध होती है और इसका प्रयोग साल्वेंट के रूप में प्रचुर मात्रा में किया जाता है। प्रयोग की अधिकांश स्थितियों के अंतर्गत यह ज्वलनशील नहीं है पर अधिक गर्म करने पर यह जल सकता है।
- ख) इस उत्पाद के अन्य ज्ञात ग्रेड भी हैं। तथापि, इसका व्यापार (टैंकरों में) खुले तौर पर और पैकड (ड्रमों में) रूप में किया जा सकता है, तद्वारा उसका कीमत पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
- ग) मिथाइलीन क्लोराइड को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत सीमाशुल्क उप-शीर्षक 29031200 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

- घ) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्मों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों वितरण एवं विपणन और वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसे गुण धर्मों के रूप में तुलनीय हैं। क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन का परिकलन नर्बद्ध/अनपैकड और पैकड उत्पादों के लिए अलग-अलग किया गया है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

5. किसी भी अन्य निर्यातक, उत्पादक अथवा उपभोक्ता ने इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई विचार व्यक्त नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

6. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. और रूस का मूल का अथवा वहां से निर्यातित "मिथाइलीन क्लोराइड" है जिसे "डाइक्लोरोमिथेन" और "मिथाइलीन डाइक्लोराइड" (एमडीसी) के रूप में भी जाना जाता है।

7. मिथाइलीन क्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका आण्विक फार्मूला सीएच₂सी₂ होता है। यह एक रंगहीन द्रव होता है जिसका ईथर की तरह की सुहावनी सुगंध होती है और इसका प्रयोग साल्वेंट के रूप में प्रचुर मात्रा में किया जाता है। प्रयोग की अधिकांश स्थितियों के अंतर्गत यह ज्वलनशील नहीं है पर अधिक गर्म करने पर यह जल सकता है। मिथाइलीन क्लोराइड उच्च ताप पर अपघटित भी हो सकता है जिससे विषाक्त गैसें उत्पन्न होती हैं। यह विभिन्न प्रकार के विलायकों के साथ पूर्णतया मिश्रणीय है। एमडीसी एक विलायक है और इसका प्रयोग पालीकार्बोनेट और फिनोलिकरेजिन्स, रेयन यार्न, फार्मास्युटिकल्स, कृषि एवं सुगंध का विनिर्माण करने के लिए किया जाता है। यह खाद्य बसा, कोकोआ, मक्खन और सतों के निस्सारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।

8. मिथाइलीन क्लोराइड का उत्पादन करने के लिए दो प्रविधियां हैं – मिथेन पथ और मेथानाल पथ दोनों तरीकों से उत्पादित उत्पाद के अनिवार्यतः समान प्रविधि विनिर्देशन हैं। मिथाइलीन क्लोराइड को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत सीमाशुल्क उप-शीर्षक 29031200 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

9. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(घ) समान वस्तु को निम्नवत परिभाषित करता है।

"समान वस्तु" का आशय उस वस्तु से जो भारत में पाटित की जा रही जांचाधीन वस्तु के सभी तरह से समान या समरूप हो या ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी तरह से समान न हो फिर भी उसके गुणधर्म जांचाधीन वस्तु के निकटतम समान हों।

10. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्मों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों वितरण एवं विपणन और वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसे गुण धर्मों के रूप में तुलनीय हैं। उपभोक्तागण इनका प्रयोग अंतर्बदल करके कर रहे हैं।

ग. घरेलू उद्योग एवं आधार

11. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत निम्नवत परिभाषित किया गया है :-

"घरेलू उद्योग" का आशय समान वस्तु के विनिर्माण या उससे संबंधित किसी अन्य क्रियाकलाप में समग्र रूप से लगे उन सभी घरेलू उत्पादकों अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के समस्त घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता है, सिवाय इसके कि यदि ये उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हो पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों अथवा उसके स्वयं आयातक हो तो ऐसे मामलों में वाक्यांश "घरेलू उद्योग" को केवल शेष उत्पादकों के रूप में माना जाएगा।"

12. यह आवेदनपत्र मैसर्स केमप्लास्ट सन्मार लिमिटेड और मैसर्स गुजरात फ्लूरोकैमिकल्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। इस आवेदनपत्र के अनुसार इस उत्पाद के गुजरात अल्कलाइ एंड कैमिकल्स लिमिटेड और एसआरएफ

लिमिटेड नामक दो अन्य उत्पादक भी हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का लगभग *** प्रतिशत उत्पादन बनता है और इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया उत्पादन भारत में उत्पादित समान उत्पाद के कुल उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता है। इसके अतिरिक्त, आवेदनपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि किसी भी याचिकाकर्ता ने इस विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है, और न ही इस विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक अथवा निर्यातक से उनका कोई संबंध है।

13. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर और नियमावली को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि यह आवेदनपत्र घरेलू उद्योग द्वारा अथवा घरेलू उद्योग की ओर से किया गया है और यह आवेदनपत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत "आधार" की जरूरत को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता है और याचिकाकर्ता कंपनियां पात्र घरेलू उद्योग हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" है।

घ. विविध प्रस्तुतिकरण

14. जाँच शुरूआत के बाद मैसर्स शांडांग लिआन्चेंग लुक्सी सिक्सथ कैमिकल फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. और खिमप्रोय पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, रूस के अलावा अन्य किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया है। उनके द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं :

- (i) जांच की अवधि के दौरान ईयू, कोरिया और यूएसए से किए गए आयात 77 प्रतिशत है। यह प्रस्तुतिकरण किया गया कि मौजूदा जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति उक्त देशों से आयात के कारण हुई है न कि संबद्ध देशों से आयात के कारण।
- (ii) जांच की अवधि के दौरान उन देशों से लगभग 80 प्रतिशत आयात हुआ जिन पर पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) लगा था और रूस से आयातों का हिस्सा न्यूनतम से कम अर्थात् लगभग 2.94 प्रतिशत है।
- (iii) घरेलू उद्योग ने संपूर्ण आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। जून, 2014 तक के आयात आंकड़े ही उपलब्ध कराए गए हैं और जुलाई, 2014 – सितम्बर, 2014 तक की अवधि के आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। संपूर्ण आयात आंकड़े के अभाव में निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू का दावा निरर्थक हो जाता है।
- (iv) घरेलू उद्योग ने जांच के लिए दो विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आयात आंकड़ों का उपयोग किया है अर्थात् डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़े और टिप्स साफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त आंकड़े, जबकि समान उत्पाद के लिए विभिन्न देशों से किए गए आयातों की विगत जांच में घरेलू उद्योग ने केवल एक ही स्रोत अर्थात् डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया था।
- (v) यह आवेदनपत्र साक्ष्य एवं सूचना के निर्बंधनों में यथार्थता एवं उपयुक्तता की कसौटी पर खरा उतरने में असफल रहा है। पाटन, क्षति, जहां कहीं लागू हो और पाटित आयातों तथा आरोपित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के साक्ष्य प्रदान कराए जाने चाहिए थे।
- (vi) भारत में होने वाले अधिकांश आयात शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत किए जाते हैं जो पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन नहीं होते हैं। इसलिए इन आयातों का अपवर्जन कर देना अपेक्षित है।
- (vii) रूस का कीमत अधोरदन चीन के कीमत अधोरदन की तुलना में अधिक दर्शाया गया है जबकि उतराई मूल्य रूस के उतराई मूल्य की तुलना में चीन का उतराई मूल्य अधिक है। इससे यह संकेत मिलता है कि कीमत अधोरदन कृत्रिम है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

15. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों का प्राधिकारी द्वारा निम्नवत विश्लेषण किया गया है :

- क. इस तर्क के संबंध में कि रूस से आयात न्यूनतम से कम है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जब वर्तमान जांच प्रारंभ की गई थी तब रूस से आयातों का हिस्सा 3.40 प्रतिशत था। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए आयातों की मात्रा एवं मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सौदेवार आंकड़ों को अपनाया है। यह नोट किया जाता है कि रूस से आयातों का हिस्सा न्यूनतम से अधिक (4.44 प्रतिशत) है।

- ख. इस तर्क के संबंध में कि उन देशों से आयातों का आयातों में बड़ा हिस्सा है जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है और वे आयात की क्षति कारित कर रहे हैं। यह नोट किया जाता है कि उन देशों से होने वाले आयात में कमी आई जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा था, जबकि संबद्ध देशों से हुए आयातों में क्षति की अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन पर्याप्ततः सकारात्मक है जिससे प्रदर्शित हो रहा है कि संबद्ध देशों से पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं।

विवरण	मापन की इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	जांच की अवधि
संबद्ध देश	एमटी	16,514	334	6,757	15,629
वह देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	एमटी	60,974	56,324	62,444	47,571
अन्य देश	एमटी	6,956	279	484	540
कुल आयात	एमटी	84,444	56,936	69,685	63,739

- ग. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने इस याचिका के लिए दो भिन्न स्रोतों अर्थात् डीजीसीआईएंडएस और टिप्स साफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त आयात आंकड़ों को अपनाया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत के स्तर पर प्राधिकारी को स्वयं को इस बात के लिए संतुष्ट करना अपेक्षित होता है कि जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और घरेलू उद्योग ने उस अवधि तक के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया है जिसके लिए उस स्तर पर वह आंकड़े उन्हें उपलब्ध थे। तथापि, इस समय, डीजीसीआईएंडएस के सौदेवार आंकड़े उपलब्ध हो गए हैं और प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के सौदेवार आंकड़े प्राप्त कर लिए हैं और वर्तमान निर्धारण के प्रयोजनार्थ विश्लेषण डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।
- घ. इस तर्क के संबंध में कि भारत को किए गए अधिकांश आयात अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए हैं और इसलिए उनका अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत किए गए आयातों के प्रतिस्पर्धा का सृजन होता है और वह कीमत में परिवर्तन कर देते हैं क्योंकि आयातक उन विदेशी निर्यातकों अथवा घरेलू उत्पादकों से वस्तु का प्रापण करते हैं जो उन्हें वह वस्तु प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध कराते हैं। इसलिए, शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत किए गए आयात के लिए यह नहीं माना जा सकता है कि उन्होंने बाजार कीमतों को प्रभावित नहीं किया होगा और इसलिए आयातों का निश्चयन करते समय उनका अपवर्जन नहीं किया जा सकता है।

16. इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और उसकी आपूर्ति दो रूपों में की जाती है – (क) खुले रूप में भारी मात्रा में पोतलदान और (ख) पैकड रूप में पोतलदान। प्राधिकारी ने खुले/पैक न किए गए और पैक किए गए आयातों के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का अलग-अलग निर्धारण किया है। पाटन मार्जिन का निर्धारण भारित औसत के आधार पर किया गया है।

घरेलू उद्योग और प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों की मौखिक सुनवाई के बाद की टिप्पणियां

17. मौखिक सुनवाई के बाद प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

- निर्यातक की सूचना को स्वीकार नहीं करना और वर्तमान जाँच में उन्हें अलग व्यवहार देने से इनकार निर्यात कीमत निर्धारित करने संबंधी कानून और संगत पाटनरोधी प्रावधानों को समझे बिना किया गया है।
- कुछ निर्यातकों को स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुच्छेद 6.1 के अंतर्गत यथा विचारित हितबद्ध पक्षों के अधिकारों संबंधी आवश्यक प्रक्रिया पर ध्यान दिए बिना असंबंधित व्यापारियों के जरिए उनके निर्यातों के लिए संपष्टीकरण मांगे बिना प्रतिकूल व्यवहार प्रदान किया गया है।
- निर्यातकों ने संबंधित व्यापारी और असंबंधित व्यापारी के जरिए भारत को बिक्रियों के लिए उनके उत्तर में पूरी सूचना उपलब्ध कराई है। निर्यातक 'पूरी मूल्य श्रृंखला' का अर्थ समझने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि

पाटनरोधी कानून में ऐसा कोई कानून नहीं है। पाटनरोधी कानून में प्रयुक्त शब्द आवश्यक सूचना या तर्कसंगत रूप से उपलब्ध सूचना है। आवश्यक सूचना या तर्कसंगत रूप से उपलब्ध सूचना शब्दों को 'पूरी मूल्य श्रृंखला' शब्दों से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।

- iv. यह देखा जा सकता है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए निर्यात कीमत को अस्वीकार करने या असंबंधित व्यापारियों की सूचना प्रदान नहीं करने के आधार पर व्यक्तिगत व्यवहार से इनकार करने का प्रावधान हो।
- v. यह पर्याप्त है यदि निर्यातक ने उसे तर्कसंगत रूप से उपलब्ध आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई हो और यह कि उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है और उस पर ऐसी सूचना प्रदान करने का अनावश्यक दबाव नहीं डाला जा सकता है जो उसके नियंत्रण से बाहर हो।
- vi. असंबंधित व्यापारियों के उनकी सूचना/उत्तर नहीं देने के मामले में, निर्यातक के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण तर्कसंगत रूप से व्यापारियों को इन वस्तुओं के लिए बनाए गए बिलों में दी गई कीमत पर विचार करते हुए किया जा सकता है क्योंकि यह सूचना निर्यातक/उत्पादक के पास तत्काल उपलब्ध होगी जैसाकि ईसी द्वारा उसके समक्ष आए विभिन्न मामलों में किया गया है।
- vii. इस संबंध में, हम प्राधिकारी का ध्यान जापान से *कतिपय हाट-रोल्ड स्टील उत्पादों पर यूएस-पाटनरोधी उपायों में डब्लूटीओ अपीलीय निकाय की रिपोर्ट(डब्लूटी/184/एबीआर) दिनांक 24 जुलाई, 2001* की ओर दिलाना चाहते हैं जिसमें यह माना गया कि जाँचकर्ता प्राधिकारी निर्यातक पर उसके नियंत्रण से बाहर की सूचना के संबंध में समग्र मानकों पर जोर नहीं दे सकते हैं या उन पर अतर्कसंगत बोझ नहीं डाल सकते हैं।
- viii. पक्षपात के बिना, लक्सी ने आईबीआईएस के आयात आकड़ों से असंबंधित व्यापारियों के जरिए किए गए निर्यातों के ब्योरे छांटे और उन्हें रिकार्ड में रखा गया है। उनमें वह आकलन योग्य मूल्य या अंतिम कीमतें दर्शाई गई हैं जिनपर असंबंधित व्यापारियों के जरिए भारत को वस्तुओं के निर्यात किए गए हैं। लक्सी ने विनमार इंटरनेशनल लि., कोसमोस वीयू लि. और ट्रिकान एनर्जी लि. से पैकिंग सूचना आदि के साथ वाणिज्यिक मालसूचियों की प्रतियां भी प्राप्त की हैं और उन्हें रिकार्ड में भी रखा गया है। ट्रिकॉन ड्राई कैमिकल्स, एलएलसी, यूएसए ने भी निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं। अब सभी निर्यातकों का पूरा उत्तर प्रस्तुत कर दिया गया है।
- ix. प्राधिकारी डीजीसीआईएंडएस से उनके आकड़ों में आईबीआईएस आयातों की तुलना में कम आयातों के लिए कारण/स्पष्टीकरण मांग सकते हैं जैसा कि चीन, ईयू, कोरिया और थाइलैंड से पीटीए के मामले (मामला सं. 14/7/2013-डीजीएडी) (पैरा 20(xvii)) में किया गया है। यह मानना मुश्किल है कि डीजीसीआईएंडएस के अनुसार आयात आकड़े आईबीआईएस में बताए गए आयात आकड़ों से कम होंगे। अतः लक्सी ने प्राधिकारी से न्याय और उचित जाँच के हित में वर्तमान मामले में आयात आकड़ों के संपूर्ण विश्लेषण का अनुरोध किया था।
- x. यह बताना महत्वपूर्ण है कि डीजीसीआईएंडएस से सौदावार आयात ब्योरे प्राइवेट पक्षों को उपलब्ध नहीं हैं। रोचक है कि घरेलू उद्योग ने अपने पाटनरोधी आवेदन में अप्रैल 11-मार्च 12 की अवधि के लिए डीजीसीआईएंडएस के सौदावार आयात आकड़ों का प्रयोग किया है। तथापि घरेलू उद्योग ने डीजीसीआईएंडएस के सौदावार आयात आकड़ों को प्राप्त करने के लिए रिकार्ड में कोई बात नहीं बताई है। यदि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को डीजीसीआईएंडएस के सौदावार आकड़ें उपलब्ध कराए हैं तो उन्हें लक्सी से गोपनीय नहीं रखा जा सकता है और प्रारंभिक जांच परिणामों के लिए प्रयुक्त डीजीसीआई एंड एस के सौदावार आयात आकड़ों को समानता और औचित्य के सिद्धांतों के मद्देनजर लक्सी को भी प्रकट किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, टिप्स साफ्टवेय से घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त सौदावार आयात आकड़ों को भी सत्यता के कारण उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि हम टिप्पणियां दे सकें।
- xi. यह अनुरोध किया जाता है कि सटीकता और पर्याप्तता के संबंध में अनुरोधों को प्रारंभिक जाँच परिणाम में शामिल नहीं किया गया है और प्रारंभिक जाँच परिणाम में उनका समाधान भी नहीं किया गया है।

- xii. घरेलू उद्योग द्वारा दायर किये गए आवेदन में कमियां हैं क्योंकि इसमें वैध और पूर्णतः दस्तावेजी आवेदन के रूप में माने जाने के लिए कानून के अंतर्गत अपेक्षित साक्ष्य और सूचना नहीं हैं। पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार, प्राधिकारी तब तक पाटनरोधी जाँच की शुरुआत नहीं कर सकते हैं जब तक कि (क) वह यह निर्धारित करें कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है और (ख) वह आवेदन में प्रदत्त साक्ष्य की सत्यता और पर्याप्तता की जाँच नहीं करें और स्वयं को संतुष्ट न कर लें कि पाटन, क्षति और जाँच शुरुआत को सही ठहराने के लिए कारणात्मक संबंध मौजूद है। यह निर्धारण कि यह आवेदन समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है और पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध है, ऐसी पूर्व शर्तें हैं जिन्हें जाँच की शुरुआत करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए।
- xiii. यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने कोई विधिसम्मत कारण बताये बिना और नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विस्तृत प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए काफी सूचना को गोपनीय रखा है। घरेलू उद्योग ने आवेदन के साथ न तो टिप्स साफ्टवेयर सर्विसेज लि. और डीसीसीआईएंडएस से उनके द्वारा प्राप्त अपरिष्कृत/मूल सौदावार आयात आकड़ों की कोई प्रति (साफ्ट प्रति/हार्ड प्रति) प्रदान की गई है और न ही उन्होंने यह बताया है कि उन्हें प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया है। वह सार्वजनिक फाइल में भी नहीं है। सौदावार छांटे गए आयात आकड़ों की एक्सेल फाइल की साफ्ट प्रति, अपरिष्कृत/मूल आयात आकड़े और टिप्स साफ्टवेयर सर्विसेज लि. और डीजीसीआईएंडएस से बाहर रखे गए सौदों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। घरेलू उद्योग ने टिप्स साफ्टवेयर सर्विसेज लि. और डीसीसीआईएंडएस से उनके द्वारा प्राप्त अपरिष्कृत/मूल सौदावार आयात आकड़ों के साथ अलग किए गए सौदावार आयात आकड़ों की एक्सेल फाइल की साफ्ट प्रति जिसका प्रयोग पीओआई (अक्तूबर 13 से सितंबर 2014) और पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए आवेदन में किया गया है, को उपलब्ध नहीं कराया है। कंपनी-वार उत्पादन व्योरो को गोपनीय रखा गया है। निर्यात कीमत से दावा किए गए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा, वैट आदि जैसे समायोजनों के व्योरो के भी गोपनीय होने का दावा किया गया है। चीन के संबंध में कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री का व्योरा भी नहीं बताया गया है और उन्हें केवल रेंजों में बताया गया है। प्रतिशत रूप में लाभ/हानि और नियोजित पूंजी पर आय का प्रकटन भी नहीं किया गया है।
- xiv. यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने पूरी जाँच अवधि के लिए संपूर्ण आयात आकड़ों को उपलब्ध नहीं कराया है। घरेलू उद्योग की ओर से यह एक गंभीर चूक है और स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि घरेलू उद्योग का आवेदन केवल इसी आधार पर ही सत्यता और पर्याप्तता के परीक्षण को पूरा नहीं करता है।
- xv. पक्षपात के बिना, यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदन के लिए आयात आकड़ों का प्रयोग दो अलग-अलग स्रोतों से किया गया है अर्थात् अप्रैल 2011 से मार्च 2012 की अवधि के लिए डीजीसीआईएंडएस आयात आकड़े और अप्रैल 12 - मार्च 13, अप्रैल 13 -मार्च 14 और अप्रैल 14 से जून 14 की अवधियों के लिए टिप्स साफ्टवेयर सर्विसेज प्रा. लि. से आयात आकड़े। तथापि घरेलू उद्योग ने इस प्रकार से आयात आकड़ों को प्रयोग करने के लिए और एक ही स्रोत से आकड़ों का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, के लिए रिकार्ड में कोई कारण नहीं बताया है। चयनित आयात आकड़ों की सत्यता का सत्यापन नहीं किया जा सकता है।
- xvi. यह भी देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग ने बल्क और पैकड उत्पाद के लिए अलग से विश्लेषण का दावा किया है। तथापि, प्रदत्त आयात आकड़ों की पीडीएफ प्रति से लक्सी आवेदन के भाग के रूप से इस प्रकार प्रदत्त आयात आकड़ों की हार्ड प्रति से इस पहलू की पहचान नहीं कर सकता है। प्रत्येक आयात सौदे के लिए पूरा विवरण स्पष्ट नहीं है क्योंकि उसे घरेलू उद्योग द्वारा छिपाया गया है।
- xvii. आयात आकड़ों के विश्लेषण के बाद, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा अम.डा. और भारतीय रुपये दोनों के मूल्यों को उन्हें मिश्रित करके माना गया है जिससे आयात कीमतों का और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति का गलत और गुमराह करने वाला विश्लेषण होगा।
- xviii. यह देखा जा सकता है कि स्वीकार्य रूप से अन्य देशों से भारी और काफी आयात हुए हैं जो जाँच अवधि में 77 प्रतिशत के उच्च स्तर पर हैं। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति अन्य देशों से आयातों और न कि वर्तमान जाँच में संबद्ध देशों से आयातों के कारण हुई है।

- xix. यह अनुरोध किया जाता है कि भारत में हुए अधिकांश आयात भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही शुल्क मुक्त स्कीमों जैसे अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किये गये हैं जो पाटनरोधी शुल्क के अधीन नहीं हैं। माननीय सेस्टेट ने थाइ एक्रिलिक फाइबर कं. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माना कि अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयातित वस्तुएं अनन्य रूप से निर्यात उत्पाद होती हैं और इसलिए ऐसे आयातों को भारतीय बाजार में प्रवेश हुआ नहीं कहा जा सकता है। अतः जब शुल्क मुक्त स्कीमों के अंतर्गत आयात भारतीय बाजार में प्रवेश नहीं करते हैं तो उन्हें पाटनरोधी जाँच के अधीन भी नहीं माना और नहीं रखा जा सकता है और यह कि उन आयातों को घरेलू उद्योग पर आयातों के उचित और न्यायसंगत विश्लेषण के लिए और वर्तमान जाँच के निष्कर्षों के लिए जाँच से बाहर रखा जाना चाहिए।
- xx. चीन के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में, यह देखा जा सकता है कि इस पैराग्राफ के उपबंधों के अनुसार, प्राधिकारी को सर्वप्रथम सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की पहचान करनी होगी केवल तभी जहां ऐसे तीसरे देश से आवश्यक आकड़े प्राप्त करना संभव नहीं हो, वहां समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत जिसमें यदि आवश्यक हो तो तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करते हुए, सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर निर्धारण किया जा सकता है। तथापि, वर्तमान मामले में कानून द्वारा विहित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है क्योंकि हितबद्ध पक्षों को न तो तीसरे देश के चयन के बारे में जानकारी दी गई और न ही हितबद्ध पक्षों से तीसरे देश के बारे में सुझाव देने और आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इस प्रकार अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारण, वर्तमान कार्यवाही को जारी नहीं रखा जा सकता और वह शेनयांग मतसुसिता 2005 (181)ईएलटी 320 (एससी) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय जो इस मामले से सीधे संबंधित है, को देखते हुए अव्यवहार्य है।
- xxi. क्षति संबंधी विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण वर्ष 2012-13 से किया गया है परंतु आधार वर्ष 2011-12 से नहीं किया गया है। क्षति जाँच अवधि के दौरान क्षति संबंधी मापदंडों का विश्लेषण आरंभिक बिन्दु से अंतिम बिन्दु तक किया जाना चाहिए। पीओआई के आकड़ों की तुलना वर्ष 2012-13 के आकड़ों से करने से 2011-12 की सूचना निरर्थक हो गई। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने इस प्रकार से क्षति विश्लेषण करने को न्यायसंगत सिद्ध नहीं किया है।
- xxii. यह अनुरोध किया जाता है कि दोनों संबद्ध देशों के लिए प्रपत्र IVक और प्रपत्र IVख में प्रदत्त घरेलू बिक्री कीमत के ब्योरे, चीन के लिए प्रपत्र IVख और रूस के लिए प्रपत्र IVख भिन्न-भिन्न हैं। इसके अलावा रूस के लिए कीमतकटौती चीन के लिए कीमत कटौती की तुलना में अधिक दर्शाई गई है जबकि चीन के लिए पहुंच मूल्य रूस के पहुंच मूल्य से अधिक है। यह स्पष्टतः दर्शाता है कि वर्तमान मामले में कीमत कटौती को कृत्रिम रूप से सृजित किया गया जबकि वह मौजूद नहीं है।
- xxiii. उक्त अनुरोधों के पूर्वाग्रह के बिना यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग को उनके आवेदन में दी गई क्षति संबंधी सूचना और प्रारंभिक जाँच परिणामों में दी गई क्षति संबंधी सूचना के आधार पर कोई क्षति नहीं हुई है। संबद्ध देशों से आयातों में क्षति जाँच अवधि के दौरान समग्र रूप से और घरेलू उत्पादन और भारत में कुल मांग की तुलना में गिरावट आई है। क्षति जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष में 34 प्रतिशत और पीओआई में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिससे कोई क्षति नहीं प्रदर्शित होती है। क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मूल्यों और बिक्री कीमतों सभी में क्षति जाँच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है जिससे इन कारकों के संबंध में कोई क्षति नहीं होने का पता चलता है। चीन के संबंध में कोई कीमत कटौती नहीं हुई है जैसा कि प्रारंभिक जाँच परिणाम में प्रदत्त ब्योरे से देखा जा सकता है। इस प्रकार, इस कारक के संबंध में घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग का कोई कीमत ह्रास या कीमत न्यूनीकरण नहीं हुआ है। यद्यपि क्षति जाँच अवधि में नई कारकों में गिरावट आई है तथापि पूर्ववर्ती वर्ष 2012-13 की तुलना में पीओआई में इन कारकों में काफी सुधार हुआ है जिससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों से आयातों के कारण नहीं हुई है बल्कि अन्य देशों से आयातों के कारण हुई है जो काफी अधिक लगभग 80 प्रतिशत है। घरेलू उद्योग के निष्पादनसंबंधी विभिन्न मापदंडों में क्षति जाँच अवधि के दौरान सुधार हुआ है जिससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता प्रभावित नहीं हुई है। संबद्ध देशों से कथित पाटित आयातों

और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि रूस से आयात न्यूनतम सीमा से कम हैं, ईयू, यूएसए और कोरिया से भारी आयात हुए हैं। संबद्ध देशों से आयातों में समग्र रूप से और कुल मांग और घरेलू उत्पादन के अनुसार क्षति जाँच अवधि के दौरान गिरावट आई है। दूसरी ओर घरेलू उद्योग की बिक्री, उत्पादन और बाजार हिस्से में भारी वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि संबद्ध देशों से आयातों का घरेलू उद्योग की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और संबद्ध देशों से आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। यह अनुरोध किया गया है कि संबद्ध देशों से आयात कीमतों में क्षति जाँच अवधि के दौरान 9 प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि क्षति जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार आयात कीमतों से घरेलू कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

- xxiv. पीजेएससी खिमग्राम मानती है कि रूस संघ के विरुद्ध आवेदन को डब्लूटीओ करार के अनुसार समाप्त कर दिया जाएगा। वर्तमान जाँच में जाँच अवधि के दौरान भारत में उत्पाद के कुल आयात और रूस से आयात की राशि से संबंधित आकड़ों का महत्वपूर्ण अर्थ है क्योंकि उनकी सत्यता इस निष्कर्ष का पहला और प्रमुख आधार है कि पाटन हुआ था या नहीं। मै. शानडानेलिओचेंग लुक्सी सिक्स्थ फर्टिलाइजर कं. लि. और मै. लु सी कैमिकल (हांगकांग) कं. लि. द्वारा किए गए अनुरोध में आईबीआईएस आकड़े दर्शाते हैं कि पीओआई से पहले प्रत्येक पहले वर्ष और पीओआई में भी रूस से आयातों की मात्रा कुल आयातों की मात्रा के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
- xxv. पीजेएससी खिमग्राम ने अनुरोध किया है कि 2013-2014/2014-2015/2015-2016 भारतीय वर्षों (भारत को रूस से उत्पाद के आयात के संबंध में) या 2013-2014/2014-2015 रूसी वर्ष (भारत को रूस से उत्पाद के निर्यात के संबंध में) जैसी सभी संभावित तुलनीय अवधियों के बीच ऐसी कोई अवधि नहीं है जब उत्पाद की राशि नगण्य स्तर से अधिक है।
- xxvi. पीजेएससी खिमग्राम ने अनुरोध किया है कि रूसी उत्पाद की मात्रा जिसे रूसी वर्ष 2015 के दौरान भारत को आयात (1296 टन) किया गया था वर्ष 2014 की मात्रा (2054 टन) से कम है। यह तथ्य कि 2015 में अंतरिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, आयातों की मात्रा को प्रभावित नहीं कर सकता है क्योंकि उसे नवम्बर, 2015 में लगाया गया था। इसी के साथ, भारत में उत्पाद का कुल आयात बढ़ गया है (2014-15 भारतीय वर्ष में 66,7 मी.टन से 2015-16 भारतीय वर्ष, जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, में 74,4 मी.टन)। इस तथ्य को नोट करना महत्वपूर्ण है कि खिमग्राम रूस में उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है (अन्य विनिर्माता वोल्गोग्रेड खिमग्राम ने दिसंबर, 2014 में दिवालिया होने के कारण इस कार्यकलाप को हमेशा के लिए बंद कर दिया) और 2015 के दौरान रूस से उत्पाद के निर्यात की राशि उसी अवधि के दौरान खिमग्राम के निर्यात की राशि के बराबर है।
- xxvii. पीजेएससी खिमग्राम ने अनुरोध किया है कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि रूस से संभावित आयात भी 3 प्रतिशत से अधिक हो जाएंगे।
- xxviii. खिमग्राम के ड्रम सौदों के रूप में रिकार्ड किए गए के संबंध में आयात की मात्रा के आकड़ों में कुछ विशिष्ट विरोधाभास हैं। खिमग्राम भारत को रूस से निर्यात केवल ड्रमों में करता है (1 ड्रम का मानक वाल्यूम 0,27 मी.टन है)। यह मात्रा अपरिवर्तनीय है अर्थात् ड्रम में तकनीकी कारण से उत्पाद की 0.27 मी.टन से अधिक या कम मात्रा डालना असंभव है। निर्यात के सभी परिवहन दस्तावेज और गुणवत्ता प्रमाणपत्र भी यही प्रदर्शित करते और इस बात की पुष्टि करते हैं कि उत्पाद की निवल राशि, जिसका निर्यात किया गया है, हमेशा 0.27 मी.टन की गुणज होगी। यह असंभव और निरर्थक है कि परिवहन के दौरान कहीं पर किसी ड्रम को विभाजित या रीटेयरिंग की जा सकती हो। इसका अर्थ है कि जब उत्पाद की कोई खेप भारतीय सीमाशुल्क सीमा के पास आती है जहां उसे डीजीसीआईएंडएस और अन्य डाटाबेस के लिए रिकार्ड किया जाता है, उसका भार हमेशा 0.27 टन के गुणज में होना चाहिए। परंतु आवेदन में अनेक ऐसे सौदे हैं (डीजीसीआईएंडएस और टिप्स साफ्टवेयर सर्विसेज प्रा. लि. के डाटाबेस से) जिनका भार 0.27 मी.टन का गुणज नहीं है।
- xxix. खिमग्राम के लिए अलग पाटन मार्जिन नहीं निर्धारित किया जाना कानून के विरुद्ध है। प्रारंभिक जाँच परिणाम में बताया गया है कि कंपनी खिमग्राम ने प्रश्नावली में पर्याप्त उत्तर प्रस्तुत नहीं किये हैं और यह कि

संबद्ध निर्यातकों से पूर्ण मूल्य श्रृंखला के अभाव में, प्राधिकारी ने भारत में विधिवत रूप से समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर रूस के लिए सामान्य मूल्य का अनंतिम रूप से परिकलन किया है। इस संबंध में इस पर आपत्ति है कि लागू कानूनों में ऐसी किसी प्रक्रिया की मौजूदगी जैसा कुछ भी नहीं है जो प्राधिकारी को किसी भी परिस्थिति में घरेलू उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य के परिकलन का अधिकार देता हो। इसके अलावा, प्राधिकारी का सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्रत्येक ज्ञात निर्यातक या उत्पादक के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने का दायित्व होता है। वर्तमान जाँच के दौरान सूचना प्रदान करने के संबंध में खिमप्राम की ओर से कोई गलती नहीं है। समस्त सूचना जो खिमप्राम के पास और खिमप्राम के लिए उपलब्ध है, को प्राधिकारी को उपलब्ध कराया गया है। खिमप्राम और उसके असंबंधित व्यापारी के बीच संबंध की प्रकृति के कारण खिमप्राम के पास पूरी मूल्य श्रृंखला संबंधी कोई सूचना नहीं है।

xxx. उक्त पर विचार करते हुए, खिमप्राम प्राधिकारी से खिमप्राम की आपत्तियों का पूरा आकलन करने, उसके तथ्यों के आधार पर उसकी जाँच करने और रूसी परिस्थिति के संबंध में जाँच को समाप्त करने का अनुरोध करता है।

18. मौखिक सुनवाई के बाद की घरेलू उद्योग की टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:

- i. इस समय संबद्ध देशों से काफी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है जिससे पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। अन्य देशों पर पाटनरोधी शुल्क लागू होने से संबद्ध देशों से आयात में 2014-15 में 65 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इसके अलावा, ये आयात काफी पाटित कीमतों पर हुए हैं।
- ii. एक मामले में जहाँ अन्य स्रोतों से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद नए स्रोतों से पाटन शुरू हो गया, वहाँ यह सर्वाधिक तर्कसंगत है कि घरेलू उद्योग की स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। इसी विनियम विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हैं कि यदि कोई उद्योग पूर्ववर्ती पाटन के प्रभाव से उभर रहा हो तो उसे भी क्षति का कारक माना जाएगा। इस प्रकार यह तथ्य कि घरेलू उद्योग सुधार कर रहा है वास्तव में घरेलू उद्योग पर पाटन के प्रभाव को दर्शाता है।
- iii. केवल आधार वर्ष और पीओआई और पूर्ववर्ती वर्ष से ही नहीं प्रवृत्तियों का विश्लेषण सभी चार वर्षों के लिए किया गया है। पाटनरोधी जाँच का उद्देश्य क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। पीओआई को 'क्षतिकारी' के रूप में वर्णित किया जा सकता है, यही अवधि है जिसके लिए पाटन की मौजूदगी की जाँच पूर्ववर्ती कार्यनिष्पादन के संदर्भ में की जाती है।
- iv. सामान्य मूल्य का निर्धारण इस कारण से बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर नहीं किया जा सकता है कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ता बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में किसी उत्पादक से ऐसी सूचना प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा है। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने भारत में उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के लिए समायोजित करके, उसके आधार पर और याचिकाकर्ता के खपत मानकों पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
- v. रूस के घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमत के साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। प्रकाशित स्रोतों से कीमत के कोई साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास भी किए गए थे। तथापि, याचिकाकर्ता इस कारण से रूस के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमतों का कोई साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं कि संगतसूचना सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और इसलिए उन्होंने सामान्य मूल्य का परिकलन किया है।
- vi. खुले/अनपैकड और पैकड सामग्री की लागत और कीमतों में भारी अंतर को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।
- vii. इन प्रतिवादियों से इतनी देर से प्राप्त उत्तर को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। पाटनरोधी करार में जाँचकर्ता प्राधिकारी के लिए हितबद्ध पक्षों को उनके हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना अपेक्षित है। तथापि, चूंकि यह जाँच समयबद्ध जाँच होती है, इसलिए ये अवसर केवल तभी उपलब्ध होते हैं जब इनका लाभ समय पर उठाया जाए।

- viii. प्राधिकारी प्रश्नावली के उत्तर को भी अस्वीकार कर सकते हैं यदि उसे विहित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है जैसा कि सेरामिक टाइल्स के मामले में किया गया है।
- ix. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर कानून के अंतर्गत निर्धारित मानकों की बिल्कुल अनदेखी करते हैं। ये उत्तर सूचना की दृष्टि से अपर्याप्त और अधूरे होने के अलावा प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए प्रपत्र को भी पूरा नहीं करते हैं।
- x. घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री और भारत को निर्यात, सभी प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों की सूची, संस्थापित क्षमता संबंधी सूचना, उत्पादन, स्टॉक और बिक्री आदि जैसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। इस प्रकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया निर्यातक के उत्तर को असहयोगी मान सकते हैं और उन्हें अलग व्यवहार देने से इनकार करते हुए असहयोगी घोषित कर सकते हैं।
- xi. याचिकाकर्ता ने भारित औसत पाटनमार्जिन निर्धारित किया है जो न्यूनतम सीमा से अधिक है और काफी अधिक है।
- xii. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में 2012-13 में गिरावट आई और उसके बाद लगातार वृद्धि हुई है।
- xiii. भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में 2012-13 में गिरावट आई है और उसके बाद उनमें लगातार वृद्धि हुई है।
- xiv. संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में 2012-13 में गिरावट आई है और उसके बाद निरंतर वृद्धि हुई है और पीओआई में यह काफी अधिक है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती वर्ष से पीओआई में मामूली वृद्धि हुई है और पहले से पाटनरोधी शुल्क लागू वाले देशों के बाजार हिस्से में कमी आई है।
- xv. आयातित वस्तुएं खुले और पैकड दोनों रूपों में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती करते रहे हैं। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कीमत कटौती समग्र रूप से संबद्ध देशों से सकारात्मक रही है।
- xvi. पैकड रूप में आयातों की पंहुच कीमत 2012-13 से बिक्री लागत और बिक्री कीमत के स्तर से काफी कम रही है। खुले रूप में आयातों की पंहुच कीमत 2012-13 में लागत और बिक्री कीमत से कम रही थी और पीओआई में वह लगभग लागत के स्तर पर रही है। संबद्ध देशों से देश में अधिकांश आयात पैकड रूप में हैं जिससे घरेलू बाजार में काफी कीमत ह्रास हो रहा है।
- xvii. 2012-13 संबद्ध आयातों में कमी आई है और उसके बाद वृद्धि हुई है। आयात भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में काफी अधिक रहे हैं।
- xviii. पाटित आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं जिससे वित्तीय घाटा हो रहा है।
- xix. घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभों में काफी मात्रा में तेजी से गिरावट आई है।
- xx. यद्यपि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से के अनुसार सुधार हुआ है, परंतु वह घरेलू उद्योग के उत्पादन जारी रखने के निर्णय और देश में विचाराधीन उत्पाद के लिए भारी मांग के कारण हुआ है। किसी मामले में, इन मापदंडों में सुधार के बावजूद लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ में बुरी तरह से गिरावट आई है जबकि मात्रा मापदंडों में सुधार के परिणामस्वरूप उनमें सुधार होना चाहिए था।
- xxi. आयात कीमतें घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के स्तर से काफी कम रही हैं।
- xxii. भारी कीमत अंतर के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में लाभ, नकद लाभ (नकद प्रवाह) और निवेश पर आय की दृष्टि से विकृति आई है। इस प्रकार घरेलू उद्योग का खराब कार्यनिष्पादन देश में उत्पाद के पाटन का परिणाम है।

- xxiii. लाभ,नकद प्रवाह, नियोजित पूंजी पर आय में विकृति पाटित आयातों के कारण हुई है।
- xxiv. कीमत मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक हो गई है।
- xxv. उन देशों जिनपर पाटनरोधी शुल्क लागू है, से आयातों में कमी आई है जबकि संबद्ध देशों से आयातों में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है।
- xxvi. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन काफी धनात्मक है जो दर्शाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- xxvii. घरेलू उद्योग ने कीमत क्षति और न कि मात्रात्मक क्षति का दावा किया है। याचिकाकर्ता उस समय तक उत्पाद को बेच सकते हैं जब तक याचिकाकर्ता आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर पुनः समान करते हैं। इसके अलावा, आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों को बराबर करना घरेलू उद्योग की मजबूरी है।
- xxviii. मात्रा संबंधी मापदंड घरेलू उद्योग के नियंत्रण में है और घरेलू उद्योग अपनी ओर से सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने और बेचने का सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है ताकि उसकी स्थिर लागतें बड़े पैमाने पर उत्पादन से पूरी हो सकें। तथापि, उत्पाद की बिक्री कीमत घरेलू उद्योग के नियंत्रण से बाहर है और वह सीधे आयातों पर निर्भर करती है।
- xxix. घरेलू उद्योग ने भारित औसत आधार पर कीमत कटौती का परिकलन किया है। याचिकाकर्ताओं ने मासिक आधार पर तुलना पर विचार करते हुए कीमत कटौती निर्धारित की है जो स्पष्ट रूप से चीन के आयातों द्वारा सकारात्मक कीमत कटौती दर्शाती है। आयातित वस्तुएं खुले और पैकड दोनों रूपों में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती करती रही हैं। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कीमत कटौती समग्र रूप से संबद्ध देशों से सकारात्मक रही है।
- xxx. ईयू के कानून में 'इस तथ्य कि घरेलू उद्योग पाटन के पूर्ववर्ती बुरे प्रभावों से उबरने की प्रक्रिया में घरेलू उद्योग' को क्षति दर्शाने वाला एक मापदंड विशेष रूप से माना गया है, डब्ल्यूटीओ करार में यह माना गया है कि सूची विस्तृत नहीं है और भारतीय नियमों में एक समावेशी परिभाषा है जिसमें कुछ अन्य दशाओं की मौजूदगी निहित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पाटन के पूर्ववर्ती प्रभावों से आंशिक सुधार का अर्थ यह नहीं है कि घरेलू उद्योग को अब क्षति नहीं हो रही है।
- xxxi. किसी उद्योग के आरंभिक और अंतिम स्टॉक की सूचना गोपनीय होती है। यह दलील दी गई है कि प्राधिकारी औसत आधार पर मालसूची का परिकलन करें। याचिकाकर्ताओं ने घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रतिकूल कीमत प्रभाव का दावा किया है।

मौखिक सुनवाई के बाद घरेलू उद्योग और प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों की टिप्पणियों की प्राधिकारी द्वारा जाँच

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों द्वारा सार्वजनिक सुनवाई के बाद किए गए अधिकांश अनुरोध दोहराई गई प्रवृत्ति के हैं और उनपर पहले ही प्रारंभिक जाँच परिणाम अधिसूचना में विचार किया गया है। तथापि, घरेलू उद्योग और प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों द्वारा मौखिक सुनवाई के बाद की संगत टिप्पणियों की प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार जाँच की गई है:-
 - i. हितबद्ध पक्षों ने यह दलील दी है कि प्राधिकारी को इस आधार पर उत्पादक के प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार नहीं करना चाहिए था कि भारत को निर्यातों की पूरी सूचना उपलब्ध नहीं थी। हितबद्ध पक्षों ने इस बात पर जोर दिया है कि कानून के अंतर्गत अपेक्षा आवश्यक सूचना की और जो उत्पादकों के पास तर्कसंगत रूप से उपलब्ध हो, की है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी उस कीमत पर विचार कर सकते हैं जिस पर वस्तुओं को असंबंधित निर्यातकों के लिए ऐसे उत्पादकों द्वारा बिल किया गया है। मानकों के संबंध में डब्ल्यूटीओ के निर्णय का हवाला भी दिया गया कि प्राधिकारी को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के हितबद्ध पक्षों के दायित्वों को निर्धारित करना चाहिए। कुछ हितबद्ध पक्षों ने प्रारंभिक जाँचपरिणामों के जारी होने के बाद भारत को अपने निर्यातों को भारतीय सीमाशुल्क के आकड़ों से सहसंबंधित किया है और यह बताया है कि उनसे सिद्ध होता है कि निर्यात कीमत के संबंध में उनके दावे विश्वसनीय हैं। प्राधिकारी इस संबंध में नोट करते हैं कि कानून के अंतर्गत पाटन का मार्जिन सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच का अंतर होता है। अतः पाटन

मार्जिन के सही निर्धारण के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत दोनों को सही ढंग से निर्धारित करना अपेक्षित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात कीमत को तब तक सही ढंग से और पर्याप्त रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है जब तक उस कंपनी जिसमें भारत को वस्तुओं के बीजक बनाए हैं, का प्रश्नावली का उत्तर रिकार्ड में न हो और ऐसी कंपनी प्राधिकारी से सहयोग न करे। स्वीकृत रूप से, भारत को निर्यातों के सभी संबद्ध खर्चे ऐसे मामलों में ऐसे उत्पादकों द्वारा उठाए जाते हैं जिनमें निर्यातक वस्तुओं के बीजक बनाने में शामिल रहा हो। स्वीकृत रूप से, भारत को निर्यातों के सभी संबद्ध व्ययों को ऐसे मामलों में जिनमें निर्यातक वस्तुओं के बीजक बनाने में शामिल रहा हो, पर हुए व्ययों को ऐसे उत्पादकों ने नहीं उठाया है। भारत को निर्यातों के लिए कुछ व्ययों को ऐसे निर्यातकों द्वारा वहन किया गया है। इसके अलावा, वह कीमत जिस पर उत्पादक ऐसे मामलों में निर्यातक को बिक्री करता है वह कीमत नहीं होती जिस पर वस्तुओं को भारत को निर्यात के लिए बेचा गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटन तब होता है जब कोई वस्तु भारत के व्यापार में ऐसी कीमत पर लाई जाती है जो उसके सामान्य मूल्य से कम हो। अतः वह कीमत जिस पर वस्तुएं भारतीय उपभोक्ता/आयातक को बीजकीकृत की गई हैं निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह से अब यह कि प्रश्नावली के उत्तर उन निर्यातकों द्वारा दिया गया है जिन्होंने चीन के मूल के विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति की है, इस लिए प्राधिकारीने चीन के सभी उत्पादकों के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित किया है। जहां तक खिमप्राम का संबंध है, प्राधिकारी दोहराते हैं कि खिमप्राम को अवसर दिए जाने के बावजूद कंपनी ने उक्त निर्यातकों/व्यापारियों का यह दावा करते हुए कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया कि खिमप्राम के पास और खिमप्राम के लिए उपलब्ध समस्त सूचना प्राधिकारी को दे दी गई है और खिमप्राम के पास खिमप्राम और उसके असंबंधित व्यापारी के बीच संबंधों की प्रकृति के कारण पूरी मूल्य श्रृंखला संबंधी सूचना नहीं है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि खिमप्राम द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के 100% का उक्त उल्लिखित निर्यातकों द्वारा भारतको निर्यात कर दिया गया है इसलिए खिमप्राम इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि उसका उनके साथ कोई संबंध नहीं है और वह उन कंपनियों से पूरी मूल्य श्रृंखला संबंधी सूचना प्रस्तुत नहीं कर सकता है जैसा कि इस जाँच में अन्य सहयोगी चीनी उत्पादकों द्वारा किया गया है। पूरी मूल्य श्रृंखला के अभाव में प्राधिकारी खिमप्राम के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं करने का प्रस्ताव करते हैं।

- ii. आईबीआईएस आयातों की तुलना में डीजीसीआई एंड एस के आकड़ा बेस में कम आयातों के कारण/स्पष्टीकरण के संबंध में और इसके अलावा यह कि घरेलू उद्योग ने याचिका के लिए दो अलग-अलग स्रोतों से आयात आकड़ों को अपनाया है, प्राधिकारी दोहराते हैं कि जाँच शुरूआत के स्तर पर प्राधिकारी के लिए इस बात से स्वयं को संतुष्ट करना अपेक्षित है कि जाँच की शुरूआत को सही ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं और घरेलू उद्योग ने डीजीसीआई एंड एस के आकड़ों का उस अवधि तक के लिए प्रयोग किया है जिसके लिए उस स्तर पर उनके पास वह उपलब्ध थे। तथापि, इस समय डीजीसीआईएंडएस के सौदावार आकड़े उपलब्ध हो गये और प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस के सौदावार आकड़ों को प्राप्त कर लिया और वर्तमान निर्धारण के लिए विश्लेषण डीजीसीआई एंड एस के आकड़ों से किया गया है। जाँच शुरूआत के समय दो स्रोतों को अपनाने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जाँच शुरूआत के समय सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना को अपनाने को न्यायोचित सिद्ध किया है। पूरी अवधि के लिए सूचना जाँच शुरूआत के समय डीजीसीआई एंड एस द्वारा उपलब्ध कराई गई और इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा उसके बाद की अवधि के लिए द्वितीयक स्रोतों से आकड़े अपनाना न्यायोचित है। तथापि, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस के सौदावार आकड़ों को प्राप्त किया और प्रारंभिक जाँच परिणामों और वर्तमान निर्धारण के प्रयोजनार्थ विश्लेषण डीजीसीआई एंड एस के आकड़ों के आधार पर किया गया है।
- iii. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त डीजीसीआई एंड एस के आकड़े हितबद्ध पक्षों को उपलब्ध नहीं कराये गये थे, प्राधिकारीनोअ करते हैं कि उन्हें सार्वजनिक फाइल में रखा गया था और इस प्रकार उन्हें सत्यापन के लिए सभी हितबद्ध पक्षों को उपलब्ध कराया गया था।
- iv. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर किये गये आवेदन में कमियां हैं क्योंकि उसमें कानून के अंतर्गत साक्ष्य और सूचना नहीं है और प्राधिकारी तब तक पाटनरोधी जाँच की शुरूआत नहीं कर सकते हैं जब तक कि

(क) वह यह निर्धारित करें कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है और (ख) वह आवेदन में प्रदत्त साक्ष्य की सत्यता और पर्याप्तता की जाँच नहीं करें और स्वयं को संतुष्ट न कर लें कि पाटन, क्षति और जाँच शुरुआत को सही ठहराने के लिए कारणात्मक संबंध मौजूद है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने जाँच की शुरुआत पाटन और क्षति और उनके कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्यों से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ही की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच के वर्तमान स्तर पर भी प्राधिकारी पाते हैं कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में पाटन मार्जिन काफी अधिक है और पाटन आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

- v. जहां तक घरेलू उद्योग और प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों के इस तर्क का संबंध है कि काफी सूचना कोई विधिसम्मत कारण बताये बिना और नियमावली और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विस्तृत प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए गोपनीय रखी गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को जहां आवश्यक हो स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और उसका किसी अन्य हितबद्ध पक्ष को प्रकटन नहीं किया गया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश को सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध किसी सूचना को गोपनीय नहीं माना जा सकता है।
- vi. इस तर्क के संबंध में कि आवेदन के लिए आयात आकड़ों का प्रयोग दो अलग-अलग स्रोतों से किया गया है अर्थात् अप्रैल 2011 से मार्च 2012 की अवधि के लिए डीजीसीआईएंडएस आयात आकड़े और अप्रैल 12 - मार्च 13, अप्रैल 13 -मार्च 14 और अप्रैल 14 से जून 14 की अवधियों के लिए टिप्स साफ्टवेयर सर्विसेज प्रा. लि. से आयात आकड़े, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने डीजीसीआईएस के सौदा वार आकड़ों को प्राप्त किया है और वर्तमान निर्धारण के प्रयोजनार्थ विश्लेषण डीजीसीआईएस आकड़ों के आधार पर किया गया है।
- vii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि अन्य देशों से भारी और काफी आयात हुए हैं जो जाँच अवधि में 77 प्रतिशत के उच्च स्तर पर हैं और यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति अन्य देशों से आयातों और न कि वर्तमान जाँच में संबद्ध देशों से आयातों के कारण हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों में जाँच अवधि में वास्तव में वृद्धि हुई है और यह आयात काफी पाटन कीमतों पर किये गए हैं। रूस के निर्यातक के इस तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस से आयात की मात्रा नियमों के अंतर्गत नगण्य सीमाओं से अधिक रही है।
- viii. इस तर्क के संबंध में कि भारत में हुए अधिकांश आयात शुल्क मुक्त स्कीमों के अंतर्गत किये गये हैं जो पाटनरोधी शुल्क के अधीन नहीं हैं और जब शुल्क मुक्त स्कीमों के अंतर्गत आयात भारतीय बाजार में प्रवेश नहीं करते हैं तो उन्हें पाटनरोधी जाँच के अधीन भी नहीं माना और नहीं रखा जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत किए गए आयात प्रतिस्पर्धा सृजित करते हैं और कीमत क्रम को बदलते हैं क्योंकि आयातक विदेशी निर्यातक या घरेलू उत्पादक जो भी उसे प्रतिस्पर्धी कीमत देता है से वस्तुओं को खरीदता है। अतः शुल्क मुक्त स्कीमों के अंतर्गत किए गए आयातों को बाजार में कीमतों को प्रभावित नहीं किया हुआ नहीं माना जा सकता है और इसलिए आयात निर्धारित करते समय उन्हें बाहर नहीं रखा जा सकता है।
- ix. इस तर्क के संबंध में कि चीन के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में प्राधिकारी को सर्वप्रथम सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की पहचान करनी होगी केवल तभी जहां ऐसे तीसरे देश, किसी अन्य तर्कसंगत आधार से आवश्यक आकड़े प्राप्त करना संभव नहीं हो, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य इस कारण से बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर नहीं निर्धारित किया जा सकता है कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, चीन जन. गण. से किसी प्रतिवादी उत्पादक ने न तो बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का दावा किया है और न ही गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता का खंडन ही किया है। ऐसी स्थिति में, जहां किसी भी चीन की कंपनी ने

बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का दावा नहीं किया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस दावे में कोई तथ्य नहीं दिखता है कि प्राधिकारी को सबसे पहले चीन के इन उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करना चाहिए।

- x. इस तर्क के संबंध में कि क्षति संबंधी विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण वर्ष 2012-13 से किया गया है परंतु आधार वर्ष 2011-12 से नहीं किया गया है और क्षति जाँच अवधि के दौरान क्षति संबंधी मापदंडों का विश्लेषण आरंभिक बिन्दु से अंतिम बिन्दु तक किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने केवल आधार वर्ष से और पीओआई से और पूर्ववर्ती वर्ष से नहीं अपितु सभी चार वर्षों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है
- xi. इस तर्क के संबंध में कि दोनों संबद्ध देशों के लिए प्रपत्र IVक और प्रपत्र IVख में प्रदत्त घरेलू बिक्री कीमत के ब्योरे, चीन के लिए प्रपत्र IVख और रूस के लिए प्रपत्र IVख भिन्न-भिन्न हैं और इसके अलावा रूस के लिए कीमत कटौती चीन के लिए कीमत कटौती की तुलना में अधिक दर्शाई गई है जबकि चीन के लिए पहुंच मूल्य रूस के पहुंच मूल्य से अधिक है जो दर्शाता है कि वर्तमान मामले में कीमत कटौती को कृत्रिम रूप से सृजित किया गया जबकि वह मौजूद नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने आवेदन के प्रपत्र IVख में दोनों देशों के लिए पहुंच मूल्य के साथ बिक्री कीमत की तुलना मासिक आधार पर अलग-अलग की है, जबकि प्रपत्र IVक में पीओआई अवधि के लिए घरेलू उद्योग की भारित औसत बिक्री कीमत को लिया गया है। अतः ये दोनों एक जैसी हो सकती हैं। तथापि प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी करते हुए प्राधिकारी ने पीओआई के लिए भारित औसत बिक्री कीमत पर विचार किया है। रूस और चीन के बीच अलग-अलग मात्रा में कीमत कटौती के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि भिन्न देशों से कीमत कटौती का अलग-अलग स्तर का यह अर्थ नहीं है कि कम कीमत कटौती वाले देश से क्षति नहीं हुई है।
- xii. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को उसके आवेदन में क्षति संबंधी सूचना और प्रारंभिक जाँच परिणामों में दी गई क्षति संबंधी सूचना के आधार पर क्षति नहीं हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के मात्रा और कीमत प्रभावों और घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव की जाँच करने के बाद, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों में 2012-13 में गिरावट आई और उसके बाद उनमें समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में काफी वृद्धि हो गई। घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है। तथापि, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण कीमत प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती हो रही है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को पीओआई में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण कम कीमत पर बिक्री भी झेलनी पड़ी है। लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर आय ऋणात्मक बने हुए हैं। अन्य देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बावजूद, घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण पीओआई में घाटा हुआ है। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में यह निष्कर्ष है कि यद्यपि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्से के संबंध में सुधार हुआ है, तथापि लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह की दृष्टि से निष्पादन खराब हुआ है। इस प्रकार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- xiii. पीजेएससी खिमग्राम के इस तर्क के संबंध में कि रूस संघ के विरुद्ध आवेदन को डब्ल्यूटीओ करार के अनुसार समाप्त कर दिया जाएगा और वर्तमान जाँच में जाँच अवधि के दौरान भारत में उत्पाद के कुल आयात और रूस से आयात की राशि से संबंधित आकड़े यह दर्शाते हैं कि पीओआई से पहले प्रत्येक पहले वर्ष और पीओआई में भी रूस से आयातों की मात्रा कुल आयातों की मात्रा के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है और इसके अलावा इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि रूस से संभावित आयात भी 3 प्रतिशत से अधिक हो जाएंगे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच की शुरुआत के समय रूस के आयातों का हिस्सा 3.40% था। प्राधिकारी ने अब वर्तमान जाँच के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ डीजीसीआईएंडएस के सौदावार आकड़ों को अपनाया है और यह नोट किया जाता है कि रूस से आयातों का हिस्सा न्यूनतम सीमा से अधिक (4.44%) है।

- xiv. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने बल्क और पैकड उत्पाद के लिए अलग से विश्लेषण का दावा किया है परंतु प्रदत्त आयात आकड़ों की पीडीएफ प्रति से लक्सी आवेदन के भाग के रूप से इस प्रकार प्रदत्त आयात आकड़ों की हार्ड प्रति से इस पहलू की पहचान नहीं कर सकता है और इसके अलावा आयात आकड़ों के विश्लेषण के बाद, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा अम.डा. और भारतीय रुपये दोनों के मूल्यों को उन्हें मिश्रित करके माना गया है जिससे आयात कीमतों का और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति का गलत और गुमराह करने वाला विश्लेषण होगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तर्क घरेलू उद्योग द्वारा अपनाये गये द्वितीयक आयात आकड़ों से संबंधित है जबकि प्राधिकारी ने प्रारंभिक जाँच परिणाम डीजीसीआईएंडएस के आयात आकड़ों के आधार पर जारी किए हैं न कि याचिका में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त द्वितीयक आकड़ों से। अम.डा. और भारतीय रुपये में सूचित आयातों के संभावित मिश्रण के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने माप की केवल एक इकाई में आकड़ों पर विचार किया है। निर्यातक के आकड़े अम.डा. में हैं और उन्हें ही स्वीकार किया गया है, जबकि भारतीय आकड़े रुपये में हैं और उन पर विचार किया गया है। न तो प्रारंभिक जाँच परिणाम और न ही वर्तमान अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना में आकड़ों का कोई मिश्रण नहीं हुआ है।
- xv. इस तर्क के संबंध में कि खिमप्राम के ड्रम सौदो के रूप में रिकार्ड किए गए के संबंध में आयात की मात्रा के आकड़ों में कुछ विशिष्ट विरोधाभास हैं इसका कारण है कि तकनीकी कारण से उसका भार हमेशा 0.27 मी.टन की गुणज होगा परंतु आवेदन में अनेक ऐसे सौदे हैं (डीजीसीआईएंडएस और टिप्स साफ्टवेयर सर्विसेज प्रा. लि. के डाटाबेस से) जिनका भार 0.27 मी.टन का गुणज नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने डीजीसीआईएंडएस के सौदा-वार आकड़ों जैसे उपलब्ध कराये गये थे, पर भरोसा किया है।

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

चीन जन.गण. के सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा (एमईटी) का परीक्षण

20. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्य देशों द्वारा की गई पाटनरोधी जांचों में चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। इसलिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) में उल्लिखित निर्बंधनों के अनुसार चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ नियमावली में उल्लिखित निर्बंधनों के अनुसार निर्यातक देश अथवा अलग-अलग निर्यातकों द्वारा इस प्रकल्पना के खंडन के अध्यधीन माना जा सकता है।

21. यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1, पैरा 8 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रकल्पना का खंड किया जा सकता है कि यदि चीन जन.गण. के निर्यातक पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में यथाविनिर्धारित मापदंड के आधार पर सूचना एवं पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करते हैं और इसके विपरीत सिद्ध करते हैं। चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के सहयोगकर्ता निर्यातकों/उत्पादकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में यथा-उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराएं जिससे कि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर विचार करने में सक्षम हो सकें :

- (i) चीन जन.गण. में कच्चे माल, प्रविधि एवं श्रम की लागत, आउटपुट, बिक्री सहित कीमत, लागत और अंतर्निविष्टियों के संबंध में संबंधित फर्मों का निर्णय और निवेश बाजार संकेतकों के प्रत्युत्तर में किए जाते हैं जिनसे मांग एवं आपूर्ति प्रदर्शित होती है और इस संबंध में देश की सरकार द्वारा कोई खास हस्तक्षेप नहीं किया जाता है और क्या प्रमुख अंतर्निविष्टियों की लागत बाजार मूल्यों को पर्याप्ततः प्रदर्शित करती है;
- (ii) इन फार्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली द्वारा की गई भारी विकृतियों, खासकर, आस्तियों का मूल्यहास, बट्टे-खाते में डाले गए अन्य, विनिमय व्यापार और ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए भुगतान, के अध्यधीन होती है।
- (iii) यह फर्में दिवालियापन एवं संपत्ति विधियों के अध्यधीन होती हैं जो इन फार्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी प्रदान करती हैं।
- (iv) विनिमय दर संपरिवर्तन बाजार दरों पर किया जाता है।

22. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां उन्हें यह सुझाव देते हुए प्रेषित कीं कि वे विहित स्वरूप एवं ढंग से सूचना प्रदान कराएं। तथापि, चीन जन.गण. के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों को छोड़कर चीन जन.गण. के अन्य किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने अपना प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करके इस जांच में सहयोग नहीं किया है। निम्नलिखित कंपनियों ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है :

- (i) शांडांग लिआचेंग लुक्सी सिक्स्थ कैमिकल फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
- (ii) लुक्सी कैमिकल (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड, हांगकांग (निर्यातक)
- (iii) शांडांग डोंग्युई फ्लुओ-सिलिकरन मटीरियल्स कंपनी लिमिटेड चीन जन.गण.
- (iv) निंगबो जुहुआ कैमिकल एंड साइंस कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
- (v) झेजियांग क्युहना फ्लोर कैमिस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
- (vi) फार्मासिनो होल्डिंग (एचके) लिमिटेड, हांगकांग (निर्यातक)
- (vii) एच के मोन्टेज इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड हांगकांग (निर्यातक)।
- (viii) ट्रिक्ॉन एनर्जी लि., यूएसए
- (ix) ट्रिक्ॉन ड्राई कैमिकल्स एलएलसी, यूएसए

23. यह नोट किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित किसी भी उत्पादक ने न तो बाजार अर्थव्यवस्था का दावा किया है और न ही गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की प्रकल्पना का खंडन किया है। चूंकि चीन की किसी भी कंपनी ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा नहीं किया है इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह निर्धारित नहीं किया है कि क्या चीन के किसी भी उत्पादक को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जा सकता है।

चीन के लिए सामान्य मूल्य

24. चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक और निर्यातक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है इसलिए प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के आधार पर किया है।

25. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 का पैरा 7 निम्नलिखित उल्लेख करता है :

“गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण तृतीय देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर अथवा उक्त तृतीय देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत, जहां यह संभव नहीं है, अथवा किसी अन्य उत्तरदायी आधार पर, जिनमें समान उत्पाद के लिए भारत में देय या वास्तविक रूप से प्रदत्त कीमत शामिल हो, जिसमें तर्कसंगत लाभ मार्जिन को भी शामिल किया जाए, के आधार पर किया जाएगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सम्बद्ध देश के विकास एवं प्रश्नाधीन उत्पाद के स्तर को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत ढंग से एक समुचित तृतीय देश बाजार अर्थव्यवस्था का चयन किया जाएगा और इस चयन के समय यदि कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराई जाती है तो उस पर भी समुचित ध्यान दिया जाएगा। जहां उपयुक्त हुआ लेखाओं को समान मामले में किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के सम्बंध में की गई जांच के अनुरूप लिया जाएगा। किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के उपर्युक्त चयन के बारे में जांच के पक्षकारों को बिना किसी अतर्कसंगत विलम्ब के तत्काल सूचना दी जाएगी और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त समयावधि प्रदान की जाएगी।

26. इन नियमों के अनुसार चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित में से किसी भी एक आधार पर किया जा सकता है :

- क. किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में कीमतों के आधार पर, अथवा
- ख. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में विनिर्मित मूल्य के आधार पर, अथवा
- ग. इन तृतीय देशों से अन्य देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, को कीमत के आधार पर, अथवा

घ. यदि उपर्युक्त विकल्पों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी अन्य युक्तियुक्त आधार पर कर सकते हैं जिनमें तर्कसंगत लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत सामयोजित भारत में समान उत्पाद के लिए देय अथवा वास्तविक रूप से संदत्त कीमत शामिल होगी।

27. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि तृतीय देश की कीमत और लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए तृतीय देश की निर्यात बिक्रियों तथा उत्पादन लागत एवं घरेलू बिक्रियों के व्यापक सौदेवार आंकड़े और तृतीय देश में इन उत्पादकों का सहयोग अपेक्षित होता है, जो इस जांच में प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, इन बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देशों में प्रचलित कीमत और लागत के संबंध में इस तरह सत्यापन योग्य सूचना न तो आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई है और न ही प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा, न ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना तक पहुंच बनाई जा सकती है, तथा न ही चीन की प्रतिवादी कंपनियों ने समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश के संबंध में कोई दावा प्रस्तुत किया है।

28. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चीन जन.गण. इस संबद्ध वस्तु के किसी भी निर्यातक/उत्पादक से कोई भी एमईटी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और इसके अतिरिक्त, यह नोट करते हुए कि चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश के संबंध में कोई सूचना/आंकड़े रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है; इसलिए प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य पर विचार पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के द्वितीय परंतुक में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप उपलब्ध "तर्कसंगत तथ्यों के आधार पर" किया है। तदनुसार प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य एवसं प्रशासनिक व्ययों को शामिल करते हुए, विधिवत समायोजन करके किया है। पैकिंग लागत में भारी अंतर के मद्देनजर इस उत्पाद के खुले में और पैकिंग में दोनों रूपों के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। चीन जन.गण. के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य को अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

रूस के लिए सामान्य मूल्य

29. प्राधिकारी ने रूस के ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां प्रेषित कीं। प्राधिकारी को केवल खिमप्रोम पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रूस से ही प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है। इस वस्तु की बिक्री अवेस्ट्रा कैमिकल डीएमसीसी, यूएई; क्वेस्ट ग्रुप डीएमसीसी यूएई; ट्रिगान गल्फ, एफजेडसीओ, यूएई; क्वेस्ट प्वाइंट एलएलपी, यूके और क्वेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग एसए, कनाडा नामक इसके असंबद्ध निर्यातकों/व्यापारियों द्वारा भारत में इसके ग्राहकों को की गई। इस कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान *** एमटी एमडीसी की बिक्री की है। प्रश्नावली प्रत्युत्तर से यह देखा गया कि अवेस्ट्रा कैमिकल डीएमसीसी, यूएई; क्वेस्ट ग्रुप डीएमसीसी यूएई; ट्रिगान गल्फ, एफजेडसीओ, यूएई; क्वेस्ट प्वाइंट एलएलपी, यूके और क्वेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग एसए, कनाडा ने खिमप्रोम पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, रूस उत्पादक की भारत को इस संबद्ध वस्तु के कुल निर्यातों में से *** प्रतिशत निर्यात करने के बावजूद प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। चूंकि मूल्य श्रृंखला पूरी नहीं था, इसलिए प्राधिकारी इस अनन्तिम जांच परिणाम के स्तर पर खिमप्रोम पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, रूस के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया था।

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि खिमप्राम को अवसर दिए जाने के बावजूद कंपनी ने यह दावा करते हुए ऊपर उल्लिखित निर्यातों/व्यापारियों का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है कि समस्त सूचना जो खिमप्राम के पास और खिमप्राम के लिए उपलब्ध है, को प्राधिकारी को उपलब्ध कराया गया है और यह कि खिमप्राम और उसके असंबंधित व्यापारी के बीच संबंध की प्रकृति के कारण खिमप्राम के पास पूरी मूल्य श्रृंखला संबंधी कोई सूचना नहीं है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि खिमप्राम द्वारा उत्पादित 100 प्रतिशत वस्तुएं उक्त उल्लिखित निर्यातकों द्वारा भारत को निर्यात की गई हैं, इसलिए खिमप्राम यह दावा नहीं कर सकता है कि उसका उनके साथ कोई संबंध नहीं है और वह उन कंपनियों से पूरीमूल्य श्रृंखला के लिए उत्तर प्रस्तुत करने को नहीं कह सकता है जैसाकि इस जांच में अन्य सहयोगी चीनी उत्पादकों द्वारा किया गया है। पूर्ण मूल्य श्रृंखला के अभाव में प्राधिकारी रूस के लिए समग्र रूप से भारत में उत्पादन लागत जिसे नियम 6(8) के अंतर्गत बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों को शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है, के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। पैकिंग लागत में भारी अंतर को देखते हुए उत्पाद के खुले और पैकड रूप के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। रूस के लिए परिकल्पित औसत सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत

लु क्सी कैमिकल (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड, हांगकांग (निर्यातक) के जरिए शांडांग लिआओचेंग लुक्सी सिक्स्थ कैमिकल फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. (उत्पादक) के लिए निर्यात कीमत

31. शांडांग लिआओचेंग लुक्सी सिक्स्थ कैमिकल फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत को इस संबद्ध वस्तु की बिक्री की सूचना दी है। इस वस्तु की बिक्री इसके संबद्ध निर्यातक लु क्सी कैमिकल (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड, हांगकांग के साथ-साथ इसके असंबद्ध निर्यातक ट्रिकान एनर्जी, यूएसए; विन्यार इंटरनेशनल लिमिटेड यूएसए और कास्मास वीयू लिमिटेड हांगकांग के जरिए भारत में इसके उपभोक्ताओं को की है। इस कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान *** एमटी एमडीसीस का भारत को निर्यात किया है। इसके प्रश्नावली प्रत्युत्तर से यह देखा गया कि ट्रिकान एनर्जी, यूएसए; विन्यार इंटरनेशनल लिमिटेड यूएसए और कास्मास वीयू लिमिटेड हांगकांग ने उत्पादक शांडांग लिआओचेंग लुक्सी सिक्स्थ कैमिकल फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड की इस संबद्ध वस्तु की भारत को किए गए कुल निर्यातों में से *** प्रतिशत का निर्यात करने के बावजूद प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। चूंकि मूल्य श्रृंखला पूरी नहीं किया, इसलिए प्राधिकारी अनन्तिम जांच परिणाम के स्तर पर सहयोगकर्ता उत्पादक/निर्यातक शांडांग लिआओचेंग लुक्सी सिक्स्थ कैमिकल फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड के संपूर्ण प्रत्युत्तर को नामंजूर किया। तथापि, अनन्तिम जांच परिणाम के बाद, ट्रिकान एनर्जी, यूएसए, विनमार इंटरनेशनल लि., यूएसए, कोसमोस वीयू लि. हांगकांग ने अपने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं और मूल्य श्रृंखला को पूरा किया है। चूंकि मूल्य श्रृंखला पूरी हो गई है, इसलिए प्राधिकारी शानडोंग लिआओचेंग लुक्सी सिक्स्थ कैमिकल फर्टिलाइजर कं. लि. की निर्यात कीमत इस प्रकार प्रस्तुत आकड़ों के आधार पर निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। उत्पादक ने कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए विदेशी परिवहन, अंतर्देशीय परिवहन, बैंक प्रभार, बीमा, कमीशन, ऋण लागत और वैट के लिए समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने इनकी अनुमति दी है। इस प्रकार निर्धारित औसत कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

शांडांग डोंग्यूइ फ्लुओ सिलिकन मटीरियल्स कंपनी लिमिटेड, चीन (उत्पादक) के लिए निर्यात कीमत

32. शांडांग डोंग्यूइ फ्लुओ सिलिकन मटीरियल्स कंपनी लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत को इस संबद्ध वस्तु का निर्यात करने की सूचना दी है। इस वस्तु की बिक्री भारत स्थित ग्राहकों को सीधे ही की गई है। भारतीय ग्राहकों को यह बिक्रियां एफओबी और सीआईएफ दोनों आधारों पर की गई हैं। इस कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** एमटी एमडीसी की बिक्री की है। फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए उत्पादक ने समुद्रपारीय परिवहन, भू-भागीय परिवहन, बैंक प्रभार, बीमा, कमीशन, क्रेडिट लागत और वैट का समायोजन करने का दावा किया है। प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा दावाकृत समायोजनों को अनन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है। इस उत्पाद के पैकड फार्म के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। तदनुसार, फैक्टरी बाह्य स्तर पर औसत निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है जिसे अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निंग्बो जुहुआ कैमिकल एंड साइंस कंपनी लिमिटेड, चीन के लिए निर्यात कीमत

33. निंग्बो जुहुआ कैमिकल एंड साइंस कंपनी लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत को इस संबद्ध वस्तु के निर्यात की सूचना दी है। इस वस्तु की बिक्री दो सरणियों के जरिए की गई है। एक इसके असंबद्ध निर्यातक एच के मोटेज इंटरनेशनल होल्लिंग लिमिटेड, हांगकांग है, जो इस संबद्ध वस्तु की बिक्री फार्मासिनो होल्लिंग (एचके) लिमिटेड, हांगकांग नामक एक अन्य निर्यातक/व्यापारी को करता है और कभी-कभी इसकी बिक्री भारत स्थित ग्राहकों को भी करता है। दूसरी सरणी ट्रिकान ड्राइ कैमिकल्स एलएलसी, यूएसए है, जिसके जरिए भी भारत में ग्राहकों को इसकी बिक्री की जाती है। इस कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान *** एमटी, एमडीसी का भारत को निर्यात किया था। प्रश्नावली प्रत्युत्तर से यह स्पष्ट है कि ट्रिकान ड्राइ कैमिकल्स एलएलसी, यूएसए ने उत्पादक निंग्बो जुहुआ कैमिकल एंड साइंस कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत को किए गए इस संबद्ध वस्तु के कुल निर्यात में से *** प्रतिशत निर्यात करने के बावजूद प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। चूंकि मूल्य श्रृंखला पूरी नहीं है, इसलिए प्राधिकारी ने अनन्तिम जांच परिणाम के इस स्तर पर सहयोगकर्ता उत्पादक/निर्यातक निंग्बो जुहुआ कैमिकल एंड साइंस कंपनी लिमिटेड के संपूर्ण प्रत्युत्तर को नामंजूर कर दिया। तथापि, अनन्तिम जांच परिणाम के बाद, ट्रिकान ड्राइ कैमिकल्स एलएलसी, यूएसए, ने अपने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं और मूल्य श्रृंखला को पूरा किया है।

चूंकि मूल्य श्रृंखला पूरी हो गई है, इसलिए प्राधिकारी निंगबो जुहुआ कैमिकल एंड साइंस कं. लि. की निर्यात कीमत इस प्रकार प्रस्तुत आकड़ों के आधार पर निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। इस प्रकार निर्धारित औसत कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

झेजियांग क्वूहना फ्लोर कैमिस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन के लिए निर्यात कीमत

34. जेजियांग क्वूहना फ्लोर कैमिस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन ने जांच की अवधि के दौरान भारत को इस संबद्ध वस्तु का निर्यात करने की सूचना दी है। भारत को इस संबद्ध वस्तु की बिक्री इसके असंबद्ध निर्यातकों/व्यापारियों फार्मासिनो होल्डिंग (एचके) लिमिटेड, हांगकांग, मर्सी ग्रुप कंपनी लिमिटेड, हांगकांग और पालीकेम कारपोरेशन, ताईवान के जरिए की गई थी। भारतीय ग्राहकों को इसकी बिक्री एफओबी एवं सीआईएफ आधार पर की गई है। इस कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान *** एमटी एमडीसी का निर्यात किया है। प्रश्नावली प्रत्युत्तर से यह देखा जा सकता है कि मर्सी ग्रुप कंपनी लिमिटेड, हांगकांग और पालीकेम कारपोरेशन, ताईवान ने उत्पादक/निर्यातक जेजियांग क्वूहना फ्लोर कैमिस्ट्री कंपनी लिमिटेड द्वारा इस संबद्ध वस्तु की कुल बिक्री में से *** प्रतिशत का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने यह ध्यान रखते हुए कि इस संबद्ध वस्तु के *** प्रतिशत के लिए प्रश्नावली प्रत्युत्तर उपलब्ध है, इस अनन्तिम जांच परिणाम के स्तर पर जेजियांग क्वूहना फ्लोर कैमिस्ट्री कंपनी लिमिटेड के प्रत्युत्तर को स्वीकार कर लिया है। उत्पादक/निर्यातक ने फैक्टरी बाह्य कीमत पर पहुंचने के लिए समुद्रपारीय परिवहन, समुद्रपारीय बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, बैंक प्रभारों, क्रेडिट लागत, प्रहस्तन प्रभारों और वैट के समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा दावाकृत समायोजनों को अनन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है। पैकिंग लागत में भारी अंतर के मद्देजर इस उत्पाद के खुले रूप के लिए पृथक निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। तदनुसार, फैक्टरी बाह्य स्तर पर औसत निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है जिसे अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

चीन जन.गण. के सहयोगकर्ता उत्पादकों और निर्यातकों के मामले में निर्यात कीमत

35. इस जांच में अन्य निर्यातकों द्वारा सहयोग न किए जाने के मद्देनजर अन्य निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण चीन जन.गण. के सहयोगकर्ता निर्यातकों की निर्यात कीमत पर विचार करते हुए की है। प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान सहयोगकर्ता उत्पादकों/निर्यातकों के बीच न्यूनतम प्रतिनिधिक आयात कीमत को सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों को अपनाकर की है। फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्रपारीय परिवहन, समुद्रपारीय बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, बैंक प्रभारों, क्रेडिट लागत, प्रहस्तन प्रभारों और वैट के समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा दावाकृत समायोजनों को अनन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है। पैकिंग लागत में भारी अंतर के मद्देनजर खुले रूप में और पैकड रूप में उपलब्ध उत्पाद के लिए पृथक निर्यात कीमत का निर्धारण किया है तदनुसार, फैक्टरी बाह्य स्तर पर औसत निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है जिसे अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

रूस के लिए निर्यात कीमत

36. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सूचना पर विचार किया है और निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर विचार करते हुए किया है। पैकिंग लागत में भारी अंतर के मद्देनजर खुले रूप में और पैकड रूप में उपलब्ध उत्पाद के लिए पृथक निर्यात कीमत का निर्धारण किया है तदनुसार, फैक्टरी बाह्य स्तर पर औसत निर्यात कीमत का अनन्तिम रूप से निर्धारण किया गया है जिसे अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

पाटन मार्जिन

37. पैक किए गए और खुले/बल्क रूप में उपलब्ध इस संबद्ध वस्तु के लिए प्रस्तावित अलग-अलग सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए इस संबद्ध वस्तु के लिए समग्र रूप से पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नवत किया गया है। यह देखा जा सकता है कि इस संबद्ध वस्तु के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और पर्याप्त है।

पाटन मार्जिन

देश	उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		यूएस डालर/ एमटी	यूएस डालर/ एमटी	यूएस डालर/ एमटी	%	% रेंज
चीन जन.गण.	शांडांग लिआचेंग लुक्सी सिक्स्थ कैमिकल फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)/लुक्सी कैमिकल (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड, हांगकांग, ट्रिक्ॉन एनर्जी लि., यूएसए, विनमार इंटरनेशनल लि., यूएसए, कोसमोस वीयू लि. हांगकांग (निर्यातक)	***	***	***	***	25-35
	शांडांग डोंग्यूइ फ्लुओ-सिलिकान मटीरियल्स कंपनी लिमिटेड(उत्पादक)	***	***	***	***	40-50
	निंग्बो जुहुआ कैमिकल एंड साइंस कंपनी लिमिटेड(उत्पादक)/एच के मोन्टेज इंटरनेशनल होलिंग लिमिटेड हांगकांग, फार्मासिनो होलिंग (एचके) लिमिटेड, हांगकांग, ट्रिक्ॉन ड्राई कैमिकल्स एलएलसी, यूएसए(निर्यातक)	**	**	**	**	40-50
	झेजियांग क्युहुआ फ्लोर कैमिस्ट्री कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)/फार्मासिनो होलिंग (एचके) लिमिटेड, हांगकांग, पालीकेम कारपोरेशन, ताईवान और मर्सी ग्रुप कंपनी लिमिटेड, हांगकांग (निर्यातक)	***	***	***	***	55-65
	कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	70-80
रूस	सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	40-50

क्षति मार्जिन

घरेलू उद्योग के विचार

38. क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किया है :

- विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वर्ष 2012-13 में गिरावट आई है और तत्पश्चात इसमें संगत रूप से वृद्धि हुई है।
- भारत में उत्पादन एवं खपत में आयातों में 2012-13 में गिरावट आई और तत्पश्चात इसमें संगत रूप से वृद्धि हुई।
- संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में वर्ष 2012-13 में गिरावट आई है और तत्पश्चात इसमें संगत रूप से वृद्धि हुई है और यह जांच की अवधि के दौरान भी बहुत अधिक है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के परिणामस्वरूप विगत वर्ष की तुलना में मामूली सी वृद्धि हुई है और उन देशों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है।

- (iv) विदेशी उत्पादकों अथवा इन व्यापारियों द्वारा कीमत में कमी करने के कारण भारतीय उत्पादकों के अपनी कीमतें इन आयात कीमतों के अथवा व्यापारियों की पुनर्विक्री कीमत के अनुरूप बनाने अथवा याचिकाकर्ता द्वारा अपने आर्डर खोने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं रहा है।
- (v) घरेलू उद्योग की कीमतें व्यापार जर्नल्स में रिपोर्ट की गई कीमतों और व्यापारियों द्वारा पेशकश की जा रही कीमतों के संयुक्त प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं।
- (vi) खुले रूप और पैकड रूप, दोनों रूपों में आयातित वस्तुएं घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन कर रही हैं। संबद्ध देशों से इस विचाराधीन उत्पाद के बारे में कीमत अधोरदन समग्र रूप से सकारात्मक है।
- (vii) घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें प्रपाती रूप से और अक्सर कम करने के लिए दबाव डाला गया।
- (viii) घरेलू उद्योग की मालसूची में वर्ष 2013-14 तक वृद्धि हुई, परंतु उसके पश्चात जांच की अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई है।
- (ix) घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकद लाभ के रूप में वर्ष 2013-14 तक भारी गिरावट आई है परंतु जांच की अवधि के दौरान इसमें मामूली सी वृद्धि हुई है।
- (x) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट बिना किसी युक्तियुक्त कारणों से आयात कीमतों में कमी होने के कारण आई है। भारी पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा सहन करना पड़ रहा है।

आयातकों/उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

39. क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं :

- (i) क्षति पैरामीटरों का विश्लेषण आधार वर्ष से किया जाना चाहिए परंतु घरेलू उद्योग ने यह वर्ष 2012-13 से किया है।
- (ii) रूस का कीमत अधोरदन चीन के कीमत अधोरदन की तुलना में अधिक दर्शाया गया है जबकि उतराई मूल्य चीन का अधिक है जबकि रूस का उतराई मूल्य कम है। इससे यह संकेत मिलता है कि कीमत अधोरदन का कृत्रिम रूप से सृजन किया गया है।
- (iii) जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि नहीं हुई है और यह घरेलू उत्पादन और कुल मांग की तुलना में हुआ है।
- (iv) घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जो आधार वर्ष में 34 प्रतिशत था बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 41 प्रतिशत हो गया।
- (v) घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, उत्पादकता और बिक्री में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है जिससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग की निधि उगाहने की क्षमता में वृद्धि प्रभावित नहीं हुई है।
- (vi) घरेलू उद्योग के लिए कीमत निग्रहण अथवा कीमत अवमंदन नहीं हुआ है।
- (vii) लाभप्रदता, नकदी प्रवाह और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में क्षति अवधि में गिरावट आई परंतु इन सभी कारकों में विगत वर्ष 2012-13 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- (viii) घरेलू उद्योग के वेतन एवं रोजगार में कोई क्षति प्रदर्शित नहीं की गई है।
- (ix) संबद्ध देशों से आरोपित पाटित आयात तथा घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध मौजूद नहीं है। संबद्ध देशों से घटते आयातों और घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि के बीच अनुलोमित संबंध है।
- (x) संबद्ध देशों से आयात कीमत में क्षति अवधि के दौरान 9 प्रतिशत तक की गिरावट आई है जब कि उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमत में 7 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की कीमतों पर यह प्रभाव उन देशों से आयातों के कारण पड़ा है, जिन पर पाटनरोधी शुल्क पहले से ही लगा है, न कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण।

प्राधिकारी द्वारा जांच

40. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में प्रावधान है कि किसी क्षति निर्धारण में उन सभी कारकों की जांच अंतर्ग्रस्त होगी जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत मिलता हो। ".....पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तु के लिए कीमतों पर उनके प्रभाव, और इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी

प्रभाव सहित सभी संगत कारकों पर विचार करते हुए " कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए यह जांच करना आवश्यक प्रतीत होता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है या क्या इन आयातों का प्रभाव उन कीमतों का भारी मात्रा में अवमंदन करना या कीमतों में वृद्धि को कम करना है जो अन्यथा भारी मात्रा में हुई होती।

41. नियमावली में यह अपेक्षा की जाती है कि प्राधिकारी क्षति की जांच मात्रा एवं कीमत प्रभाव दोनों की जांच करते हुए करेंगे। क्षति के निर्धारण (क) पाटित आयातों की मात्रा तथा समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर इन पाटित आयातों के प्रभाव और (ख) घरेलू उद्योग पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों की उद्देश्य परक जांच करना अंतर्गस्त होता है। पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में उत्पादन अथवा भारत में खपत के संगत रूप से अथवा अबाधित रूप से भारी वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है अथवा इन आयातों के प्रभाव से कीमतों में भारी मात्रा में निग्रहण होगा अथवा यह कीमतों में होने वाली उस वृद्धि की प्रतिनिवारित करेगा जो अन्यथा भारी मात्रा में घटित हुई होती।

42. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (iv) निम्नलिखित उल्लेख है:-

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक तथ्यों तथा उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले अन्य सभी कारकों जिसमें बिक्री, लाभ, आउट-पुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में प्राकृतिक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले तथ्यों, पाटन के मार्जिन की वास्तविक मात्रा तथा नकदी प्रवाह पर संभावित नकारात्मक प्रभाव, माल सूची, रोजगार, वेतनवृद्धि, पूंजीनिवेश उगाहने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाना शामिल होगा।"

43. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए पूर्वोक्त नियमावली के अनुबंध-II (iv) के अनुसार प्राधिकारी ने उन संकेतकों पर विचार किया है जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जैसे उत्पादन क्षमता उपयोग, बिक्री प्रमात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्रापण, पाटन मार्जिन एवं उसकी मात्रा आदि।

संचयी आकलन

44. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (iii) में प्रावधान है कि यदि किसी उत्पाद के आयात एक से अधिक देशों द्वारा किए जा रहे हैं और वे पाटनरोधी जांच के अध्यधीन हैं तो निर्दिष्ट प्राधिकारी यदि निम्नलिखित का निर्धारण करते हैं तो इन आयातों के प्रभावों का संचयी रूप से आकलन करेंगे :

- (i) प्रत्येक देश भूभाग से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान उत्पाद के आयातों का तीन प्रतिशत है अथवा जहां अलग-अलग देशों के निर्यात तीन प्रतिशत से कम हैं वहां संचयी रूप से यह आयात समान वस्तु के आयातों के सात प्रतिशत से अधिक बनते हैं; और
- (ii) आयातित वस्तु और घरेलू समान वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों के आलोक में इन आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उपयुक्त होता है।

45. वर्तमान मामले में

- क) प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन ऊपर निर्धारित सीमा से अधिक है;
- ख) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा उपयुक्त निर्धारित सीमा से अधिक है; और
- ग) आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उपयुक्त होगा क्योंकि संबद्ध देशों से आयात प्रत्यक्षतः परस्पर और भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु से प्रतिस्पर्धा करती है। यह नोट किया जाता है कि वर्तमान मामले में संचयी आकलन का विरोध करते हुए किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया है।

46. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उपयुक्त मानते हैं।

47. विस्तृत जांच करने के पश्चात यूरोपियन यूनियन और यूएसए से इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर दिनांक 21 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना के तहत अंतरिम पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया गया था और दिनांक 21 मई, 2014 की अधिसूचना के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया गया था। यह नोट किया जाता है कि यद्यपि ईयू और यूएसए से आयातों में गिरावट आई है वहीं वर्ष 2013-14 और जांच की अवधि में चीन और रूस से आयातों में वृद्धि हुई है।

मांग और बाजार हिस्सा

48. इस संबद्ध वस्तु की घरेलू खपत/मांग का आकलन करने के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री मात्रा को भारत को हो रहे कुल आयातों में जोड़ा गया है और उसे संक्षिप्त रूप से निम्नवत प्रस्तुत किया गया है :

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच की अवधि
याचिकाकर्ता की बिक्री	एमटी	60,28	72,879	70,476	73,205
अन्य उत्पादकों की बिक्री	एमटी	33,921	33,597	37,734	33,830
संबद्ध देश आयात	एमटी	16,514	334	6,757	15,629
वह देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	एमटी	60,974	56,324	62,444	47,571
अन्य देश	एमटी	6,956	279	484	540
कुल मांग/उपभोग	एमटी	78,651	163,413	177,895	170,774

49. यह नोट किया जाता है कि इस विचाराधीन उत्पाद की समग्र मांग ने मामूली सी गिरावट प्रदर्शित की है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि (क) मांग में यह कमी कुछ फार्मा कंपनियों द्वारा खपत में कमी करने के कारण आई है, (ख) घरेलू उद्योग को क्षति मांग में इस कमी के कारण नहीं आई है क्योंकि जांच की अवधि के दौरान भारत में 170,774 एमटी मांग की तुलना में भारतीय उद्योग की संयुक्त क्षमता 117,000 एमटी थी, (ग) देश में इस उत्पाद की भारी मांग के मद्देनजर घरेलू उद्योग को लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह के रूप में घाटा उठाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह तर्क भी दिया है कि जहां जांच की अवधि के दौरान इस विचाराधीन उत्पाद की मांग में 4.50 प्रतिशत की समग्र गिरावट प्रदर्शित हुई है, वहीं इन संबद्ध देशों से आयात जो (वर्ष 2012-13 के दौरान) 334 एमटी थे बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 15629 एमटी हो गए।

पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

आयात मात्रा एवं बाजार हिस्सा

50. पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि निर्बाध रूप से अथवा भारत में उत्पादन और उपभोग के संगत रूप में हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध देशों से इस संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा का विश्लेषण निम्नवत किया गया है :

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच की अवधि
आयात मात्रा					
संबद्ध देश	एमटी	16,514	334	6,757	15,629
चीन जन.गण.	एमटी	16,084	334	4,794	12,802

रूस	एमटी	430	-	1,963	2,827
वह देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	एमटी	60,974	56,324	62,444	47,571
अन्य देश	एमटी	6,956	279	484	540
कुल आयात मात्रा	एमटी	84,444	56,936	69,685	63,739
आयात मात्रा का बाजार हिस्सा					
संबद्ध देश	%	19.56	0.59	9.70	24.52
चीन जन.गण.	%	19.05	0.59	6.88	20.08
रूस	%	0.51	-	2.82	4.44
वह देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	%	72.21	98.92	89.61	74.63
अन्य देश	%	8.24	0.49	0.69	0.85
कुल आयात	%	100.00	100.00	100.00	100.00

51. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात में वर्ष 2012-13 में गिरावट आई और तत्पश्चात इसमें वृद्धि हुई जिससे जांच की अवधि में इसमें भारी वृद्धि दर्ज हुई। यह नोट किया जाता है कि उन देशों से आयात, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है, में, दिनांक 21 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 24/2013-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था, गिरावट आई है।

संगत रूप में आयात

52. उपभोग और उत्पादन के संबंध में आयातों का विश्लेषण निम्नवत किया गया है :

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच की अवधि
संबद्ध देशों का आयात					
भारत में उत्पादन के संबंध में	%	16.81	0.31	6.05	14.53
भारत में मांग/उपभोग के संबंध में	%	9.24	0.20	3.80	9.15

53. यह नोट किया जाता है कि उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में वर्ष 2012-13 में गिरावट आई और तत्पश्चात इसमें वृद्धि हुई।

आयातों का कीमत प्रभाव

54. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों का इतनी अधिक मात्रा में अवमंदन करना अथवा कीमतों में वृद्धि होने से रोकना है, जिनमें अन्यथा

भारी मात्रा में वृद्धि हुई होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत अधोरदन, कीमत निग्रहण और कीमत अवमंदन के संबंध में की गई है।

कीमत अधोरदन

55. यह निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या इन आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन हुआ है, प्राधिकारी ने आयातों की उतराई कीमत की तुलना घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण से की है :

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच की अवधि
चीन (लूज और पैकड)					
आयातों की उतराई कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
निवल बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
कीमत अधोरदन	रुपए/एमटी	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (%)	%	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (% रेंज)	%	ऋणात्मक	ऋणात्मक	ऋणात्मक	ऋणात्मक
रूस (लूज और पैकड)					
आयातों की उतराई कीमत	रुपए/एमटी	***	-	***	***
निवल बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	***	-	***	***
कीमत अधोरदन	रुपए/एमटी	***	-	***	***
कीमत अधोरदन (%)	%	***	-	***	***
कीमत अधोरदन (% रेंज)	%	ऋणात्मक	-	ऋणात्मक	5-15
संबद्ध देश (लूज और पैकड)					
आयातों की उतराई कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
निवल बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
कीमत अधोरदन	रुपए/एमटी	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (%)	%	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (% रेंज)	%	ऋणात्मक	ऋणात्मक	ऋणात्मक	ऋणात्मक

56. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान रूस से इस संबद्ध वस्तु की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी। तथापि, चीन जन.गण. के मामले में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना में यह मामूली सी अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप कीमत अधोरदन मामूली सा ऋणात्मक रहा है।

कीमत अधोविक्रयण

57. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा सहन किए गए कीमत अधोविक्रयण की जांच भी की है जो निम्नवत है :

विवरण	यूनिट	चीन जन.गण.	रूस
औसत गैर-क्षतिकारी कीमत	यूएस डालर/एमटी	***	***
औसत उतराई मूल्य	यूएस डालर/एमटी	***	***
कीमत अधोविक्रयण	यूएस डालर/एमटी	***	***
कीमत अधोविक्रयण	%	***	***
कीमत अधोविक्रयण	% Range	15-25	30-40

58. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से इस संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण जांच की अवधि के दौरान भारी कीमत अधोविक्रयण सहन करना पड़ा है।

कीमत निग्रहण और अवमंदन

59. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का निग्रहण अथवा अवमंदन कर रहे हैं और क्या इन आयातों के प्रभाव से कीमतों का भारी मात्रा में निग्रहण हुआ है अथवा इनसे कीमतों में वृद्धि होना निवारित हुई है, जिसमें अन्यथा भारी मात्रा में वृद्धि हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान कीमत और लागत में परिवर्तनों पर विचार किया है। प्राधिकारी ने इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ लूज (खुली) और पैक की गई सामग्री की औसत कीमत पर विचार किया है। अधोलिखित तालिका तथ्यपरक स्थिति दर्शाती है :

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	70	87	107
संबद्ध देशों का औसत उतराई मूल्य	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	81	84	91
बिक्री लागत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	105	133	132

60. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि उक्त अवधि के दौरान बिक्री लागत में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वर्ष 2012-13 में गिरावट आई परंतु तत्पश्चात उसमें वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, आयातों की उतराई कीमत ने भी बिक्री कीमत के समान ही प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। बिक्री कीमत में वृद्धि बिक्री लागत में हुई वृद्धि की तुलना में बहुत कम है। इस प्रकार आयात घरेलू बाजार में भारी कीमत निग्रहण कारित कर रहे हैं।

घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटर

61. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षा करता है कि क्षति के निर्धारण में इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच अंतर्गस्त होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में पुनः यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों एवं संकेतकों की उद्देश्यपरक एवं पक्षपात रहित मूल्यांकन शामिल होगी जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, इनमें शामिल है बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ या क्षमता उपयोग में संभावित एवं वास्तविक गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन

की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव मालसूची, रोजगार वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता शामिल है।

62. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति पैरामीटरों की जांच निम्नवत की गई है,:

i. घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग

63. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग का उल्लेख निम्नवत किया गया है :

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच की अवधि
संयंत्र क्षमता उपयोग	एमटी	106,688	117,000	117,000	117,000
संयंत्र उत्पादन	एमटी	120,240	135,877	130,133	131,973
संयंत्र क्षमता उपयोग	%	113%	116%	111%	113%
विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन	एमटी	62,788	74,386	71,689	73,335
घरेलू बिक्री मात्रा	एमटी	60,286	72,879	70,476	73,205

64. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस विचाराधीन उत्पाद का क्लोरोफार्म के साथ संयुक्त रूप से उत्पाद किया जाता है और टेट्राक्लोराइड सह-उत्पाद के रूप में उत्पादित होता है। चूंकि उत्पादन सुविधाएं समान हैं और उत्पादों का उत्पादन सह उत्पाद के रूप में किया जाता है, इसलिए क्षमता उपयोग की जांच मिथाइलीन क्लोराइड और क्लोरोफार्म का संयुक्त रूप से उत्पादन पर विचार करते हुए किया गया है।

65. यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता कंपनियों में से एक कंपनी ने वर्तमान क्षति अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि कर ली है। इस क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों, उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि मात्रा प्राचल घरेलू उद्योग के नियंत्रणाधीन है और घरेलू उद्योग अधिकतम मात्रा में उत्पादन और बिक्री करने का सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है ताकि इसकी नियत लागत का प्रेक्षण बड़े उत्पादन पर किया जा सके। तथापि, पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

ii. बाजार हिस्सा

66. पाटित आयातों के घरेलू बिक्रियों पर और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर प्रभाव की जांच निम्नवत की गई है :

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच की अवधि
मांग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	33.75	44.60	39.62	42.87
अन्य उत्पादकों की बिक्री	%	18.99	20.56	21.21	19.81
संबद्ध देश-आयात	%	9.24	0.20	3.80	9.15
उन देशों से आयात जिन पर पाटनरोधी की शुल्क लगा है	%	34.13	34.47	35.10	27.86
अन्य देशों से आयात	%	3.89	0.17	0.27	0.32
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00

67. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वर्ष 2012-13 में वृद्धि हुई और वर्ष 2013-14 में गिरावट आई और तत्पश्चात जांच की अवधि में इसमें पुनः वृद्धि हुई। संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में वर्ष 2012-13 में गिरावट और तत्पश्चात जांच की अवधि में इसमें भारी वृद्धि हुई।

iii. लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह

68. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, बिक्री कीमत और लाभ/हानि का विश्लेषण निम्नवत किया गया है :

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच की अवधि
बिक्री लागत – औसत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	105	133	132
बिक्री कीमत – औसत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	70	87	107
लाभ/हानि	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	(140)	(184)	(47)
ब्याज एवं कर पूर्व लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	(169)	(215)	(57)
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	(116)	(149)	(22)
निवेश पर प्रतिलाभ	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	(80)	(95)	(11)

69. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत वर्ष 2012-13 की बिक्री लागत के स्तर से कम है जिसके परिणामस्वरूप घाटा हुआ। घरेलू उद्योग को अन्य देशों से भी पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है। इस समय जिन देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगा है उनसे हो रहे कम कीमत वाले आयातों से याचिकाकर्ताओं का अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को वर्ष 2012-13 से घाटा होना प्रारंभ हो गया है। घरेलू उद्योग उन देशों पर जांच की अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क आकर्षित करने वाले देशों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित होने से अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम हुआ। तथापि, संबद्ध देशों से आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत उस स्तर तक भी बढ़ाने से वंचित कर दिया जिस स्तर तक उनकी बिक्री लागत में वृद्धि हुई थी और इसलिए जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा निरंतर बना रहा।

70. घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हो रहा है और इसके अतिरिक्त निवेश पर प्रतिलाभ भी वर्ष 2012-13 में ऋणात्मक हो गया और उन देशों से, जिन पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित है, भारी पाटन होने के कारण वर्ष 2013-14 में नकद घाटा और भी अधिक हो गया। इन देशों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से जांच की अवधि के दौरान नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ में कुछ मामूली सा सुधार हुआ, तथापि संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने पाटन के दुष्प्रभावों से संपूर्ण रूप से उबरने से घरेलू उद्योग को वंचित कर दिया।

iv. मालसूची

71. संबद्ध वस्तु की मालसूची से संबंधित आंकड़े अधोलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं :

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच की अवधि
औसत स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	167	328	117

72. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि औसत स्टॉक में वर्ष 2013-14 तक वृद्धि हुई और तत्पश्चात इसमें गिरावट आ गई।

v. रोजगार और वेतन

73. रोजगार और वेतन से संबंधित स्थिति निम्नवत हैं :

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	104	101	102
वेतन	रुपए लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	123	165	151

74. यह देखा जाता है कि जब रोजगार को एक विशिष्ट रेंज के अंतर्गत अनुरक्षित है तो वेतन क्षति अवधि तक बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है।

vi. उत्पादकता

75. उत्पादकता से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित दर्शाते हैं :

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच की अवधि
उत्पादकता प्रतिदिन	एमटी/दिवस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	93	110	106	109
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी/संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	114	113	114

76. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है और उसका उसी दिशा में झुकाव आया है जिस दिशा में उत्पादन का झुकाव था।

vii. पाटन की मात्रा

77. पाटन की मात्रा, उस सीमा की संकेतक के रूप में जिस तक पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं, यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों के विरुद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और पर्याप्त है।

viii. पूंजी निवेश उगहने की क्षमता

78. यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता कंपनियां बहु-उत्पाद कंपनियां हैं और याचिकाकर्ता कंपनियों में से एक कंपनी क्षति अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि की है। तथापि, वर्ष 2011-12 में भारी अतिरिक्त निवेश करने के बावजूद घरेलू उद्योग को ब्याज, कर एवं अवक्षयण से पूर्व अपने लाभ में वृद्धि करने में सक्षम होना चाहिए था। तथापि, अन्य देशों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के बाद भी उद्योग को घाटा उठाना पड़ रहा है, और इस प्रकार यह पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता को प्रभावित कर रहा है।

ix. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

79. संबद्ध देशों से आयात कीमतों, संरचना लागत में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा पर विचार करते हुए पाटित आयातों के अलावा उन अन्य कारकों पर विचार करते हुए, जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से आयातित सामान का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना में बहुत कम है, जिससे भारतीय बाजार में भारी कीमत अधोरदन और कीमत अधोविक्रयण हो रहा है। इस उत्पाद का कोई अन्य व्यवहार्य प्रतिस्थानी नहीं है। इस उत्पाद की मांग घरेलू उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे कीमत निग्रहण के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए उत्तरदायी एकमात्र कारक इस उत्पाद की आयात कीमतें और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत है। जैसाकि सूचना दर्शाएगी, इन आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें लागत में वृद्धि के अनुरूप बढ़ाने से वंचित किया है।

x. वृद्धि

80. घरेलू उद्योग का विकास विपरीत है, क्योंकि वर्ष 2011-12 को छोड़कर जांच की अवधि के दौरान लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह से संबंधित विकास पर्याप्ततः ऋणात्मक रहा है।

xi. उद्योग पाटित आयातों के विगत प्रभावों से उबर रहा है

81. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि नियमावली के अंतर्गत वर्णित विभिन्न क्षति पैरामीटर सर्वांगीण नहीं हैं और इस प्रकार प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले किसी भी अन्य कारक का विश्लेषण कर सकते हैं। यह प्रस्तुतिकरण किया गया है कि घरेलू उद्योग उन अन्य देशों द्वारा कारित पाटन के दुष्प्रभावों से मुक्त होने पर प्रयास कर रहा है जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है। तथापि, मौजूदा संबद्ध देशों से पाटित आयात घरेलू उद्योग के विकास को निवारित कर रहा है। इस संबंध में यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के अन्य देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगे होने के बावजूद लगातार घाटा हो रहा है।

वास्तविक क्षति संबंधी निष्कर्ष

82. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव की जांच करने के पश्चात यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में वर्ष 2012-13 में गिरावट आई और तत्पश्चात इसमें निर्बाध रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संगत रूप से वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में वर्ष 2012-13 में गिरावट आई और तत्पश्चात इसमें वृद्धि हुई। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण मात्रा क्षति नहीं हुई है। तथापि, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण कीमत प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का भारी कीमत अधोरदन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण भारी कीमत निग्रहण हुआ है। लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर प्रतिलाभ ऋणात्मक रहा है। अन्य देशों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के बावजूद घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण घाटा उठाना पड़ा है। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यद्यपि उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियां, बाजार हिस्सा के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है, तथापि, लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में कमी आई है। इस प्रकार प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

अन्य ज्ञात कारक एवं कारणात्मक संबंध

83. वास्तविक क्षति, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के मात्रा एवं कीमत प्रभाव की जांच करने के पश्चात प्राधिकारी ने कीमत अधोरदन, अधोविक्रयण और कीमत निग्रहण एवं अवमंदन प्रभाव, भारतीय नियमावली और पाटनरोधी

करार के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य संकेतात्मक पैरामीटरों की जांच यह देखने के लिए की कि क्या पाटित आयातों के अलावा कोई अन्य कारक है जिसने घरेलू उद्योग की क्षति में अपना योगदान दिया हो।

क) तृतीय देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

84. यह नोट किया गया कि इस विचाराधीन उत्पाद के अन्य देशों से आयात या तो मात्रा के रूप में नगण्य रहे हैं या उन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात कीमतें जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक नहीं हैं।

ख) मांग में संकुचन और खपत के प्रतिमान में परिवर्तन

85. जैसाकि इससे पूर्व नोट किया गया है, घरेलू बाजार में इस संबद्ध वस्तु के लिए खपत के प्रतिमान और मांग परिदृश्य यह दर्शाता है कि क्षति अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की मांग में गिरावट आई है, जिसके लिए कुछ फार्मा कंपनियों द्वारा खपत को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तथापि, यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति मांग में गिरावट के कारण नहीं हुई है क्योंकि भारत में कुल 170,774 एमटी मांग की तुलना में भारतीय उद्योग की संयुक्त क्षमता 189000 एमटी थी और इसलिए देश में इस उत्पाद की भारी मांग के मद्देनजर घरेलू उद्योग को लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह के लिए घाटा उठाने की आवश्यकता नहीं थी।

ग) प्रौद्योगिकी में विकास

86. इस संबद्ध उत्पाद का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी में विकास वह कारक नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

घ) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं तथा विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

87. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है जिसने घरेलू उद्योग की क्षति में अपना योगदान दिया हो।

ड.) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

88. प्राधिकारी द्वारा जांच की गई क्षति सूचना घरेलू प्रचालनों से संबंधित है और इसलिए, निर्यात निष्पादन ने घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं की है।

च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

89. यह नोट किया जाता है कि प्रति कर्मचारी उत्पादन तथा प्रतिदिन उत्पादन के रूप में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में जांच की अवधि के दौरान सुधार हुआ है।

90. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि अन्य ज्ञात कारक यह नहीं दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को इन अन्य कारकों के कारण क्षति सहन करनी पड़ी है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या इस उत्पाद के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति कारित हुई है। अधोलिखित पैरामीटर यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों द्वारा कारित की गई है :

- क) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का भारी अधोरदन कर रहे हैं।
- ख) घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों में वृद्धि करने से वंचित किया गया। घरेलू उद्योग द्वारा सहन किया गया कीमत निग्रहण संबद्ध देशों से इस उत्पाद के पाटन के कारण हुआ है।
- ग) घरेलू उद्योग को अपनी उत्पादन लागत से भी कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए मजबूर किया गया जिसके कारण उन्हें भारी वित्तीय घाटा हुआ। इस प्रकार, आयातों द्वारा कारित किया गया कीमत निग्रहण के परिणामस्वरूप जांच की अवधि में वित्तीय घाटा हुआ।
- घ) लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर प्रतिलाभ के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन कीमत निग्रहण और कीमत अधोरदन के परिणामस्वरूप ऋणात्मक रहा। इस प्रकार, इस उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर प्रतिलाभ के रूप में गिरावट आई है।
- ड) अन्य देशों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित होने के बावजूद, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में घाटा संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण हो रहा है।

91. इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

क्षति मार्जिन का परिमाण

92. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की निर्धारित गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देशों के निर्यातों के उतराई मूल्य से की गई है। इस तरह निर्धारित क्षति मार्जिन निम्नलिखित है :

क्षति मार्जिन

विवरण	यूनिट	चीन जन.गण.	रूस
औसत गैर-क्षतिकारी कीमत	यूएस डालर/एमटी	***	***
औसत उतराई मूल्य	यूएस डालर/एमटी	***	***
कीमत अधोविक्रयण	यूएस डालर/एमटी	***	***
कीमत अधोविक्रयण	%	***	***
कीमत अधोविक्रयण	% Range	15-25	30-40

देश	उत्पादक/निर्यातक	औसत गैर-क्षतिकारी कीमत	औसत उतराई मूल्य	कीमत अधोविक्रयण	कीमत अधोविक्रयण	कीमत अधोविक्रयण
		यूएस डालर/एमटी	यूएस डालर/एमटी	यूएस डालर/एमटी	%	% रेंज
चीन जन. गण.	शांडांग लिआचेंग लुक्सी सिक्स्थ कैमिकल फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)/लु क्सी कैमिकल (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड, हांगकांग, ट्रिक्ॉन एनर्जी लि., यूएसए, विनमार इंटरनेशनल लि., यूएसए, कोसमोस वीयू लि. हांगकांग (निर्यातक)	***	***	***	***	10-20
	शांडांग डोंग्यूइ फ्लुओ-सिलिकान मटीरियल्स कंपनी लिमिटेड(उत्पादक)	***	***	***	***	10-20
	निंग्बो जुहुआ कैमिकल एंड साइंस कंपनी लिमिटेड(उत्पादक)/एच के मोन्टेज इंटरनेशनल होल्लिंग लिमिटेड हांगकांग, फार्मासिनो होल्लिंग (एचके) लिमिटेड, हांगकांग, ट्रिक्ॉन ड्राई कैमिकल्स एलएलसी, यूएसए(निर्यातक)	***	***	***	***	20-30
	झेजियांग क्युहुआ फ्लोर कैमिस्ट्री कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)/फार्मासिनो होल्लिंग (एचके) लिमिटेड, हांगकांग, पालीक्रेम कारपोरेशन, ताईवान और मर्सी ग्रुप कंपनी लिमिटेड, हांगकांग (निर्यातक)	***	***	***	***	20-30

	कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	40-50
रूस	सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	30-40

पञ्चः प्रकटीकरण विवरण टिप्पणियां

विरोधी हितबद्ध पक्षों की पञ्चः प्रकटीकरण टिप्पणियां

93. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों की प्रकटन के बाद की टिप्पणियां संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

- i. चूंकि प्राधिकारी खुले/बल्क और पैकड रूप में उत्पाद के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का विश्लेषण कर रहे हैं इसलिए जाँच की गई अलग-अलग कंपनियों के लिए उत्पाद के खुले/बल्क और पैकड रूप के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण अलग-अलग किया जाना चाहिए। भारित औसत पाटन मार्जिन और भारित औसत क्षति मार्जिन का निर्धारण उनके द्वारा भारत को निर्यात बिक्रियों के लिए खुले/बल्क और पैकड उत्पाद के भार के आधार पर और न कि सरल औसत के आधार पर किया जाए क्योंकि उससे पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का अलग निर्धारण हो सकता है।
- ii. आईबीआईएस के आयात आकड़ों में उच्चतर आयात दर्शाए गए हैं। कुल आयातों में रूस का हिस्सा न्यूनतम हैं क्योंकि कुल आयातों में उनका हिस्सा केवल 2.94 प्रतिशत है। इस तर्क को नकारने के लिए प्रकटन विवरण में कोई विश्लेषण या कारण रिकार्ड नहीं किया गया है कि आईबीआईएस आयात आकड़ों में बताए गए आयात सही हैं। चीन के सहयोगी निर्यातकों और रूस से एक भागीदार निर्यातक द्वारा वास्तविक आयातों का संबंधित संबद्ध देशों के लिए डीजीसीआईएंडएस के आयात आकड़ों के आधार पर बताए गए आयातों के साथ विश्लेषण भी नहीं किया गया है।
- iii. देशों जिनपर पाटनरोधी शुल्क लागू है से लगभग 80 प्रतिशत के काफी अधिक आयातों के प्रभाव के संबंध में विश्लेषण इस प्रकार से नहीं किया गया है कि उन देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की स्थिति पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है और घरेलू उद्योग को क्षति केवल संबद्ध देशों से आयातों के कारण हुई है।
- iv. प्रकटन विवरण में यह समुक्ति कि चीन से सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध 1 के पैरा 7 में विहित आधारों में से किसी पर किया जा सकता है त्रुटिपूर्ण है और वह शेनयांग मतसुशिता 2005 (181) ईएलटी 320 (एससी) मामलों में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया के उल्लंघन में है।
- v. चूंकि रूस से एक निर्यातक ने रूस में घरेलू कीमतों के लिए परिशिष्ट 1 में अपनी सूचना प्रस्तुत की है, इसलिए पैरा 7 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए चीन के सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उन पर विचार किया जाए।
- vi. संबद्ध देशों से कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और कारणात्मक संबंध मौजूद नहीं है।
- vii. कंपनियों के लिए भारित औसत क्षति मार्जिन की गणना उनके द्वारा भारत को निर्यात बिक्रियों के लिए खुले/बल्क और पैकड उत्पाद के अलग-अलग भार के आधार पर की जा सकती है।
- viii. शानडोंग लियाचेंग लक्सी सिक्स्थ कैमिकल फर्टिलाइजर्स कं. लि. और निंगबो जुहुआ कैमिकल एंड साइंस कं. लि. के लिए पाटन मार्जिन सही प्रदान किया गया है तथापि, ट्रिकान ड्राई कैमिकल एलएलसी को पाटन मार्जिन तालिका में संगत व्यापार शृंखला में शामिल नहीं किया गया है।
- ix. रूसी परिसंघ के उद्योग और व्यापार मंत्रालय ने बताया है कि:
 - (i) सामान्य मूल्य की गणना एडी करार के उपबंधों के अनुसार नहीं की गई है। सामान्य मूल्य की गणना के वैकल्पिक तरीके तभी उचित होते हैं यदि व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान उत्पाद की कोई बिक्रिया न हो या बाजार विशेष की स्थिति या बिक्रियों की कम मात्रा के कारण उचित तुलना न हो सके।
 - (ii) यदि हितबद्ध पक्ष द्वारा प्रदत्त सूचना सभी तरह से आदर्श न भी हो तो उसे मनमाने ढंग से विचार करने से बाहर नहीं किया जा सकता है।

- (iii) जेएससी खिमप्राम के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन एडीकरार के अनुच्छेद 2 और 6.8 का उल्लंघन है। महानिदेशक ने असंबंधित कंपनियों से आकड़े प्राप्त करने में खिमप्राम को आई दिक्कतों पर ध्यान नहीं दिया है।
- (iv) निर्यात कीमत की गणना भारतीय उत्पादकों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर की गई है और अनुच्छेद 6.8 के उल्लंघन में आकड़ों पर आधारित नहीं है। जेएससी खिमप्राम द्वारा प्रदत्त अनुप्रयोज्य आकड़ों पर विचार किया गया है। प्राधिकारी निर्यातकों और आयातकों के बीच संबद्धताया किसी क्षतिपूर्ति व्यवस्था की मौजूदगी को सिद्ध करने में विफल रहे हैं।
- (v) रूसी निर्यातों की मांग में बाजार हिस्सा केवल 1.66 प्रतिशत है। इतने कम प्रतिशत से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।
- (vi) प्राधिकारी 2011-14 में घरेलू उद्योग की सकारात्मक स्थिति जैसे मांग, बिक्री में बाजार हिस्से में वृद्धि, पर ध्यान नहीं दे पाए हैं। 2012-13 में घरेलू उद्योग की क्षमता पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त बोझ था।
- (vii) कुछ कारकों के ऋणात्मक आकड़ों ने क्यों अनेक अन्य कारकों के सकारात्मक आकड़ों को कैसे धता बता दिया, इसका कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

घरेलू उद्योग की पश्चः प्रकटीकरण टिप्पणियां

94. घरेलू उद्योग की प्रकटन के बाद की टिप्पणियां संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

- i. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और यह क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के प्रतिकूल कीमत प्रभाव के द्वारा साक्ष्यांकित है।
- ii. सूचना क्षति अवधि के लिए है और न कि केवल पीओआई और उसके पूर्ववर्ती वर्ष के लिए। अन्यथा, उससे लंबी अवधि के लिए आकड़े मंगाने का पूरा प्रयोजन ही विफल हो जाता है। चूंकि विचाराधीन उत्पाद 2013-14 में अन्य देशों से पाटित किया जा रहा था इसलिए घरेलू उद्योग को उन देशों से आयातों के संबंध में इस अवधि में क्षति का सामना करना पड़ रहा था। जाँच अवधि में ह्रासकारी/न्यूनकारी प्रभाव सीमित थे क्योंकि अन्य देशों से पाटन पर रोक लगी थी। तथापि घरेलू उद्योग को इस कारण से लाभ पर दबाव का सामना करना पड़ा कि वर्तमान संबद्ध देशों से अलग पाटन शुरू हो गया।
- iii. यह अभूतपूर्व निर्णय है और एनआईपी संबंधित रिट याचिकाओं में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष निदेशालय द्वारा दायर अनेक शपथपत्रों का उल्लंघन में, उच्च न्यायालय में लम्बित इन रिट याचिकाओं के संबंध में डीजीएडी द्वारा परिचालित बैठक के कार्यवृत्त में एनआईपी का निर्धारण आबद्ध निविष्टियों पर नियोजित पूंजी पर आय को जोड़े बिना किया गया है। विभिन्न मामलों में एनआईपी कानून से डीजीएडी द्वारा की जा रही व्याख्याएं कानून से असंगत हैं और डीजीएडी ने एनआईपी कानून को पूर्णतः समर्थित करते हुए इन रिट याचिकाओं में स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत किए हैं। आबद्ध निविष्टियों पर नियोजित पूंजी पर आय को जोड़े बिना वर्तमान मामले में एनआईपी के निर्धारण का प्रस्ताव एनआईपी कानून के दायरे से भी बाहर जाने जैसा है और एक स्पष्ट तथ्य पर विषयपरक आकलन को शुरू करने के समान है। यह प्रस्ताव निम्नलिखित से असंगत है:
- क. नियम 17(1)(ख) जिसमें प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी शुल्क की उस राशि को निर्धारित करना अपेक्षित है जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हो।
- ख. अनुबंध-11। जिसमें प्राधिकारी के लिए कच्ची सामग्रियों के सर्वोत्तम उपयोग और जाँच अवधि की दर पर विचार करते हुए उत्पादन की लागत निर्धारित करना अपेक्षित है।
- ग. निम्नलिखित रिट याचिकाओं में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दायर किए गए उत्तर जिनमें एनआईपी कानून को 'इस प्रकार' और 'यथा लागू' रूप में चुनौती दी गई है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इन शपथपत्रों में बताया है कि यदि आबद्ध रूप से उत्पादित निविष्टियों को उत्पादन लागत पर आधारित दर पर हस्तांतरित किया जाता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उनकी उत्पादन लागत के अलावा आबद्ध रूप से उत्पादित निविष्टियों के उत्पादन में नियोजित पूंजी पर तर्कसंगत आय की अनुमति देते हैं।

घ. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के उपबंधों को संशोधित करने के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षों से प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों पर चर्चा करने के लिए 29.12.2015 को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बुलाई गई बैठक के परिणामस्वरूप डीजीएडी द्वारा बैठक के कार्यवृत्त अधिसूचित किए गए थे। इस बैठक की अध्यक्षता निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई थी और उसमें डीजीएडी के सभी अधिकारी उपस्थित थे। तत्कालीन परामर्शदाता भी बैठक में उपस्थित थे। इन बैठक के कार्यवृत्तों को डीजीएडी द्वारा 20 जनवरी, 2016 के ईमेल द्वारा परिचालित किया गया था जिनमें प्राधिकारी ने बताया है कि यदि घरेलू उद्योग उत्पादन लागत पर आबद्ध रूप से उत्पादित निविदियों की गणना करता है तो ऐसी निविदियों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त परिसम्पत्तियों के लिए नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय की अनुमति भी होगी।

प्राधिकारी द्वारा जांच

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रकटन विवरण के बाद किए गए अधिकांश अनुरोध दोहराई गई प्रवृत्ति के हैं और उनपर पहले ही प्रकटन विवरण में विचार किया गया है और पुनः अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में समुचित शीर्षों के अंतर्गत ध्यान दिया गया है। संगत समझे गए अतिरिक्त मुद्दों पर निम्नानुसार ध्यान दिया गया है:

- i. इस तर्क के संबंध में कि चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध के पैरा 7 में निर्धारित क्रम के अनुसार किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि अनुक्रम का पालन किया जाना चाहिए, बशर्ते कि पद्धति के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्राधिकारी को उपलब्ध कराए जाएं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने कीमत या बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में परिकलित मूल्य उपलब्ध नहीं कराया है। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से अन्य देशों को कीमत भी याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। यह नोट किया जाए कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमतों को भी इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि (क) किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है (ख) विचाराधीन उत्पाद में अनेक अलग-अलग किस्में शामिल हैं जिनकी संबद्ध लागतों और कीमतों में अंतर है (ग) कारखाना-द्वारा कीमत निर्धारित करने के लिए कीमत समायोजन उपलब्ध नहीं हैं। बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत को कीमत को अपनाया नहीं जा सकता है क्योंकि इन आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू था और इसलिए वह पाटित आयात कीमतें हैं। चीन के उत्पादकों या आयातों या किसी अन्य हितबद्ध पक्ष ने कोई दावा नहीं किया है न ही बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, रूस से सहयोगी उत्पादक का उत्तर अधूरा है और इसलिए उसके आकड़ों का विश्लेषण वांछित सीमा तक नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी की राय है कि एकमात्र उपलब्ध विकल्प तर्कसंगत लाभ मार्जिन को शामिल करके विधिवत रूप से समायोजित उत्पादन लागत के अनुमानों पर विचार करते हुए 'किसी अन्य आधार' पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना है।
- ii. इस तर्क के संबंध में कि क्षति पहुंचाने वाले देशों जिनपर पाटनरोधी शुल्क लागू है, के संबंध में कोई विश्लेषण नहीं किया गया है, यह नोट किया जाता है कि अन्य देश जिनपर एडीडी लागू है, पर उन पर इस समय लागू पाटनरोधी शुल्क द्वारा ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, इस अधिसूचना के संगत भाग में विशेष रूप से नोट किया गया है कि एडीडी लागू वाले देशों से आयातों में गिरावट आई है जबकि वर्तमान संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि हुई है।
- iii. यह स्पष्ट किया जाता है कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण जाँच की गई अलग-अलग कंपनियों के लिए खुले/बल्क और पैकड उत्पाद के लिए अलग अलग किया गया है और भारित औसत क्षति मार्जिन का निर्धारण खुले/बल्क और पैकड उत्पाद के भार के आधार पर किया गया है।
- iv. इस तर्क के संबंध में कि आईबीआईएस के आयात आकड़े अधिक आयात दर्शाते हैं और यह कि कुल आयातों में रूस का हिस्सा केवल 2.94 प्रतिशत है और इसलिए न्यूनतम है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजीसीआईएंडएस के आकड़ों के आधार पर आयात आकड़े अपनाये गये हैं।
- v. सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में रूस के निर्यातक का दावों पर यहां उपर्युक्त निर्धारित पाटन मार्जिन में उचित रूप से ध्यान दिया गया है।

- vi. ट्रिकान ड्राई कैमिकल्स एलएलसी के नाम को अब पाटन मार्जिन तालिका के संगत व्यापार चैनलों में शामिल किया गया है।
- vii. खिमप्राम के लिए अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में, प्राधिकारी दोहराते हैं कि प्रश्नावली के उत्तर में भारी खामियों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी मानते हैं कि उत्पादक-निर्यातक से प्रश्नावली का पूरा उत्तर अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए अनिवार्य है।
- viii. भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग/खपत में रूस के कम बाजार हिस्से के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में विचाराधीन उत्पाद की खपत के आधार पर कोई न्यूनतम मापदंड नहीं हैं। नियमावली में भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों के अनुसार नगण्यता परीक्षण की व्यवस्था है और यह देखा जाता है कि रूस से आयात कानून में विहित सीमा से अधिक हैं।
- ix. घरेलू उद्योग द्वारा पहले के समय में उठाई गई क्षति और अन्य स्रोतों से पाटन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य स्रोतों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के बाद देशों के वर्तमान समूह से पाटन तेज हो गया है। संबद्ध देशों से आयातों की वर्तमान मात्रा को पूर्ववर्ती पाटन और उत्पाद पर लागू पाटनरोधी शुल्क के आलोक में देखा जाना चाहिए।
- x. घरेलू उद्योग के कुछ मापदंडों में सकारात्मक रुझान के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति विश्लेषण घरेलू उद्योग के समग्र कार्यनिष्पादन पर विचार करते हुए किया जाना अपेक्षित है। जाँच से स्पष्ट रूप से पता चला है कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में समग्र और संचयी आधार पर क्षति अवधि के दौरान विकृति प्रदर्शित हुई है।
- xi. इस तर्क के संबंध में कि एनआईपी संबंधित रिट याचिकाओं में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष निदेशालय द्वारा दायर अनेक शपथपत्रों के उल्लंघन में और उच्च न्यायालय में लम्बित इन रिट याचिकाओं के संबंध में डीजीएडी द्वारा परिचालित बैठक के कार्यवृत्त में एनआईपी का निर्धारण आबद्ध निविष्टियों पर नियोजित पूंजी पर आय को जोड़े बिना किया गया है और इसलिए आबद्ध निविष्टियों पर नियोजित पूंजी पर आय को जोड़े बिना वर्तमान मामले में एनआईपी के निर्धारण का प्रस्ताव एनआईपी कानून के दायरे से भी बाहर जाने जैसा है और एक स्पष्ट तथ्य पर विषयपरक आकलन को शुरू करने के समान है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निदेशालय ने वस्तुतः तीन अलग सिविल रिट याचिकाओं जिनका संख्यांक 2013 का 145, 2013 का 2453 और 2013 का 3782 है में दिल्ली उच्च न्यायालय में तीन विरोधी शपथपत्र दायर किए हैं और इन सभी तीन रिट याचिकाओं में निदेशालय ने यह संगत दृष्टिकोण अपनाया है कि यदि आबद्ध रूप से उत्पादित निविष्टियों को उत्पादन लागत पर आधारित दर पर हस्तांतरित किया गया है और तब निर्दिष्ट प्राधिकारी उनकी उत्पादन लागत के अलावा आबद्ध रूप से उत्पादित निविष्टियों के उत्पादन में नियोजित पूंजी पर तर्कसंगत आय की अनुमति देते हैं।
- xii. सिविल रिट याचिका सं. 2013 की 145 में यह बताते हुए प्रति शपथपत्र दायर किया गया था कि 'यह भी बताया जाता है कि पाटनरोधी नियमों के अनुबंध में यह भी अधिदेशित है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ कच्ची सामग्रियों के सर्वोत्तम उपयोग और सुविधाओं की घरेलू उद्योग द्वारा रखे गए लेखाओं की बहियों में अपनायी गई दरों पर विचार करें। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी खरीदी गई निविष्टियों की वास्तविक कीमत पर विचार करते हैं और आबद्ध रूप से उत्पादित निविष्टियों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा रखे गए लेखा बहियों अपनायी गई हस्तांतरण दर पर विचार करते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे आबद्ध रूप से उत्पादित निविष्टियों के लिए निवेश पर आय की अनुमति देते हैं यदि ऐसी निविष्टियों का हस्तांतरण उत्पादन लागत पर किया गया है।'
- xiii. इसके अलावा, सिविल रिट याचिकाओं 2013 की 2453 और 2013 की 3782 में, प्रति शपथ पत्र यह कहते हुए दायर किया गया था कि 'एनआईपी के निर्धारण के सिद्धांत में यह व्यवस्था है कि घरेलू उत्पादकों की लागत और वित्तीय रिकार्डों के अनुसार वास्तविक दरों (खपत की गई निविष्टियों के वास्तविक मूल्य के अनुसार) पर आवश्यक जाँच और मिलान के बाद विचार किया जाए। यदि आबद्ध रूप से उत्पादित निविष्टियों का हस्तांतरण उत्पादन लागत की दर के आधार पर किया गया है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे आबद्ध रूप से उत्पादित निविष्टियों के लिए उनकी उत्पादन लागत के अलावा आबद्ध रूप से उत्पादित निविष्टियों की लागत में निवेश पर आय की अनुमति देते हैं।'

- xiv. प्राधिकारी का यह मत है कि एनआईपी के निर्धारण की पद्धति पर उच्च न्यायालय में इस सैद्धांतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योगका यह तर्क कि वर्तमान मामले में आबद्ध निविष्टियों में नियोजित पूंजी पर आय को जोड़े बिना एनआईपी के निर्धारण के लिए प्राधिकारी का प्रस्ताव न केवल एनआईपी कानून के दायरे से भी बाहर जाने जैसा है बल्कि दिल्ली उच्च न्यायालय में प्राधिकारी द्वारा अपनाये गये मत के उल्लंघन में भी है, में सत्यता है। इस संबंध में प्राधिकारी ने नोट किया कि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग ने आबद्ध रूप से उत्पादित निविष्टियों को उत्पादन लागत (घरेलू उद्योग द्वारा रखे गये लागत और वित्तीय रिकार्डों के अनुसार) पर हस्तांतरित किया है। अतः प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग की एनआईपी का निर्धारण आबद्ध रूप से उत्पादित निविष्टियों की उत्पादन लागत के अलावा उत्पादन में नियोजित पूंजी पर तर्कसंगत आय की अनुमति देकर करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, घरेलू उद्योग की एनआईपी निर्धारित की गई है।

भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

96. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से भारत में इस उत्पाद के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से पाटन की प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ कम होगा, घरेलू उद्योग का पतन होने से रुकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में सहयोग मिलेगा। सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का प्रशमन करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा कायम हो सके जो देश के सामान्य हित में है। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से उपभोक्ताओं को इस संबद्ध वस्तु की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होगा और इसलिए उपभोक्ताओं इस संबद्ध वस्तु की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता अभी भी इस उत्पाद की आपूर्ति के दो अथवा उससे अधिक स्रोत बनाए रख सकते हैं।

सिफारिश

97. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं :

- क) इस विचाराधीन उत्पाद का भारत को संबद्ध देशों से सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया।
- ख) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण वास्तविक क्षति सहन करनी पड़ी है।
- ग) घरेलू उद्योग को यह वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है।

98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच प्रारंभ की गई तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई और निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के सभी पहलुओं पर सकारात्मक जानकारी पट्टान कराने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटनरोधी नियमावली में दी गई शर्तों के अनुरूप पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंधी की जांच प्रारंभ करके एवं आयोजित करके घरेलू उद्योग के लिए सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा इन पाटित आयातों के कारण हुई वास्तविक क्षति की स्थापना करने के पश्चात प्राधिकारी का विचार है कि पाटन और परिणामी "क्षति" को दूर करने के लिए निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना अपेक्षित है जिससे कि घरेलू उद्योग की क्षति दूर हो सके। घरेलू उद्योग ने सहन की जा रही क्षति का निराकरण करने के लिए पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने का अनुरोध किया है।

99. प्राधिकारी यह अपनाए गए न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के न्यूनतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं जिससे कि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट राशि के अनुरूप पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वस्तु विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	290312	डाइक्लोरो-मिथेन ("मिथाइलीन क्लोराइड)	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	शांडांग डोंग्यूइ फ्लुओ-सिलिकान मैटीरियल्स कंपनी लिमिटेड	शांडांग डोंग्यूइ फ्लुओ-सिलिकान मैटीरियल्स कंपनी लिमिटेड	143.71	एमटी	यूएस डालर
2	290312	डाइक्लोरो-मिथेन ("मिथाइलीन क्लोराइड)	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	झेजियांग क्युहुआ फ्लोर कैमिस्ट्री कंपनी लिमिटेड	झेजियांग क्युहुआ फ्लोर कैमिस्ट्री कंपनी लिमिटेड/फार्मासिनो होल्डिंग (एचके) लिमिटेड, हांगकांग/पालीकेम कारपोरेशन, ताईवान/मर्सी ग्रुप कंपनी लिमिटेड, हांगकांग	166.83	एमटी	यूएस डालर
3	290312	डाइक्लोरो-मिथेन ("मिथाइलीन क्लोराइड)	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	शांडांग लिआचेंग लुक्सी सिक्स्थ कैमिकल फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड	शांडांग लिआचेंग लुक्सी सिक्स्थ कैमिकल फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड	122.14	एमटी	यूएस डालर
4	290312	डाइक्लोरो-मिथेन ("मिथाइलीन क्लोराइड)	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	शांडांग लिआचेंग लुक्सी सिक्स्थ कैमिकल फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड	लुक्सी कैमिकल (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड, हांगकांग	122.14	एमटी	यूएस डालर
5	290312	डाइक्लोरो-मिथेन ("मिथाइलीन क्लोराइड)	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	शांडांग लिआचेंग लुक्सी सिक्स्थ कैमिकल फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड	लुक्सी कैमिकल (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड, हांगकांग/ट्रिकॉन एनर्जी लि., यूएसए/विनमार इंटरनेशनल लि., यूएसए/कोसमोस वीयू लि. हांगकांग	122.14	एमटी	यूएस डालर
6	290312	डाइक्लोरो-मिथेन ("मिथाइलीन क्लोराइड)	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	निंग्बो जुहुआ कैमिकल एंड साइंस कंपनी	निंग्बो जुहुआ कैमिकल एंड साइंस कंपनी लिमिटेड/एच के मोन्टेज इंटरनेशनल होल्डिंग	162.16	एमटी	यूएस डालर

					लिमिटेड	लिमिटेड हांगकांग /फार्मासिनो होलिंग (एचके) लिमिटेड, हांगकांग /ट्रिकॉन ड्राई कैमिकल्स एलएलसी, यूएसए			
7	290312	डाइक्लोरो- मिथेन ("मिथाइलीन क्लोराइड)	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	उपर्युक्त क्रम संख्या को छोड़कर कोई अन्य संयोजन		279.78	एमटी	यूएस डालर
8	290312	डाइक्लोरो- मिथेन ("मिथाइलीन क्लोराइड)	चीन जन.गण.	कोई	कोई	कोई	279.78	एमटी	यूएस डालर
9	290312	डाइक्लोरो- मिथेन ("मिथाइलीन क्लोराइड))	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य देश	चीन जन.गण.	कोई	कोई	279.78	एमटी	यूएस डालर
10	290312	डाइक्लोरो- मिथेन ("मिथाइलीन क्लोराइड)	रूस	रूस	कोई	कोई	219.00	एमटी	यूएस डालर
11	290312	डाइक्लोरो- मिथेन ("मिथाइलीन क्लोराइड)	रूस	कोई	कोई	कोई	219.00	एमटी	यूएस डालर
12	290312	डाइक्लोरो- मिथेन ("मिथाइलीन क्लोराइड)	संबद्ध देशों के अलावा कोई अन्य देश	रूस	कोई	कोई	219.00	एमटी	यूएस डालर

नोट: जहां कहीं किसी संबद्ध देश के संबंध में किसी सीमाशुल्क अधिसूचना में इस सम्बद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क का अतिछादन हुआ है, तो उस सम्बद्ध देश पर लागू शुल्क वह होगा जो सीमाशुल्क अधिसूचना के अंतर्गत अधिरोपित किया गया और जिसमें उस देश का उल्लेख विशेष रूप से 'उदगम का देश' कालम के अन्तर्गत किया गया।

100. उक्त के अधीन, प्राधिकारी प्रारंभिक जाँच परिणाम अधिसूचना सं. 14/33/2014-डीजीएडी दिनांक 30.10.2015 की पुष्टि करते हैं।
101. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी शुल्क शामिल होंगे।
102. केन्द्र सरकार द्वारा इस जांच परिणाम पर आधारित आदेश के विरुद्ध खिलाफ कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2016

(FINAL FINDINGS)

Subject: Anti-dumping Investigation concerning import of “Methylene Chloride” originating in or exported from China PR and Russia—reg.

No. 14/33/2014-DGAD.—Whereas in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the AD Rules or the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), received a written application from M/s Chemplast Sanmar Limited and M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd (hereinafter also referred to as the petitioners or applicants) on behalf of the domestic industry producing Methylene Chloride (hereinafter referred to as the subject goods or the product under consideration {PUC}) in India, alleging dumping of the subject goods from People’s Republic of China and Russia (hereinafter referred to as the subject countries).

2. Whereas the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicants on behalf of the domestic industry, issued a public notice dated 7th April 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, in accordance with the sub-Rule 6(1) of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to consider recommendation of the anti-dumping duty.

PROCEDURE

3. The following Procedure described below has been followed with regard to this investigation:

- i. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of an application from the applicants alleging dumping before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the Anti-dumping Rules.
- ii. The Authority issued a public notice dated 7th April, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.
- iii. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were made available by the Applicants) and industry associations and gave them opportunity to make their views known in writing within the prescribed time in accordance with the Rule 6(2) of the Anti-dumping Rules.
- iv. The Authority also forwarded a copy of the public notice to all the known importers of the subject goods in India (whose details were made available by the Applicants) and advised them to make their views in writing within the prescribed time limit.
- v. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters and the embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Anti-dumping Rules. A copy of the Application was also made available other interested parties, upon request.
- vi. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Anti-dumping Rules:
 - a. Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd.
 - b. Jiangsu Meilan Chemical Co., Ltd.
 - c. Zhejiang Juhua Co., Ltd.
 - d. JSC Khimprom
 - e. Kong Long Huat

- f. Zouping Changshan Zefeng Fertilizer Co., Ltd.
 - g. Dalian Richfortune Chemical Company
 - h. Tianjin Yuanlong Chemical Industry Co., Ltd.
- vii. After the initiation, the Authority received responses from the following exporters from the subject countries:
 - a. Shandong Liaocheng Luxi Sixth Chemical Fertilizer Co. Ltd., China PR
 - b. Lu Xi Chemical (Hong Kong) Co.Ltd., Hong Kong (Exporter)
 - c. Shandong Dongyue Fluo-Silicon Materials Co. Ltd., China PR
 - d. Ningbo Juhua Chemical & Science Co. Ltd., China PR
 - e. Zhejiang Quhua Flour–chemistry Co. Ltd., China PR
 - f. Farmasino Holding (HK) Limited, Hong Kong (Exporter)
 - g. HK Montage International Holding Limited, Hong Kong (Exporter)
 - h. Khimprom Public Joint Stock Company, Russia
- viii. However, none of the exporters from China PR either claimed market economy treatment or filed questionnaire response to the market economy questionnaire issued by the Designated Authority. Further, after the initiation, Shandong Liaocheng Luxi Sixth Chemical Fertilizer Co. Ltd., China PR, Khimprom Public Joint Stock Company, Russia and Trade Representation of the Russian Federation in India, filed legal submissions.
- ix. Questionnaires were sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Anti-dumping Rules:
 - a. Vardhaman Trading Corporation
 - b. Harsh Kumar & Company
 - c. Hetero Labs ltd
 - d. Dr. Reddy's Laboratories Ltd
 - e. Aurobindo Pharma Ltd
 - f. Covalent Laboratories Ltd
 - g. Ranbaxy Laboratories Ltd
 - h. Ralchem Limited
 - i. Morpean LABS
 - j. Surya Medicare Limited
 - k. Indsol Drugs Limited
 - l. Meghmani Organics Limited
 - m. United Phosphorus Limited
 - n. KDL Biotech Limited
 - o. Sun Pharmaceuticals Industries Limited
 - p. Rails India Limited
 - q. Alembic Limited
 - r. Hindustan Chemicals Industries

- x. M/s Aurobindo Pharma Ltd., Dr. Reddy's Laboratories Ltd, Sandeep Organics Pvt. Ltd. responded to the initiation notification by filing importer's questionnaire/submissions.
- xi. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- xii. Investigation was carried out for the period of investigation (POI) starting from October, 2013-September, 2014 (POI). The examination of trends, in the context of injury analysis, covered the period from 2011-12, 2012-13, 2013-14 and the POI.
- xiii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of the subject goods for the past three years, including the period of investigation. The transaction wise import data received from the DGCI&S has been relied upon by the Authority in this preliminary finding.
- xiv. The cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the applicant on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out in accordance with Annexure III of the anti dumping rules so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry.
- xv. The Authority, having regard to the Act and the AD Rules, recommended imposition of provisional Anti-Dumping duties concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries, vide its Preliminary Findings Notification No 14/33/2014-DGAD dated 30.10.2015. The recommendations made by the Designated Authority were accepted by the Ministry of Finance and interim duties were levied vide Notification No. 58/2015-Customs (ADD) dated 08.12.2015 for a period not exceeding six months (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of the notification in the Official Gazette.
- xvi. The Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 22.01.2016. The parties, which presented their views in the public hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally. The arguments made in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered.
- xvii. Verification of the information and data submitted by the domestic industry and the interested parties was carried out to the extent deemed necessary. In respect of the cooperative producers/exporters, the verification of their records was done on the table-study basis.
- xviii. A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which would have formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 17.03.2016. The post Disclosure Statement submissions received have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.
- xix. The submissions made by the interested parties considered relevant by the Authority have been addressed in the Final Findings Notification.
- xx. *** in this Final Findings Notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxi. The exchange rate adopted for the POI is 1 US \$ =Rs 61.65

PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Views of the Domestic Industry

4. The submissions made by domestic industry are as follows:
 - a) Methylene chloride is an organic compound with molecular formula CH_2Cl_2 . It is a colorless liquid with sweetish ether-like odor, and is used as a solvent predominantly. It is essentially non-flammable under most conditions of use but can burn if strongly heated.
 - b) There are no known grades of the subject goods. However, it can be traded in loose (in tankers) or packed form (in drums), thereby, having direct effect on prices.

- c) Methylene Chloride is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under customs subheading 29031200. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
- d) There is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods. Injury margin and dumping margin has been calculated for loose/unpacked and packed product separately.

Views of the other interested parties

5. None of the exporters, importers or consumers has offered any views with regard to the product under consideration.

Examination of the Authority

6. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Methylene Chloride” also known as “Dichloromethane” and “Methylene Dichloride” (MDC) originating in or exported from China PR and Russia.
7. Methylene chloride is an organic compound with molecular formula CH_2Cl_2 . It is a colorless liquid with sweetish ether-like odor, and is used as a solvent predominantly. It is essentially non-flammable under most conditions of use but can burn if strongly heated. Methylene Chloride may decompose at high temperatures forming toxic gases. It is completely miscible with a variety of solvents. MDC is a solvent and is used in the manufacturing of polycarbonate and phenolic resins, rayon yarn, pharmaceuticals, agro and fragrance. It is also used as an extractant for edible fats, cocoa, butter and essences.
8. There are two technologies for production of Methylene Chloride - Methane route and Methanol route. The product produced through the two routes has essentially similar technical specifications. Methylene Chloride is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under customs subheading 29031200. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
9. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules provides as under:

“like article” means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.”

10. After considering the information on record, the Authority has determined that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods. The consumers are using the two interchangeably.

DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

11. Rule 2(b) of the AD Rules defines domestic industry as under: -

“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”

12. The Application has been jointly filed by M/s. Chemplast Sanmar Ltd. and M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd. According to the application, there are two other producers, namely, Gujarat Alkalies & Chemicals Limited and SRF Ltd. The Authority notes that production of the petitioners constitutes almost 68% of the Indian productions and, therefore, the production by the petitioners constitutes a major proportion in the total production of the like product produced in India. It is further stated in the application that none of petitioners has

imported the product under consideration, nor they are related to an importer or exporter of the product under consideration.

13. On the basis of information on record and having regard to the Rules, the Authority determines that the application has been made by or on behalf of the domestic industry and the application satisfies the requirement of 'standing' under Rule 5 of the AD Rules. Further, the production of the petitioning companies constitutes a major proportion in Indian production and the petitioner companies are eligible domestic industry. The petitioners, therefore, constitute 'Domestic Industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

View of the Importers/consumers and other interested parties

14. After the initiation, no interested party except M/s Shandong Liancheng Luxi Sixth Chemical Fertilizer Co. Ltd, China PR and Khimprom Public Joint Stock Company, Russia has made any submissions. Submissions made by them are as follows:
- The imports from EU, Korea and USA are as high as 77% in the POI. It is submitted that the injury to the domestic industry is due to imports from the said countries and not from the subject countries in the current POI.
 - The imports from the countries attracting anti dumping duty (ADD) are about 80% in the POI and the share of imports from Russia is de-minimis, i.e., nearly 2.94%.
 - The complete import data has not been provided by the domestic industry. Import data up to June 2014 is provided and no import data for the period of July 2014-September 2014 has been provided. In the absence of complete import data, claim of domestic industry with regard to export price and dumping margin fails.
 - The domestic industry has utilized import data of two different sources for the investigation, i.e., DGCI&S data and Tips Software Services Pvt. Ltd. whereas in the previous investigation for the same product from different countries, domestic industry has utilized import data of only one source, i.e., DGCI&S.
 - Application fails to meet the test of accuracy and adequacy in terms of evidence and information. Evidence of dumping, injury, where applicable, and a causal link between the dumped imports and the alleged injury should be provided.
 - Majority of imports into India are under duty free schemes which are not subject to anti dumping duty. So such imports are required to be excluded.
 - The price undercutting of Russia is shown higher as compared to price undercutting of China whereas the landed value for China is higher than that of Russia. It indicates that the price undercutting is taken artificially.

Examination by Authority

15. The submissions made by the interested parties have been analyzed by the Authority as follows:

- With regard to the argument that import from Russia is de-minimis, the Authority notes that at the time of initiation of current investigation the share of Russian imports was 3.40%. The Authority has now adopted DGCI&S transaction wise data for the purpose of determining volume and value of imports for the present investigation. It is noted that the share of imports from Russia is above de-minimis (4.44%).
- With regard to the argument that imports from countries attracting ADD hold major share in imports and are causing injury, it is noted that the imports from countries attracting anti dumping duty declined whereas imports from the subject countries have increased significantly over the injury period. It is noted that dumping margin and injury margin determined for the subject goods from the subject countries is significantly positive showing that dumped imports from the subject countries are causing injury to the domestic industry.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Subject Countries	MT	16,514	334	6,757	15,629

Countries attracting ADD	MT	60,974	56,324	62,444	47,571
Other Countries	MT	6,956	279	484	540
Total Imports	MT	84,444	56,936	69,685	63,739

- c. With regard to the argument that domestic industry has adopted import data of two different sources for the petition, i.e., DGCIS data and Tips Software Services Pvt. Ltd, the Authority notes that at the stage of initiation, the Authority is required to satisfy itself that there is sufficient evidence to justify initiation of investigations and the domestic industry used DGCIS data upto the period for which it was available with them at that stage. However, presently, the DGCIS transaction wise data has become available and the Authority has procured DGCIS transaction wise data and the analysis for the purpose of the present determination has been made on the DGCIS data.
 - d. With regard to the argument that majority of imports into India are under advance license and, therefore, should be excluded, the Authority notes that imports made under duty exemption scheme create competition and change the price line as the importers would procure the goods from foreign exporters or domestic producers whosoever gives them the competitive price. Therefore, the imports made under duty exemption scheme cannot be considered not to have affected the price in the market and, therefore, cannot be excluded while determining imports.
16. The product under consideration is produced and supplied in two forms - (a) bulk shipments in loose form and (b) packed shipments. The Authority has determined separate normal value and export price of loose/unpacked imports and packed imports. Dumping margin has been determined on the basis of Weighted Average.

POST ORAL HEARING COMMENTS OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND THE OPPOSING INTERESTED PARTIES

17. The post oral hearing comments of the opposing interested parties are as under:

- i. Non-acceptance of the information of the exporter and denial of the individual treatment to them in the current investigation has been made without appreciation of the law concerning the determination of the export price and the relevant anti-dumping provisions.
- ii. Some of the exporters were granted adverse treatment without seeking clarifications for their exports through the unrelated traders keeping in view the principles of natural justice and due process rights of the interested parties as contemplated under Article 6.1 of WTO ADA.
- iii. The exporters provided complete information in their response for sales to India through related trader as well as through unrelated traders. The exporters are not in a position to appreciate the meaning of 'complete value chain' as there is no such concept known in the anti-dumping law. The words used in the anti-dumping law are the necessary information or the information reasonably available. The use of the words necessary information or reasonably available information cannot be substituted with the words 'complete information'.
- iv. It may be seen that there is nothing in the Customs Tariff Act, 1975 as well as in the Anti-dumping Rules which provide for the rejection of the export price for the determination of dumping margin and denial of individual treatment on the ground of non-providing of the information of unrelated traders.
- v. It is sufficient if the exporter has provided the necessary information as is reasonably available with him and that it cannot be forced and put under undue burden to provide the information which is not under his control.
- vi. In case the non-related traders do not provide their information/response, the export price for the exporter can reasonably be determined by considering the price at which the goods have been billed to traders as this information is readily available with the exporter/producer as has been done by EC in various cases before it.
- vii. In this connection, we would also like to draw the kind attention of the Authority to the *WTO Appellate Body Report in US-Anti-dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan (WT/184/ABR) dated 24th July 2001* wherein it was held that the investigating authorities cannot insist

upon the absolute standards or impose unreasonable burdens upon the exporters with respect to the information which is not under their control.

- viii. Without prejudice, Luxi has culled out the details of the exports made through non-related traders from the IBIS import data and have been placed on record. The same clearly indicates the assessable values or the final prices at which the goods have been exported to India made through the non-related traders. Luxi has also obtained the copies of the commercial invoices along with the packing lists etc. from Vinmar International Ltd., Cosmos VU Ltd. and Tricon Energy Ltd. and the same have also been placed on record. Tricon Dry Chemicals, LLC, USA, has also filed its responses with the Designated Authority. Now complete response of all the exporters has been filed.
- ix. The Authority may kindly seek the reasons / clarifications from DGCI&S for the lower imports in their data base than IBIS imports as has been done in the case of PTA from China, EU, Korea & Thailand (Case No. 14/7/2013-DGAD) [Para 20(xvii)]. It is hard to believe that the import data as per the DGCI&S would be lower than the import data reported in IBIS. Luxi would, therefore, request the Authority for the complete analysis of the import data in the current case in the interest of justice and fair play. A copy of the DGCI&S transaction-wise import data may also be provided to Luxi for comments
- x. It is important to submit that the transaction-wise import details from DGCI&S are not available to private parties. Interestingly, the domestic industry has used the DGCI&S transaction-wise import data for the period April 11-March 12 for their anti-dumping application. However, the domestic industry has not provided any submissions on record for getting the DGCI&S transaction-wise import data. In case the Authority has provided the DGCI&S transaction-wise data to the domestic industry, the same cannot be kept as confidential from Luxi and the transaction-wise import data from DGCI&S used for the preliminary findings is required to be disclosed to Luxi in view of the principles of equality and fairness. Similarly, the transaction-wise import data used by the domestic industry from Tips Software may also be provided in all fairness to enable us to make comments.
- xi. It is submitted that the submissions with regard to accuracy and adequacy have not been included in the preliminary findings and have also not been addressed in the preliminary findings.
- xii. The application filed by the domestic industry is deficient as it lacks the evidence and the information required under the law to be considered as a valid and fully documented application. In terms of Rule 5(3) of the Anti-dumping Rules, the Authority is obligated not to initiate an anti-dumping investigation unless (a) it determines that the application has been made by or on behalf of the domestic industry and (b) it examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies itself that there is sufficient evidence regarding dumping, injury and causal link to justify initiation. The determinations that the application has been made by or on behalf of the domestic industry producing the like product and there is dumping, injury and causal link are the conditions precedent which ought to be fulfilled prior to the initiation of the investigation.
- xiii. It is submitted that the domestic industry has kept lots of information as confidential without providing any legitimate reasons and in violation of the Rules and detailed procedure laid down by the Authority. The domestic industry has not provided a copy (soft copy/hard copy) of the raw/original transaction-wise import data obtained by them from Tips Software Services Ltd. & DGCI&S along with the application nor they have indicated that the same has been provided to the Authority. It is also not there in the public file. Soft copy in excel file of transaction-wise sorted import data, raw/original import data and list of excluded transactions from Tips Software Services Ltd. & DGCI&S: The domestic industry has not provided a soft copy in excel file of the transaction-wise sorted import data along with the original/raw import data obtained from Tips Software Services Ltd. & DGCI&S that has been used for the application for the POI (October 13 to September 2014) and previous three years. The company-wise production details have been kept as confidential. Details of adjustments such as ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, inland freight, VAT etc. claimed from export price are also claimed as confidential. The details of Price undercutting and price underselling for China in percentage terms have not been disclosed and the same have been provided only in ranges. Profit / loss and ROCE in percentage terms have not been disclosed.

- xiv. It is submitted that the domestic industry has not provided the complete import data for the whole period of investigation. It is a serious lapse on the part of the domestic industry and clearly indicates that the application of the domestic industry fails to meet the test of accuracy and adequacy on this ground alone.
- xv. Without prejudice, it is submitted that the import data for the application has been utilized from two different sources, i.e., DGCI&S import data for the period April 2011 to March 2012 and the import data from Tips Software Services Pvt. Ltd. for the periods from April 12-March 13, April 13-March 14 and April 14 to June 2014. However, the domestic industry has not provided any reasons on record for using the import data in such a manner and why the import data from a single source was not used. Correctness of Sorted Import data cannot be verified.
- xvi. It may also be seen that the domestic industry has made claims on separate analysis for bulk and packed product. However, from a PDF copy of the import data provided, Luxi cannot identify this aspect from the hard copy of the import data so provided as part of the application. The complete description for each import transaction is not visible as the same has been concealed by the domestic industry.
- xvii. After analysis of the import data, it is noted that the values in both USD and Indian Rupees have been considered after mixing them up by the domestic industry which would lead to incorrect and misleading analysis of the import prices and the consequent injury to the domestic industry.
- xviii. It may be seen that admittedly there are significant and substantial imports from the other countries which are as high as 77% in the period of investigation. It indicates that the injury to the domestic industry is due to the imports from the other countries but not from the subject countries in the current investigation.
- xix. It is submitted that the majority of the imports into India are under duty free schemes such as advance license run by the Government of India which are not subject to any anti-dumping duty. The Hon'ble CESTAT in case of Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. Vs. DA held that the goods imported under advance license are exclusively for export products and hence, such imports cannot be said to have entered in the Indian market. Therefore, when the imports under duty free schemes do not enter the Indian market the same cannot be considered and be made subject to the anti-dumping investigation and that those imports are required to be excluded for a fair & just analysis of the impact of the imports on the domestic industry and conclusions in the current investigation.
- xx. With regard to determination of normal value for China, it may be seen that in terms of the provisions of this paragraph, the Authority is required to first identify the market economy third country for determination of normal value and only where it is not possible to obtain necessary data from such third country, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. However, the mandatory procedure prescribed by law in the present case has not been followed as the interested parties have not been put to notice about selection of the third country nor the interested parties have been requested to suggest and make necessary information available about the third country. Thus, in the absence of following the mandatory procedure, the present proceedings cannot continue and have become incurable in view of the decision of the Hon'ble Supreme Court in the case of Shenyang Matsushita 2005 (181) ELT 320 (SC) which is directly on the issue.
- xxi. The analysis of various injury parameters has been made from the year 2012-13 but not from the base year 2011-12. The analysis of injury parameters is to be made from starting point to the end point over the injury investigation period. The comparison of POI figures with that of year 2012-13 has made the information for the year 2011-12 meaningless. Further, the domestic industry has not justified making injury analysis in such a manner.
- xxii. It is submitted that the domestic selling price details provided in proforma IVA and proforma IVB for both the subject countries, proforma IVB for China and proforma IVB for Russia are at variance. Further, the price undercutting for Russia was shown higher as compared to price undercutting for China whereas the landed value for China was higher than the landed value for Russia. It clearly indicates that the price undercutting has been artificially created in the current case whereas the same does not exist.

- xxiii. Without prejudice to the submissions above, it is submitted that the domestic industry has not suffered injury in the current case based on the injury information in their application as well as on the basis of the injury information contained in the preliminary findings. The imports from subject countries in absolute terms have declined over the injury investigation period and also in comparison to domestic production and total demand in India. The market share of the domestic industry over the injury investigation period has increased from 34% in the base year to 43% in the POI indicating no injury. The capacity, production, capacity utilisation and sales values as well as sales prices all have increased over the injury investigation period indicating there is no injury with respect to these factors. There is no price undercutting for China as may be seen from the details provided in the preliminary findings. Thus, there is no injury to the domestic industry with respect to this factor. There is no price depression and suppression for the Domestic industry. Although there is a decline in these factors over the injury investigation period, there is a significant improvement in these factors in the POI as compared to previous year 2012-13 indicating that the injury to the domestic industry is not due to imports from the subject countries but due to imports from other countries which are quite significant at about 80%. Various performance parameters of the domestic industry have improved over the injury investigation period indicating that the growth of the domestic industry and its ability to raise capital investments is not affected. There is no causal link between the alleged dumped imports from the subject countries and injury to the domestic industry as imports from Russia are de minimis, there are significant imports from EU, USA and Korea. The imports from subject countries in absolute terms as well as a share of total demand and domestic production have declined over the injury investigation period. On the other hand sales, production and market share of the domestic industry have increased significantly. It indicates that the imports from subject countries have no bearing on the state of the domestic industry and no injury is caused to the domestic industry from imports from the subject countries. It is submitted that the import prices from the subject countries have declined by 9% over the injury investigation period whereas on the other hand the domestic prices have increased by 7% over the injury investigation period. Thus, the import prices have no bearing on the domestic prices.
- xxiv. PJSC Khimprom believes that the Application against Russian Federation shall be terminated in accordance the WTO Agreement. In the present investigation data regarding the amount of total import of the Product in India and import from Russia during POI has a very important meaning because their accuracy is the first and main basis for conclusion if it was dumping or not. IBIS data presented in submission given by M/s Shandon Liaocheng Luxi Sixth Fertilizer Co., Ltd and M/s Lu Xi Chemical (Hong Kong) Co., Limited shows that volume of import from Russia in every previous period before POI and during POI itself doesn't exceed 3 % of the volume of total import.
- xxv. PJSC Khimprom submits that among all the possible comparable periods like 2013-2014/2014-2015/2015-2016 Indian year (in respect of import of the Product from Russia to India) or 2013-2014/2014-2015 Russian year (in respect of export of the Product from Russia to India), there is no period when the amount of the Product is above the negligible level.
- xxvi. PJSC Khimprom submits that the amount of the Russian Product which was imported to India during 2015 Russian year (1 296 tons) is less than during 2014 (2 054 tons). The fact that the interim anti-dumping duty was imposed during 2015 cannot affect the volume of import because it was imposed only in November, 2015. At the same time, the amount of total import of the Product in India has increased (from 66,7 MT at 2014-2015 Indian year to 74,4 MT in 2015-2016 Indian year which now has not finished yet). It would be important to note the fact that Krimprom is the only producer of the Product in Russia (another manufacture Volgograd Khimprom stopped its activity forever because of the bankruptcy in December, 2014) and the amount of the export of the Product from Russia during 2015 is equal to the amount of Khimprom's export during the same period.
- xxvii. PJSC Khimprom submits that there is no evidence that potential import from Russia is going to be above the 3 % as well.
- xxviii. There are some specific contradictions in the import volume data regarding the recorded as Khimprom's drums transaction. Khimpom exports from Russian to India only product in drums (Standard volume of 1 drum is 0,27mt). This volume is unchangeable, i.e., it's impossible to put in drum more or less than 0.27mt of the product because of technical reason. All the transport documents for export and certificates

of quality also demonstrate and confirm that net amount of the product, which is exported, is always 0.27 mt.-fold. It's impossible and senseless that somewhere during transportation any drum could be divided or re-taring. It means that when any consignment of the product comes to Indian customs border where it's recorded for DGCI&S and other database, its weight should always be 0.27 t.-fold. But in the Application there are many transactions (from both DGCI&S and Tips Software Services Pvt. Ltd database) which do not weigh 0.27 mt.-fold.

- xxix. Denial of determination the individual dumping margin for Khimprom contradicts the Law. The Preliminary Finding) says that the company Khimprom has not filed complete response to questionnaire and that in the absence of complete value chain from the subject exporters, the Authority has provisionally constructed the normal value for Russia on the basis of the cost of production in India, duly adjusted. In this connection it is objected that there is nothing in the applicable legislation regarding existence of such a procedure which gives to the Authority right to calculate the normal value on the basis of the cost of domestic production under any circumstances. Moreover, the Authority has obligation to determine individual dumping margin for each known exporter or producer as per Custom Tariff Act and the Anti Dumping Rule. There aren't any faults from Khimprom side regarding providing information during the present investigation. All the information, which is in possession of Khimprom and available for Khimprom, had been provided for the Authority. Khimprom does not have information regarding complete value chain because of nature of the relationship between Khimprom and its unrelated traders.
- xxx. Considering the above, Khimprom requests the Authority to give a full assessment of Khimprom's objections, consider it on the merits and terminate the investigation in relation to Russian Federation.

18. The post oral hearing comments of the domestic industry are as under:

- i. Significant imports from the subject countries currently attracting anti dumping duty led to imposition of anti dumping duties. With imposition of anti dumping duties on other countries, the imports from subject countries have increased by 65% in 2014-15. Further, these imports are at significantly dumped prices.
- ii. In a case where dumping has shifted to new sources after imposition of anti dumping duty on other sources, it is most logical that the situation of domestic industry would show some improvement. The EC Regulation specifically considers the fact that an industry is still in progress of recovering from the effect of past dumping as a factor showing injury. Thus, the fact that of domestic industry is recovering, in fact, shows the impact of dumping on the domestic industry.
- iii. Trends are analysed for all the four years, just not from the base year and the POI and that of the previous year. The purpose of an anti-dumping investigation is to evaluate the effect of the dumped imports on the situation of the domestic industry over the injury period. The POI can be described as "injurious, which is the period for which the existence of dumping is examined, having regard to its performance in the past.
- iv. Normal Value cannot be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available. The petitioners have not been able to procure such information from a producer in market economy third country. Accordingly, petitioners have determined normal value on the basis of cost of production in India, duly adjusted with selling, general and administrative expenses and considering the consumption norms of the petitioner.
- v. Efforts were made to get evidence of price of product under consideration in the domestic market of Russia. Efforts have also been made to get any evidence of price from published sources. However, the petitioners have not been able to get any information/evidence of price of subject goods in the domestic market of Russia for the reason that the relevant information is not in public domain information and have, therefore, constructed the normal value.
- vi. In view of significant difference in the costs and prices of loose/unpacked and packed material, the normal value has been determined separately for the two.
- vii. Response from these responses should not be accepted at such belated stage. Anti Dumping Agreement require investigating authority to provide sufficient opportunities to the interested parties to defend their

- interests. However, such investigations being a time bound investigation; these opportunities are available only if these are availed in a timely manner
- viii. The Authority also can reject the questionnaire response if the same is not filed within the time limits prescribed as has been done in the case of Ceramic Tiles.
 - ix. The responses submitted by the other interested parties are in utter disregard of the standards laid down under the law. The responses, besides being inadequate and insufficient in terms of information, also do not meet the set proforma prescribed by the Authority.
 - x. Information such as sales of subject goods in the home market and exports to India, list of all raw materials used, Information on installed capacity, production, stocks and sale etc have been claimed confidential. Thus, the Designated Authority may kindly disregard the response of the exporter and declare them as non-cooperative by denial of individual treatment.
 - xi. The petitioners have determined weighted average dumping margin which is above de minimis and is significant.
 - xii. Imports of the product under consideration from the subject countries declined in 2012-13 and thereafter increased consistently.
 - xiii. Imports in relation to production and consumption in India declined in 2012-13 and has thereafter increased consistently.
 - xiv. Market share of the subject countries declined in 2012-13 and consistently increased thereafter and is significant in the POI. Market share of the domestic industry has increased in the POI marginally from the previous year as a result of imposition of anti dumping duties and market share of countries already attracting ADD has declined.
 - xv. Imported goods have been undercutting the prices of the domestic industry in both loose and packed form. Price undercutting in respect of the product under consideration as a whole is positive from the subject countries.
 - xvi. Landed price of imports in packed form has remained significantly below the level of cost of sales and selling price since 2012-13. Landed price of imports in loose form was lower than the cost and selling price in 2012-13 and has remained almost at the level of costs in the POI. Majority of imports into the country from subject countries are in packed form which is causing significant price suppression in the domestic market.
 - xvii. Subject imports declined in 2012-13 and have thereafter increased. Imports are significant in relation to production and consumption in India.
 - xviii. Dumped imports are suppressing the prices of the domestic industry in the market causing financial losses.
 - xix. Performance of the domestic industry has steeply deteriorated in terms of profits, return on investments and cash profits to a very significant extent.
 - xx. Even though performance of the domestic industry improved in terms of production, domestic sales, capacity utilization, market share, the same was because of decision of the domestic industry to continue production and significant demand for the product under consideration in the Country. In any case, despite improvement in these parameters, profits, return on investments and cash profits declined very severely whereas these should have improved as a result of improvement in volume parameters.
 - xxi. The imports prices are much below the level of cost of production of the domestic industry.
 - xxii. As a result of significant price difference, the performance of the domestic industry has deteriorated in terms of profits, cash profits (cash flows) and return on investments. Thus, the deterioration in performance of the domestic industry is due to dumping of the product in the Country.
 - xxiii. Deterioration in profits, cash flow, return on capital employed are as a result of dumped imports;
 - xxiv. Growth of the domestic industry became negative in respect of price parameters.

- xxv. Imports from countries attracting anti-dumping duty declined whereas imports from the subject countries have increased significantly over the injury period.
- xxvi. The dumping margin and injury margin determined for the subject goods from the subject countries is significantly positive showing that dumped imports from the subject countries are causing injury to the domestic industry.
- xxvii. Domestic Industry has claimed price injury and not volume injury. Petitioners can sell the product so long as the Petitioners are realigning the prices of domestic industry to imports. Further, realigning the prices of domestic industry to imports is the compulsion of the domestic industry.
- xxviii. Volume parameters are under the control of the domestic industry and domestic industry on its part is doing its best to produce and sell maximum volumes so that its fixed costs get observed over larger production. However, the selling price of the product is beyond the control of the domestic industry and is directly dependent on the imports.
- xxix. Domestic industry has calculated price undercutting on the weighted average basis. Petitioners have determined price undercutting by considering month by month comparison, which clearly shows positive price undercutting by the Chinese imports. The imported goods have been undercutting the prices of the domestic industry in both loose and packed form. Price undercutting in respect of the product under consideration as a whole is positive from the subject countries.
- xxx. EU law specifically consider "the fact that the domestic industry is in the process of recovering from the past ill effect of dumping" as one of the parameters showing injury; the WTO Agreement recognises that the list is not exhaustive and the Indian Rules contain an inclusive definition, which implies existence of some other conditions. It is thus evident that the partial recovering from the past effects of dumping does not mean that the domestic industry is no longer suffering injury.
- xxxi. The information of opening and closing stock of an industry is confidential. It is contended, the Authority calculate inventory on average basis. Petitioners have claimed adverse price effect of imports on the domestic industry.

Examination of the Authority of the post oral hearing comments of the domestic industry and the opposing interested parties

19. The Authority notes that most of the post Public Hearing submissions made by the domestic industry and the opposing interested parties are repetitive in nature and have already been dealt with in the Preliminary Final Findings Notification. However, the examination of the Authority of the relevant post oral hearing comments of the domestic industry and the opposing interested parties is as under:
 - i. It has been contended by the interested parties that the authority should not have rejected questionnaire responses of the producers on the ground that full information on exports to India was not available. The interested parties have stressed that the requirement under the law is necessary information and as is reasonably available to the producers. It has also been contended that the authority could consider the price at which the goods have been billed by such producers onto the unrelated exporters. Reference has also been made to the WTO decision with regard to standards that the Authority should lay down and the obligations of the interested parties for providing necessary information. Some of the interested parties have, after issuance of preliminary findings, correlated their exports to India with the Indian customs data and have submitted that the same establishes that their claims with regard to export price were reliable. The Authority notes in this regard that the margin of dumping under the law is the difference between normal value and export price. Therefore, for correct determination of dumping margin, both normal value and export price are required to be accurately determined. The Authority notes that the export price cannot be accurately and adequately determined unless the questionnaire response of the company who has invoiced the goods to India is on record and such company cooperates with the Authority. Admittedly, all associated expenses for exports to India have not been incurred by such producers in cases where the exporter is involved in invoicing the goods. Some of the expenses for exports to India have been incurred by such exporters. Further, the price at which the producer sells to the exporter in such cases is not the price at which the goods have been sold for export to India. The Authority also notes that dumping occurs when an article is introduced into the commerce of India at a price less than its normal value. Therefore, the price at

which the goods have been invoiced onto Indian customer/ importer is vital for determination of export price. In any case, now that the questionnaire responses have been filed by those exporters who have supplied product under consideration originating in China, the Authority has determined individual dumping margin for all the Chinese producers. As far as Khimprom is concerned, the Authority re-iterates that inspite of giving opportunity to Khimprom, the company has not submitted any response of the above mentioned exports/traders claiming that all the information which is in possession of Khimprom and available for Khimprom, had been provided for the Authority and that Khimprom does not have information regarding complete value chain because of nature of the relationship between Khimprom and its unrelated traders. In this regard, the Authority notes that since 100% of the subject goods produced by Khimprom have been exported to India by the above mentioned exporters, Khimprom cannot claim that it has no relationship with them and cannot ask these companies to file the responses to complete the value chain as has been done by other cooperative Chinese producers in this investigation. In the absence of completion of the value chain the Authority does not determines the individual dumping margin for Khimprom.

- ii. As far as the reasons/clarifications for the lower imports in the DGCI&S data base than IBIS imports and further that the domestic industry has adopted import data of two different sources for the petition, the Authority re-iterates that at the stage of initiation, the Authority is required to satisfy itself that there is sufficient evidence to justify initiation of investigations and the domestic industry used DGCI&S data upto the period for which it was available with them at that stage. However, presently, the DGCI&S transaction wise data has become available and the Authority has procured DGCI&S transaction wise data and the analysis for the purpose of the present determination has been made on the DGCIS data. As regards adoption of two sources at the stage of initiation, the Authority notes that the domestic industry is justified in adopting best available information at the stage of initiation. Information for the complete period was not made available by the DGCI&S by the time of initiation and, therefore, the domestic industry was justified in adopting the secondary source data for the subsequent period. However, the Authority has procured DGCI&S transaction wise data and the analysis for the purpose of the preliminary findings and the present determination has been made on the DGCI&S data.
- iii. As far as the argument that DGCI&S data used by the domestic industry was not made available to the interested parties, the Authority notes that the same was placed in the public file and thus was available to all the interested parties for verification.
- iv. As far as the argument that the application filed by the domestic industry is deficient as it lacked the evidence and the information required under the law and that the Authority was obligated not to initiate an anti-dumping investigation unless (a) it determines that the application has been made by or on behalf of the domestic industry and (b) it examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies itself that there is sufficient evidence regarding dumping, injury and causal link to justify initiation, the Authority notes that it had initiated the investigation only after satisfying itself of the prima facie evidence of dumping and injury and causal link thereof. The Authority notes that even at the present stage of investigation, the Authority finds that there is sufficient evidence that dumping margins in respect of the responding producers/exporters is significant and the dumped imports are causing injury to the domestic industry.
- v. As far as the argument of the domestic industry and the opposing interested parties that lots of information has been kept as confidential without providing any legitimate reasons and in violation of the Rules and detailed procedure laid down by the Authority in this regard, the Authority notes that the information provided by of the domestic industry and the opposing interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.
- vi. As far as the argument that the import data for the application has been utilized from two different sources,

i.e., DGCI&S import data for the period April 2011 to March 2012 and the import data from Tips Software Services Pvt. Ltd. for the periods from April 12-March 13, April 13-March 14 and April 14 to June 2014, the Authority notes that the Authority has procured DGCI&S transaction wise data and the analysis for the purpose of the present determination has been made on the DGCIS data.

- vii. As far as the argument that there are significant and substantial imports from the other countries which are as high as 77% in the period of investigation and that it indicates that the injury to the domestic industry is due to the imports from the other countries but not from the subject countries in the current investigation, the Authority notes that the imports from the subject countries have actually increased significantly in the POI and these imports are at significantly dumped prices. As regards the argument from Russian exporter, the Authority notes that the volume of imports from Russia is more than negligible limits under the Rules.
- viii. Regarding the argument that the majority of the imports into India are under duty free schemes which are not subject to any anti-dumping duty and when the imports under duty free schemes do not enter the Indian market, the same cannot be considered and be made subject to the anti-dumping investigation, the Authority notes that the imports made under duty exemption scheme create competition and change the price line as the importers would procure the goods from foreign exporters or domestic producers whosoever gives them the competitive price. Therefore, the imports made under duty exemption scheme cannot be considered not to have affected the price in the market and, therefore, cannot be excluded while determining imports.
- ix. Regarding the argument that with regard to determination of the normal value for China, the Authority is required to first identify the market economy third country for determination of normal value and only where it is not possible to obtain necessary data from such third country, on any other reasonable basis, The Authority notes that the Normal Value could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available. Further, neither the responding producers from China PR have claimed market economy treatment nor have sought to rebut the non-market economy presumption. In a situation where none of the Chinese companies has claimed market economy treatment, the Designated Authority does not see any merit in the claim that the Authority should have firstly identify the market economy third country for determination of normal value for these Chinese producers/exporters.
- x. Regarding the argument that the analysis of various injury parameters has been made from the year 2012-13 but not from the base year 2011-12 and that the analysis of injury parameters is to be made from starting point to the end point over the injury investigation period, the Authority notes that it has analysed the trends for all the four years, just not from the base year and the POI and that of the previous year.
- xi. Regarding the argument that the domestic selling price details provided in proforma IVA and proforma IVB for both the subject countries, proforma IVB for China and proforma IVB for Russia are at variance and further that the price undercutting for Russia was shown higher as compared to price undercutting for China whereas the landed value for China was higher than the landed value for Russia, indicating that the price undercutting has been artificially created by the domestic industry in the current case whereas the same does not exist, the Authority notes that the domestic industry in perform IVB of the petition compared the selling price with the landed price on month to month basis for both the subject countries separately whereas in proforma IVA, the weighted average selling price of the domestic industry for the POI period has been taken. Therefore, the two could match. However, while issuing the preliminary findings, the Authority considered weighted average selling price for the POI. As regards different degree of price undercutting between Russia and China, the Authority notes that the different degree of price undercutting from different countries does not imply that the country with lower price undercutting has not caused injury.
- xii. Regarding the argument that the domestic industry has not suffered injury in the current case based on the injury information in their application as well as on the basis of the injury information contained in the preliminary findings, the Authority notes that after examining the volume and price effects of imports of the subject goods from the subject countries and its impact on the domestic industry, it is noted that volume of imports of subject goods from subject countries declined in 2012-13 and thereafter increased significantly in absolute terms and in relation to production and consumption in India. The domestic

industry has not suffered volume injury on account of dumped imports of subject goods from the subject countries. However, with regard to price effect on account of imports of the subject goods from the subject countries, it is noted that imports of the subject goods from subject countries are significantly undercutting the prices of domestic industry. Further, the domestic industry has suffered price suppression on account of imports of the subject goods from the subject countries in the POI. Profit, cash flow and return on investment remain negative. Despite imposition of anti dumping duty on other countries, the domestic industry is incurring losses in the POI because of the presence of dumped imports from the subject countries. With regard to consequent impact of the dumped imports on the domestic industry, it is concluded that even though the performance of the domestic industry has improved in respect of production, capacity utilization, domestic sales, market share, the performance deteriorated in terms of profits, return on investment and cash flows. Thus, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

- xiii. Regarding the argument of PJSC Khimprom that the application against Russian Federation shall be terminated in accordance the WTO Agreement and that in the present investigation data regarding the amount of total import of the Product in India and import from Russia during POI shows that volume of import from Russia in every previous period before the POI and during the POI itself does not exceed 3 % of the volume of total import, and further that there is no evidence that potential import from Russia is going to be above the 3 % as well, the Authority notes that at the time of initiation of current investigation, the share of Russian imports was 3.40%. The Authority has now adopted DGCI&S transaction wise data for the purpose of determining volume and value of imports for the present investigation and it is noted that the share of imports from Russia is above de-minimis (4.44%).
- xiv. As regards the argument that the domestic industry has made claims on separate analysis for bulk and packed product but from a PDF copy of the import data provided, Luxi could not identify this aspect from the hard copy of the import data so provided as part of the application, and further that after analysis of the import data, the values in both USD and Indian Rupees have been considered after mixing them up by the domestic industry which would lead to incorrect and misleading analysis of the import prices and the consequent injury to the domestic industry, the Authority notes that the argument relates to the secondary import data relied upon by the domestic industry in the petition whereas the Authority has issued the preliminary findings based on the DGCI&S import data and not the secondary data provided by the domestic industry in the petition. As regards the possible mixing of imports reported in US\$ and INR, it is clarified that the Authority has considered data in only one unit of measurement. The exporters' data is in US\$ and the same has been adopted, whereas the Indian data is in INR and the same has been considered. There is no mixing of the data either in the preliminary findings or in the present disclosure statement.
- xv. Regarding the argument that there are some specific contradictions in the import volume data regarding Khimprom's drums transaction in the sense that whereas its weight should always be 0.27 mt.-fold for technical reasons, but in the application there are many transactions (from both DGCI&S and Tips Software Services Pvt. Ltd database) which do not weigh 0.27 mt.-fold, the Authority notes that it has relied upon the transaction wise data of DGCI&S as it was provided.

ASSESSMENT OF DUMPING – METHODOLOGY AND PARAMETERS

Normal Value, Export Price and Dumping Margin

Market Economy Treatment (MET) Examination for all producers and exporters from China PR

- 20. The Authority notes that in the past three years, China PR has been treated as non-market economy country in the anti-dumping investigations by other WTO Members. Therefore, in terms of Para 8 (2) of the annexure 1 of AD rules, China PR is to be treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules for the purposes of preliminary determination.
- 21. As per Paragraph 8 of the Annexure I to the Anti Dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and establish to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from China are required to furnish

necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:-

- i. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
 - ii. The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
 - iii. Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms; and
 - iv. The exchange rate conversions are carried out at the market rate.
22. The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. However, barring below mentioned producers and exporters from China PR, none of the producer/exporter from China PR has co-operated in this investigation by filing their Questionnaires' responses. The questionnaire response has been filed by the following companies:
- i. Shandong Liaocheng Luxi Sixth Chemical Fertilizer Co. Ltd., China PR
 - ii. Lu Xi Chemical (Hong Kong) Co.Ltd., Hong Kong (Exporter)
 - iii. Shandong Dongyue Fluo-Silicon Materials Co. Ltd., China PR
 - iv. Ningbo Juhua Chemical & Science Co. Ltd., China PR
 - v. Zhejiang Quhua Flour-Chemistry Co. Ltd., China PR
 - vi. Farmasino Holding (HK) Limited, Hong Kong (Exporter)
 - vii. HK Montage International Holding Limited, Hong Kong (Exporter)
 - viii. Tricon Energy Ltd, USA
 - ix. Tricon Dry Chemicals LLC, USA
23. It is noted that neither of the above mentioned producers has claimed market economy treatment nor has not sought to rebut the non-market economy presumption. Since none of the Chinese companies has claimed market economy treatment, the Designated Authority has not determined whether any of the Chinese producers could be granted market economy treatment.

Normal Value in China

24. As none of Chinese producers and exporters has submitted the questionnaires' responses; the Authority has constructed the Normal Value in China PR on the basis of Para-7 to Annexure-I to the AD Rules.
25. Para 7 of Annexure I of the AD Rules provides that:
- "In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation

shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments”.

26. According to these Rules, the normal value in China can be determined on any of the following basis:

- a) On the basis of the price in a market economy third country, or
- b) The constructed value in a market economy third country, or
- c) The price from such a third country to other countries, including India.
- d) If the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.

27. The Authority notes that for determination of the normal value based on the third country cost and prices, complete and exhaustive transaction-wise data on the domestic sales of third country export sales, as well as cost of production and cooperation of such producers in third country is required, which is not available with the Authority in the present investigation. Also, no such verifiable information with regard to prices and costs prevalent in other such market economy third countries have been provided either by the applicant or by the responding exporters, nor any publicly available information could be accessed, nor the responding Chinese companies have made any claim with regard to an appropriate market economy third country.

28. Considering that there has been no MET response from any exporter/producer of the subject goods from China PR and further noting that information/data regarding appropriate market economy third country for determination of normal value in China PR is not available on record; the Authority has considered the normal value in China PR on available ‘reasonable facts basis’, in terms of second proviso of para 7 of Annexure 1 to the AD Rules. Accordingly, the Authority has constructed the normal value for China PR on the basis of the cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses. Separate normal value has been determined for loose and packed form of the product in view of significant difference in packing costs. The constructed normal value determined for China PR is shown in the dumping margin table below.

Normal Value in Russia

29. The Authority sent questionnaires to the known exporters from Russia. The Authority has received response only from the producer Khimprom Public Joint Stock Company, Russia. The goods have been sold through its unrelated exporters/traders, namely, Avestra Chemical DMCC, UAE; Quest Group DMCC, UAE; Trigon Gulf, FZCO, UAE; Quest Point LLP, UK and Quest International Trading SA, Canada, to customers in India. The company has exported *** MT of MDC during the POI. It is seen from the questionnaire response that Avestra Chemical DMCC, UAE; Quest Group DMCC, UAE; Trigon Gulf, FZCO, UAE; Quest Point LLP, UK and Quest International Trading SA, Canada, have not filed their questionnaire response despite exporting ***% of the total exports of subject goods to India of the producer Khimprom Public Joint Stock Company, Russia. Since the value chain was not complete, the Authority, at the stage of the provisional findings, had not determined the individual dumping margin in respect of Khimprom Public Joint Stock Company, Russia.

30. The Authority notes that inspite of giving opportunity to Khimprom, the company has not submitted any response of the above mentioned exports/traders claiming that all the information which is in possession of Khimprom and available for Khimprom, had been provided for the Authority and that Khimprom does not have information regarding complete value chain because of nature of the relationship between Khimprom and its unrelated traders. In this regard, the Authority notes that since ***% of the subject goods produced by Khimprom have been exported to India by the above mentioned exporters, Khimprom cannot claim that it has no relationship with them and cannot ask these companies to file the responses to complete the value chain as has been done by other cooperative Chinese producers in this investigation. In the absence of completion of the value chain the Authority determines the normal value for Russia as a whole on the basis of the cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses

under Rules 6(8). Separate normal value has been determined for loose and packed form of the product in view of significant difference in packing costs. The constructed average normal value determined for Russia is shown in the dumping margin table below.

Export Price for China PR

Export Price for Shandong Liaocheng Luxi Sixth Chemical Fertilizer Co. Ltd., China PR (Producer) through Lu Xi Chemical (Hong Kong) Co.Ltd., Hong Kong (Exporter)

31. Shandong Liaocheng Luxi Sixth Chemical Fertilizer Co. Ltd. has reported export of the subject goods to India during the POI. The goods have been sold through its related exporter Lu Xi Chemical (Hong Kong) Co. Ltd., Hong Kong, as well unrelated exporters Tricon Energy, USA; Vinmar International Ltd, USA and Cosmos VU Ltd, Hong Kong, to customers in India. The company has exported ***MT of MDC during the POI. At the stage of the provisional findings, it was seen from the questionnaire response that Tricon Energy, USA; Vinmar International Ltd, USA and Cosmoss VU Ltd, Hong Kong had not filed their questionnaire response despite exporting ***% of the total exports of subject goods to India of the producer Shandong Liaocheng Luxi Sixth Chemical Fertilizer Co. Ltd. Since the value chain was not complete, the Authority, at the stage of the provisional findings, had rejected the complete response of the cooperative producer/exporter Shandong Liaocheng Luxi Sixth Chemical Fertilizer Co. Ltd. However, post provisional Findings, Tricon Energy, USA; Vinmar International Ltd, USA and Cosmos VU Ltd, Hong Kong filed their invoices/packing list and completed the value chain. Since the value chain is complete, the Authority determines the export price of Shandong Liaocheng Luxi Sixth Chemical Fertilizer Co. Ltd. on the basis of their data so filed. The producer has claimed adjustments towards overseas transportation, Inland transportation, bank charges, insurance, customs & port handling charges, credit cost and VAT to arrive at ex factory export price. The Authority has allowed the same. The average export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin Table below.

Export Price for Shandong Dongyue Fluo-Silicon Materials Co. Ltd., China (Producer)

32. Shandong Dongyue Fluo-Silicon Materials Co. Ltd has reported export of the subject goods to India during the POI. The goods have been sold directly to customers in India. The sales to Indian customers are on both FOB and CIF basis. The company has exported ***MT of MDC to India during the POI. The producer has claimed adjustments towards overseas transportation, Inland transportation, bank charges, insurance, commission, credit cost and VAT to arrive at ex factory export price. The Authority has admitted the adjustments claimed by the exporter. Export price has been determined for packed form of the product. Accordingly, the average export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin Table below.

Export Price for Ningbo Juhua Chemical & Science Co. Ltd., China

33. Ningbo Juhua Chemical & Science Co. Ltd has reported export of subject goods to India during the POI. The goods have been sold through two channels. One is through its unrelated exporter HK Montage International Holding Ltd, Hong Kong who further sells the subject goods to another exporter/trader, namely, Farmasino Holding (HK) Ltd, Hong Kong and eventually to customers in India. The second channel is through Tricon Dry Chemicals LLC, USA to customers in India. The company has exported ***MT of MDC during the POI. At the stage of the provisional findings, it was seen from the questionnaire response that Tricon Dry Chemicals LLC, USA had not filed its questionnaire response despite exporting ***% of the total exports of subject goods to India of the producer Ningbo Juhua Chemical & Science Co. Ltd. Since the value chain was not complete, the Authority, at the stage of the provisional findings, rejected the complete response of the cooperative producer/exporter Ningbo Juhua Chemical & Science Co. Ltd. However, post provisional Findings, Tricon Dry Chemicals LLC, USA filed their questionnaire response and completed the value chain. Since the value chain is complete, the Authority determines the export price of Ningbo Juhua Chemical & Science Co. Ltd. on the basis of their data so filed. Accordingly, the average export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin Table below.

Export Price for Zhejiang Quhua Flour Chemistry Co. Ltd., China

34. Zhejiang Quhua Flour Chemistry Co. Ltd. has reported export of subject goods to India during the POI. The goods have been sold through unrelated exporters/traders Farmasino Holding (HK) Ltd, Hong Kong, Mercy Group Co. Ltd, Hong Kong and Polychem Corporation, Taiwan, to customers in India. The sales to Indian

customers are on FOB and CIF basis. The company has exported ***MT of MDC during the POI. It is seen from the questionnaire response that Mercy Group Co. Ltd, Hong Kong and Polychem Corporation, Taiwan have exported ***% of the subject goods of the producer/exporter Zhejiang Quhua Flour Chemistry Co. Ltd. but not filed their questionnaire response. The Authority, keeping in view that questionnaire response of ***% of the subject goods are available, accepts the response of the Zhejiang Quhua Flour Chemistry Co. Ltd. The producer/exporter has claimed adjustments towards overseas transportation, overseas insurance, Inland transportation, bank charges, credit cost, handling charges and VAT to arrive at ex factory export price. The Authority has admitted the adjustments claimed by the exporter. Separate export price has been determined for loose form of the product in view of significant difference in packing costs. Accordingly, the average export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin Table below.

Export price in case of non-cooperative producers and exporters from China PR

35. In view of the non cooperation of other exporters in this investigation, the export price for other exporters has been determined considering the export price of the cooperating exporter from China. The Authority has adopted lowest representative import price from amongst the cooperative producers/exporters during the POI as best facts available. Price adjustments have been considered towards overseas transportation, Inland transportation, bank charges, insurance, credit cost and VAT to arrive at ex factory export price. Separate export price has been determined for loose and packed form of the product in view of significant difference in packing costs. Accordingly, the average export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin Table below.

Export Price for Russia

36. The Designated Authority has considered information received from the DGCI&S and determined the export price considering all imports of the product under consideration in India. The price adjustments have been considered towards overseas transportation, Inland transportation, bank charges, insurance, commission, and port handling charges to arrive at ex-factory export price. Separate export price has been determined for loose and packed form of the product in view of significant difference in packing costs. Accordingly, the average export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin Table below.

Dumping Margin

37. Considering the normal values and export prices for the subject goods, separately for packed and loose/bulk form as determined above, dumping margin for the subject goods as a whole has been determined as follows. It is seen that the dumping margin for the subject goods is more than de-minimis and significant.

Dumping Margin Table

Country	Producer/Exporter	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	%	% Range
China PR	Shandong Liaocheng Luxi Sixth Chemical Fertilizer Co. Ltd. (Producer) and Lu Xi Chemical (Hong Kong) Co. Ltd., Hong Kong/Tricon Energy Ltd., USA/Vinmar International Ltd, USA/Cosmoss VU Ltd, Hong Kong (Exporters)	***	***	***	***	25-35
	Shandong Dongyue Fluo-Silicon Materials Co., Ltd.	***	***	***	***	40-50
	Ningbo Juhua Chemical & Science Co. Ltd. (Producer) and HK Montage International Holding Ltd, Hong Kong, Farmasino Holding (HK) Ltd, Hong Kong and Tricon Dry Chemicals LLC, USA (Exporters)	***	***	***	***	40-50

Country	Producer/Exporter	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	%	% Range
	Zhejiang Quhua Flour-chemistry Co. Ltd. (Producer) and Farmasino Holding (HK) Limited, Hong Kong, Polychem Corporation, Taiwan and Mercy Group Co., Ltd., Hong Kong (Exporters)	***	***	***	***	55-65
	Any Other Producer/Exporter	***	***	***	***	70-80
Russia	All Producers/Exporters	***	***	***	***	40-50

ASSESSMENT OF INJURY

Injury Determination

Views of the Domestic Industry

38. The submissions made by domestic industry with regard to injury and casual link are as follows:

- i. Imports of the product under consideration declined in 2012-13 and thereafter increased consistently.
- ii. Imports in relation to production and consumption in India declined in 2012-13 and thereafter increased consistently.
- iii. Market share of the subject counties declined in 2012-13 and consistently increased thereafter and is significant in the POI. Market share of the domestic industry has increased in the POI marginally from the previous year as a result of imposition of anti dumping duties and market share of countries already attracting ADD has declined.
- iv. With reduction in the prices either by the foreign producers or by these traders, either the Indian producers must realign their prices with the changes in the import prices or traders' resale prices, or the petitioners must loose orders.
- v. Domestic industry prices reflect the combined effect of the prices which have been reported in the trade journals and the prices that are being offered by the traders.
- vi. Imported goods have been undercutting the prices of the domestic industry in both loose and packed form. Price undercutting in respect of the product under consideration as a whole is positive from the subject countries.
- vii. The domestic industry has been forced to reduce the prices too steeply and too frequently.
- viii. Inventories with the domestic industry increased till 2013-14, but thereafter declined during the POI.
- ix. Performance of the domestic industry has deteriorated in terms of profits, return on investments and cash profits to a very significant extent till 2013-14 but during the POI, it has increased slightly.
- x. The decline in profitability of the domestic industry was due to reduction in the import prices without any justifiable reasons. The domestic industry is suffering significant financial losses as a result of significant dumping.

View of the Importers/consumers and other interested parties

39. The submissions made by the interested parties with regard to injury and casual link are as follows:

- i. Analysis of injury parameters should be made from the base year but domestic industry has made it from the year 2012-13.
- ii. The price undercutting of Russia is shown higher as compared to price undercutting of China whereas the landed value for China is higher than the landed value for Russia. It indicates that the price undercutting is created artificially.

- iii. No increase in imports from subject countries over the investigation period and in comparison to domestic production and total demand.
- iv. Market share of domestic industry has increased from 34% in the base year to 41% in the POI.
- v. Capacity, production, capacity utilization, productivity and sales of the domestic industry have increased during the injury period which indicates growth of the DI's ability to raise funds is not affected.
- vi. There is no price depression and suppression for the domestic industry.
- vii. Profitability, cash flows and ROCE have declined in the injury period but all these factors have increased in POI as compared to the previous year 2012-13.
- viii. Employment and wages have shown no injury to DI.
- ix. There exists no causal link between the alleged dumped import from the subject countries and injury to the domestic industry. There is inverse relation between decrease imports from subject countries and increase sales of domestic industry.
- x. The import prices from the subject countries have declined by 9% over the injury period whereas the price of domestic industry has increased by 7% over the same period. The effect of price on the domestic industry is due to the countries attracting ADD and not due to the subject countries.

Examination by the Authority

40. Rule 11 of the AD Rules read with its Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...." While considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
41. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
42. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry, para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments.”
43. For the examination of the impact of the imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.

Cumulative Assessment

44. Annexure II (iii) of the Anti Dumping Rules provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that: -
- the margin of dumping established in relation to the imports from each country/ territory is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries is less than three percent, the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article, and;
 - Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
45. In the present case-
- The margin of dumping from each of the subject countries is more than the limits prescribed above;
 - The volume of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed above; and
 - Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete inter se and with the like goods offered by the domestic industry in the Indian market. It is noted that there is no submission made by any interested party disputing cumulative assessment in the present case.
46. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports from the subject countries.
47. After elaborate investigations, interim anti dumping duty was earlier imposed on the imports of the product under consideration from European Union and USA vide notification dated 21st October, 2012 and definitive anti dumping duty was imposed vide notification dated 21st May, 2014. It is noted that whereas imports from EU and USA declined, imports from China and Russia increased between 2013-14 and the POI.

Demand and market share

48. For the purpose of assessment of the consumption/demand of the subject goods, the sales volume of DI and other Indian producers have been added to the total imports into India and the same has been summarized below:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Sales of Petitioners	MT	60,286	72,879	70,476	73,205
Sales of Other Producers	MT	33,921	33,597	37,734	33,830
Subject Countries – Imports	MT	16,514	334	6,757	15,629
Countries Attracting ADD	MT	60,974	56,324	62,444	47,571
Other Countries	MT	6,956	279	484	540
Total demand/Consumption	MT	178,651	163,413	177,895	170,774

49. It is noted that overall demand for the product under consideration shows marginal decline. Domestic industry contended that (a) the decline in demand is because of reduction in consumption by some pharma companies, (b) injury to the domestic industry is not because of decline in demand, as combined capacities with the Indian industry was 117,000 MT as against demand of 170,774 MT in India in the POI, (c) in view of significant demand for the product in the country, there was no need for the domestic industry to suffer on account of profits, return on investment and cash flow. The domestic industry further contended that whereas demand for the product under consideration showed an overall decline of 4.50%, imports from subject countries increased from 334 MT (2012-13) to 15,629 MT during the POI, thus showing almost 45 times increase over the period.

Volume Effects of Dumped Imports**Import Volume and Market Share**

50. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S. The volume of imports of the subject goods from the subject countries has been analyzed as under:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Import Volume					
Subject Countries	MT	16,514	334	6,757	15,629
China PR	MT	16,084	334	4,794	12,802
Russia	MT	430	-	1,963	2,827
Countries attracting ADD	MT	60,974	56,324	62,444	47,571
Other Countries	MT	6,956	279	484	540
Total Imports Volume	MT	84,444	56,936	69,685	63,739
Market Share in Import Volume					
Subject Countries	%	19.56	0.59	9.70	24.52
China PR	%	19.05	0.59	6.88	20.08
Russia	%	0.51	-	2.82	4.44
Countries attracting ADD	%	72.21	98.92	89.61	74.63
Other Countries	%	8.24	0.49	0.69	0.85
Total Imports	%	100.00	100.00	100.00	100.00

51. It is noted from the above table that imports of the subject goods from subject countries declined in 2012-13 and increased thereafter registering significant increase in the POI. It is noted that imports from countries attracting anti dumping duty declined with the imposition of anti dumping duty vide Notification No. 24/2013-Customs (ADD) dated 21st October, 2012 whereas imports from subject countries started increasing.

Imports in relative terms

52. Imports in relation to consumption and production have been analyzed as under:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Subject Countries Imports					
In relation to Indian Production	%	16.81	0.31	6.05	14.53
In relation to Indian Demand/Consumption	%	9.24	0.20	3.80	9.15

53. It is noted that imports in relation to production and consumption declined in 2012-13 and increased thereafter.

Price effect of imports

54. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any.

Price undercutting

55. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
China (Loose & Packed)					
Landed price of imports	Rs/MT	***	***	***	***
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	%	***	***	***	***
Price Undercutting (% Range)	%	Negative	Negative	Negative	Negative
Russia (Loose & Packed)					
Landed price of imports	Rs/MT	***	***	***	***
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	%	***	***	***	***
Price Undercutting (% Range)	%	Negative	-	Negative	5-15
Subject countries (Loose & Packed)					
Landed price of imports	Rs/MT	***	***	***	***
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	%	***	***	***	***
Price Undercutting (% Range)	%	Negative	Negative	Negative	Negative

56. The Authority notes that the landed prices of the subject goods from Russia was below the selling price of the domestic industry during the POI, however in the case of China PR, the same is slightly more than the selling price of domestic industry resulting in marginally negative price undercutting.

Price-underselling

57. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from the subject countries, as follows:

Particulars	Unit	China	Russia
Weighted Average Non Injurious Price	US\$/Mt	***	***
Weighted Average Landed Value	US\$/Mt	***	***
Price underselling	US\$/Mt	***	***
Price underselling	%	***	***
Price underselling	% Range	15-25	30-40

58. It is noted from the above table that the domestic industry has suffered significant price underselling during the investigation period on account of imports of the subject goods from the subject countries.

Price suppression and depression

59. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. Authority has considered the average price of loose and packed material for the purpose of this analysis. Table below shows the factual position:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Average Selling price of DI	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	70	87	107
Average Landed Value of subject countries	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	81	84	91
Cost to Sales	Rs./MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	105	133	132

60. It is noted from the table above that cost of sales have increased over the period and selling price of the domestic industry declined in 2012-13 but increased thereafter. Further, landed price of imports has shown same trend as the selling price. Increase in selling price is much less than the increase in cost of sales. Thus imports are causing significant price suppression in the domestic market.

Economic parameters of the domestic industry

61. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

62. Various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

i. Production, capacity and capacity utilization of the Domestic Industry

63. The production, domestic sales, capacity & capacity utilization of the domestic industry have been stated as follows:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Plant Capacity	MT	***	***	***	***
Plant Production	MT	***	***	***	***
Plant Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
Production PUC	MT	***	***	***	***
Domestic Sales Volumes	MT	60,286	72,879	70,476	73,205

64. The Authority notes that the product under consideration is jointly produced with Chloroform and Carbon Tetrachloride comes out as a by-product. Since the production facilities are common and the products are coproduced, capacity utilization has been examined by considering combined production of Methylene chloride and chloroform.

65. It is noted that one of the petitioner companies has enhanced capacity within the present injury period. Domestic sales, production and capacity utilization of the domestic industry have increased over the injury period. The domestic industry has contended that volume parameters are under the control of the domestic industry and domestic industry on its part is doing its best to produce and sell maximum volumes so that its fixed costs get observed over larger production. However, dumping is causing losses to the domestic industry.

ii. Market share

66. The effects of the dumped imports on the domestic sales and the market share of the domestic industry have been examined as below:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Market Share in Demand					
Sales of Domestic Industry	%	33.75	44.60	39.62	42.87
Sales of Other Producers	%	18.99	20.56	21.21	19.81
Subject countries - Imports	%	9.24	0.20	3.80	9.15
Imports from countries attracting ADD	%	34.13	34.47	35.10	27.86
Imports from Other Countries	%	3.89	0.17	0.27	0.32
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00

67. It is noted that market share of the domestic industry increased in 2012-13, declined in 2013-14 and thereafter increased in the POI. Market share of the subject countries declined in 2012-13 but increased thereafter significantly in the POI.

iii. Profits, return on investment and cash flow

68. The cost of sales, selling price and profit/loss of the domestic industry have been analysed as follows:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Cost of Sales - Average	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>105</i>	<i>133</i>	<i>132</i>
Selling Price - Average	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>70</i>	<i>87</i>	<i>107</i>
Profit/Loss	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>(140)</i>	<i>(184)</i>	<i>(47)</i>
PBIT	Rs Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>(169)</i>	<i>(215)</i>	<i>(57)</i>
Cash Profit	Rs Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>(116)</i>	<i>(149)</i>	<i>(22)</i>
ROI	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>(80)</i>	<i>(95)</i>	<i>(11)</i>

69. It is seen that the selling price of the domestic industry is below the level of cost of sales since 2012-13 resulting into losses. The domestic industry was suffering from injury in view of dumped imports from other countries as well. Low priced imports from countries currently attracting anti dumping duty forced the petitioners to reduce its prices and consequently the petitioner started incurring losses since 2012-13. The domestic industry has been able to increase its selling price in the POI with the imposition of anti dumping duties on countries attracting anti dumping duty. However, imports from subject countries have prevented the domestic industry from increasing its selling price even to the level of costs of sales and, therefore, the domestic industry continues to suffer financial losses in the POI.

70. The domestic industry is suffering cash losses and further, the return on investment also became negative in 2012-13 and the cash losses intensified in 2013-14, in view of significant dumping from countries now attracting anti dumping duty. Imposition of anti dumping duties on such countries have led to some marginal improvement in cash profit and return on investment in the POI, however dumped imports of subject countries prevents the domestic industry from recovering completely from ill effects of dumping.

iv. Inventories

71. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Average Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	167	328	117

72. It is noted from the above table that the average stock increased till 2013-14 and declined thereafter.

v. Employment and wages

73. The position with regard to employment and wages is as follows:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Number of Employees	No	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>104</i>	<i>101</i>	<i>102</i>
Wages	Rs Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>123</i>	<i>165</i>	<i>151</i>

74. It is seen that when employment is maintained within a particular range, wages show increasing trend over the injury period.

vi. Productivity

75. Data relating to productivity shows as follows:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>93</i>	<i>110</i>	<i>106</i>	<i>109</i>
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>114</i>	<i>113</i>	<i>114</i>

76. It is noted that the productivity of the domestic industry has increased and moved in the same direction as that of the production.

vii. Magnitude of Dumping

77. Magnitude of dumping, as an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry, shows that the dumping margins determined against the subject countries are above de minimis and significant.

viii. Ability to raise capital investment

78. It is noted that the petitioner companies are multi product companies and one of petitioner companies has enhanced capacities during the injury period. However, despite significant additional investment made in the year 2011-12, the domestic industry should have been able to increase its profit before interest, tax and depreciation. However, even after imposition of ADD on other countries, the industry is suffering with losses, thus, affecting the ability to raise capitals.

ix. Factors affecting domestic prices

79. Consideration of the import prices from subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market show that the landed value of imported material from subject countries are significantly below the selling price and non injurious price of the domestic industry, causing significant price undercutting and underselling in the Indian market. There is no viable substitute to this product. Demand for the product is not a factor responsible for price suppression faced by the domestic industry. It is thus evident that the only factor responsible for the domestic industry prices are the import prices of the product and the cost of production of the domestic industry. As the information would show, the imports prevented the domestic industry from increasing their prices in line with the increase in the cost.

x. Growth

80. Growth of the domestic industry is adverse, as growth with regard to profits, return on investments and cash flow was significantly negative during period of investigation except 2011-12.

xi. Industry recovering from past effect of dumped imports

81. The domestic industry has contended that various injury parameters illustrated under the Rules are not exhaustive, and thus the Authority may analyse any other factor showing injury to the domestic industry. It has been submitted that the domestic industry is trying to recover from the ill effects of dumping caused by other countries which are now attracting anti dumping duties. However, the dumped imports from current subject countries are preventing the growth of the domestic industry. It is seen in this regard that the domestic industry continues to incur losses, despite imposition of anti dumping duties on other countries.

Conclusion on material injury

82. After examining the volume and price effects of imports of the subject goods from the subject countries and its impact on the domestic industry, it is noted that volume of imports of subject goods from subject countries declined in 2012-13 and thereafter increased significantly in absolute terms and in relation to production and consumption in India. Market share of the subject countries declined in 2012-13 and increased thereafter. It is noted that the domestic industry has not suffered volume injury on account of dumped imports of subject goods from the subject countries. However, with regard to price effect on account of imports of the subject goods from the subject countries, it is noted that imports of the subject goods from subject countries are significantly undercutting the prices of domestic industry. Further, the domestic industry has suffered price suppression on account of imports of the subject goods from the subject countries in the POI. Profit, cash flow and return on investment remain negative. Despite imposition of anti dumping duty on other countries, the domestic industry is incurring losses in the POI because of the presence of dumped imports from the subject countries. With regard to consequent impact of the dumped imports on the domestic industry, it is concluded that even though the performance of the domestic industry has improved in respect of production, capacity utilization, domestic sales, market share, the performance deteriorated in terms of profits, return on investment and cash flows. Thus, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

Other Known Factors & Causal Link

83. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting, underselling and price suppression, and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping have been examined by the Authority to see whether any other factor, other than the dumped imports, could have contributed to injury to the domestic industry.

a) Volume and prices of imports from third countries

84. It is noted that imports of product under consideration from other countries are either negligible in terms of volume or are attracting anti dumping duties. It is noted that the import prices from subject countries are much higher during the POI.

b) Contraction of demand and changes in the pattern of consumption.

85. As noted earlier, demand scenario and pattern of consumption for the subject goods in the domestic market show that there has been decline in the demand of the products concerned over the injury period which has been attributed to consumption by some pharma companies. It is, however, seen that injury to the domestic industry is not because of decline in demand, as combined capacities with the Indian industry was 189,000 MT as against demand of 170,774 MT in India. In view of significant demand for the product in the country, there was no need for the domestic industry to suffer on account of profits, return on investment and cash flow.

c) Developments in technology:

86. Technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, development in technology is not a factor causing injury to the domestic injury.

d) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

87. There is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

e) Export performance of the domestic industry

88. The injury information examined by the Authority is for domestic operations only and, therefore, export performance has not caused injury to the Domestic Industry.

f) Productivity of the Domestic Industry

89. It is noted that the productivity of the domestic industry in terms of production per employee as well as production per day has increased over the period.

90. It is thus noted that listed known other factors do not show that the domestic industry could have suffered injury due to these other factors. The Authority examined whether the dumping of the product has caused injury to the domestic industry. The following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by dumped imports:

- a) The imports of the subject goods from the subject countries were significantly undercutting the prices of the domestic industry in the market.
- b) The domestic industry was prevented from increasing its prices. The price suppression suffered by the domestic industry is because of dumping of the product by the subject countries.
- c) The domestic industry is forced to sell at prices even below the cost of production which is resulting into significant financial losses. The price suppression caused by the imports thus results in financial losses in the POI.
- d) Performance of the domestic industry with regard to profits, cash flow and return on investments is negative as a result of price suppression and price undercutting. Thus, dumping of the product has led to deterioration in performance of the domestic industry in terms of profits, cash flow and return on investments.
- e) Despite imposition of anti dumping duty on other countries, the domestic industry is incurring losses in the POI because of the presence of dumped imports from the subject countries.

91. It is, therefore, concluded that the domestic industry suffered material injury due to the dumped imports.

Magnitude of Injury Margin**Injury Margin**

92. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry determined has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin during POI. The injury margins so determined are as under:-

Particulars	Unit	China	Russia
Weighted Average Non-Injurious Price	US\$/Mt	***	***
Weighted Average Landed Value	US\$/Mt	***	***
Injury Margin	US\$/Mt	***	***
Injury Margin	%	***	***
Injury Margin	% Range	15-25	30-40

Country	Producer/Exporter	Non-Injurious Price	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	%	% Range
China PR	Shandong Liaocheng Luxi Sixth Chemical Fertilizer Co. Ltd. (Producer) and Lu Xi Chemical (Hong Kong) Co. Ltd., Hong Kong/Tricon Energy Ltd., USA/Vinmar International Ltd, USA/Cosmos VU Ltd, Hong Kong (Exporters)	***	***	***	***	10-20
	Shandong Dongyue Fluo-Silicon Materials Co., Ltd.	***	***	***	***	10-20
	Ningbo Juhua Chemical & Science Co. Ltd. (Producer) and HK Montage International Holding Ltd, Hong Kong, Farmasino Holding (HK) Ltd, Hong Kong and Tricon Dry Chemicals LLC, USA (Exporters)	***	***	***	***	20-30
	Zhejiang Quhua Flour-chemistry Co. Ltd. (Producer) and Farmasino Holding (HK) Limited, Hong Kong, Polychem Corporation, Taiwan and Mercy Group Co., Ltd., Hong Kong (Exporters)	***	***	***	***	20-30
	Any Other Producer/Exporter	***	***	***	***	40-50
Russia	All Producers/Exporters	***	***	***	***	30-40

POST DISCLOSURE STATEMENT COMMENTS

Post Disclosure Statement comments of the opposing interested parties

93. Post disclosure comments of the opposing interested parties, in brief, are as follows:

- i. Since the Authority is making analysis of dumping margin and injury margin separately for loose/bulk and packed form of the product, the determination of dumping margin and injury margin should be done separately for loose/bulk and packed form of the product for the individual companies examined. The weighted average dumping margin and weighted average injury margin may be made on the basis of the weight of the loose/bulk and packed product for the export sales to India by them but not on the basis of simple average as it may lead to incorrect determination of dumping margin and injury margin.
- ii. The import data from IBIS shows higher imports. The share of Russia in total imports is de minimis as their share in the total imports is merely 2.94%. No analysis or reasons have been recorded in the Disclosure Statement to negate the contention that the imports reported in IBIS import data are correct. There is also no analysis of the actual imports by the cooperative exporters from China and one participating exporter from Russia with the imports reported in DGCI&S import data base for the respective subject countries.
- iii. The analysis with regard to the impact of the substantially high imports of about 80% from the countries attracting ADD has not been carried out as to how the imports from those countries are having no impact on the state of the domestic industry and the injury to the domestic industry is only due to the imports from the subject countries.
- iv. The observation in the Disclosure Statement that the normal value for China can be determined on any of the basis prescribed in Para 7 of Annexure I is flawed and is in violation of the mandatory procedure laid down in the case of Shenyang Matsushita 2005 (181) ELT 320 (SC).

- v. Since an exporter from Russia has filed its information in Appendix 1 for the domestic prices in Russia, the same may be considered for the determination of the normal value for China in view of the provisions of Para 7.
- vi. There is no injury to the domestic industry from the alleged dumped imports from the subject countries and there is absence of causal link.
- vii. Weighted average injury margin for the companies may be computed on the basis of the separate weight of the loose/bulk and packed product for the export sales to India by them.
- viii. The Dumping Margins for Shandong Liaocheng Luxi Sixth Chemical Fertilizers Co. Ltd. and Ningbo Juhua Chemical & Science Co. Ltd. have been rightly granted. However, Tricon Dry Chemicals LLC have not been included in the relevant trade channels in the dumping margin table.
- ix. The Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation states that:
 - (a) Construction of normal value is not in conformity with the provisions of AD Agreement. Usage of alternative methods of normal value determination is justified only if there are no sales of like product in the ordinary course of trade or when because of particular market situation or low volume of sales do permit a proper comparison.
 - (b) Even if the information provided by interested party is not ideal in all respects, it cannot be arbitrarily excluded from taking into consideration.
 - (c) Normal value has been constructed for JSC Khimprom in violation of Article 2 and 6.8 of AD Agreement. The Directorate General failed to take into account difficulties faced by Khimprom in procuring data of unrelated entities.
 - (d) Export price has been calculated on the basis of data provided by Indian producers and not based on the data violating Article 6.8. Applicable data provided by JSC Khimprom was not taken into account. The Authority failed to establish the existence of association or any compensatory arrangement between exporters and importers.
 - (e) Market share in demand of Russian exports constitutes only 1.66%. Such small percentage cannot cause any injury to the domestic industry.
 - (f) The Authority failed to address the positive conditions of domestic industry in 2011-2014 such as increase in market share in demand, sales. Overload of the domestic production capacity by 10% in 2012-13.
 - (g) No reasons have been presented as to why the negative dynamics of few factors outweighed the positive dynamics of a large amount of other factors.

Post Disclosure Statement comments of the Domestic Industry

94. Post Disclosure Comments of the Domestic Industry, in brief, are as follows:

- i. Domestic industry has suffered material injury and such injury is evidenced by adverse price effect of dumped imports from the subject countries.
- ii. The information is for the injury period and just not POI and preceding year. Otherwise, it defeats the very purpose of calling data for longer period. Since the product under consideration was being dumped from other countries in 2013-14, the domestic industry was facing injury in this period in respect of imports from those countries. In the POI, the suppressing/depressing effects were limited because of check on the dumping from other countries. The domestic industry was, however, still faced with pressure on profits for the reason that fresh dumping started from present subject countries.
- iii. In an unprecedented decision and in contravention to repeated affidavits filed by the Directorate before the Delhi High Court in NIP related writ petitions, the Minutes of Meeting circulated by the DGAD with regard to these writ petitions pending in the High Court, the NIP has been determined without adding return on capital employed on captive inputs. The interpretations being drawn by the DGAD from the NIP law in different cases are inconsistent with the law, and DGAD has filed unambiguous replies in these writ petitions fully supporting the NIP law. Thus, the proposal to determine NIP in the present case without adding return on capital employed

in captive inputs is tantamount to going beyond even the NIP law and introducing subjective assessment on an unambiguous fact. The proposal is inconsistent with the following:

- a. Rule 17(1)(b) which requires the Authority to determine quantum of Anti-dumping duty which would be adequate to address injury to the domestic industry;
- b. Annexure-III which requires the Authority to determine the cost of production considering the best utilization of raw materials and at period of investigation rates.
- c. The replies filed by the Designated Authority before the Delhi High Court in the following writ petitions wherein the NIP law has been challenged "as such" and "as applied". The Designated Authority has stated in these affidavits that if captively produced inputs are transferred at a rate based on the cost of production, then the Designated Authority allows reasonable returns on capital employed in production of captively produced inputs in addition to their cost of production.
- d. The Minutes of the meeting notified by the DGAD consequent to the meeting convened by the Designated Authority on 29.12.2015 to discuss the suggestions/comments received from various interested parties for amending provisions of Annexure III of Antidumping Rules. This meeting was chaired by the Designated Authority and attended by all the officers of DGAD. The then Consultant was also present in the meeting. These Minutes of Meeting were communicated by the DGAD vide email dated 20th January, 2016 wherein the Authority has stated that if the domestic industry accounts for the captively produced inputs at the cost of production, an additional return @ 22% on capital employed for assets utilized for producing such inputs is also allowed.

Examination by the Authority

95. The Authority notes that most of the post Disclosure Statement submissions made by the domestic industry and the opposing interested parties are repetitive in nature and have already been dealt with in the Disclosure Statement and again have been addressed in this Final Findings Notification under the appropriate headings. The additional issues to the extent considered relevant have been addressed as under:
 - i. As regards the argument that the normal value for China needs to be determined as per the hierarchy laid down in Para 7 of Annexure I, the Authority notes that there is no denying the fact that hierarchy must be followed, provided sufficient evidence with regard to the methodology is made available before the Authority. The Authority notes that the petitioner had not provided an evidence of price or constructed value in a market economy third country. The price from a market economy third country to other countries was also not made available by the petitioner. It may be noted that the prices in market economy third country could also not be adopted for the reasons that (a) the desired information has not been made available by any interested party, (b) the product under consideration involved a number of different types which vary in associated costs & prices; (c) price adjustments to determine the ex-factory prices are not available. The price from market economy third country to India could not be adopted as these imports are attracting anti dumping duty and, therefore, are dumped import prices. The Chinese producers or importers or any other interested party made no claim nor advanced any evidence either with regard to the price or the constructed value in a market economy third country. Further, the response of the cooperative producer from Russia was not complete and thus its data could not be analysed to the desired extent. Under the circumstances, the Authority is of the opinion that the only option available is to determine the normal value on "any other basis", considering estimates of the cost of production, duly adjusted, including a reasonable profit margin.
 - ii. As regards the argument that no analysis has been made on the countries attracting ADD causing injury, it is noted that the injury caused by the other countries attracting ADD is being addressed by the Anti-dumping duty currently imposed on them. Further, it has been specifically noted in the relevant part of this Notification that the imports from countries attracting ADD have declined whereas the imports from the present subject countries have increased.
 - iii. It is clarified that the determination of dumping margin and injury margin has been done separately for loose/bulk and packed form of the product for the individual companies examined and the weighted average dumping margin and the weighted average injury margin have been determined on the basis of the weight of the loose/bulk and packed product.

- iv. As regards the contention that import data from IBIS shows higher imports and the volume of imports from Russia on this basis is 2.94% and thus de-minimis, the Authority notes that the import data has been adopted on the basis of DGCI&S data.
- v. The claims of the Russian exporter with regard to determination of the normal value and dumping margin have been appropriately dealt in the dumping margin determined hereinabove.
- vi. The name of Tricon Dry Chemicals LLC has now been included in the relevant trade channels of the dumping margin table.
- vii. As regards the determination of individual dumping margin for Khimprom, the Authority reiterates that the normal value could not be determined on the basis of questionnaire response filed in view of significant deficiencies in the questionnaire response. The Authority holds that complete questionnaire response from the producer-exporter is must for determination of individual dumping margin.
- viii. As regards the low market share of Russia in demand/consumption of the product under consideration in India, the Authority notes that there is no de-minimis criteria on the basis of consumption of the product under consideration in India. The Rules provide negligibility test in terms of total imports of the product under consideration in India and it is seen that imports from Russia are beyond the limits prescribed under the law.
- ix. As regards injury suffered by the domestic industry in the past and dumping from other sources, the Authority notes that with imposition of Anti-dumping duty on imports from other sources, dumping has intensified from present set of countries. The current volume of imports from the subject countries must be seen in the light of past dumping and anti dumping duty imposed on the product.
- x. As regards positive developments in some parameters of the domestic industry, the Authority notes that the injury analysis is required to be carried out by considering overall performance of the domestic industry. The investigation has clearly shown that the performance of the domestic industry on collective and cumulative basis shows deterioration over the injury period.
- xi. As regards the contention that in contravention to repeated affidavits filed by the Directorate before the Delhi High Court in NIP related writ petitions and the Minutes of Meeting circulated by the DGAD with regard to these writ petitions pending in the High Court, the NIP was determined without adding return on capital employed on captive inputs and thus, the proposal to determine NIP in the present case without adding return on capital employed in captive inputs is tantamount to going beyond even the NIP law and introducing subjective assessment on an unambiguous fact, the Authority notes that the Directorate has indeed filed three counter affidavits in the Delhi High Court in three separate civil writ petitions bearing numbers 145 of 2013; 2453 of 2013 and 3782 of 2013 and in all the three writ petitions, the Directorate has taken the consistent stand that if captively produced inputs are transferred at a rate based on cost of production as per the books of accounts by the domestic industry, then Designated Authority allows reasonable return on capital employed in production of captively produced inputs in addition to their cost of production.
- xii. In the civil writ petition number 145 of 2013, the counter affidavit has been filed stating that “It is further submitted that Annexure to the antidumping rules further mandates the Designated Authority to consider inter alia the best utilization of raw materials and utilities at the rates adopted in the books of accounts maintained by the domestic industry. The Designated Authority, therefore, considers the actual price for the purchased inputs and in respect of the *captively* produced inputs at the transfer rate adopted in the books of accounts maintained by the domestic industry. The Designated Authority further allows the return on investment for the captively produced inputs if such inputs were transferred at cost of production”.
- xiii. Further, in the civil writ petitions 2453 of 2013 and 3782 of 2013, the counter affidavit has been filed stating that “The principle for determination of NIP provides that the actual rates (as per actual value of inputs consumed) as per cost and financial records of the domestic producers are to be considered after necessary examination and reconciliation. If captively produced inputs are transferred at a rate based on cost of production, then Designated Authority allows reasonable return on capital employed in production of captively produced inputs in addition to their cost of production”.
- xiv. Keeping in view this consistent stand taken in the High Court on the methodology for determination of NIP **as per the NIP law**, the Authority is of the view that the domestic industry’s contention that the proposal of the Authority to determine NIP in the present case without adding return on capital employed in captive inputs will

not only tantamount to going beyond the NIP law but also be in contravention of the stand taken by the Authority before the Delhi High Court has merit. In this regard, the Authority has noted that the domestic industry in the present case has transferred the captively produced inputs at the rates based on its cost of production (as per the cost and financial records maintained by the domestic industry). The Authority, therefore, has decided to determine the NIP of the domestic industry in the present case by allowing reasonable return on capital employed used in the production of captively produced inputs in addition to their cost of production. The NIP of the domestic industry has been revised accordingly.

INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

96. The Authority recognizes that the imposition of Anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of Anti-dumping measures. On the contrary, imposition of Anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of Anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of Anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the Anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

RECOMMENDATION

97. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- The product under consideration has been exported to India from the subject countries below the normal values.
 - The domestic industry has suffered material injury on account of the subject imports from the subject countries.
 - The material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries.
98. The Authority notes that the investigation was initiated and it was notified to all the known interested parties. Adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of duty is required to offset dumping causing injury. The domestic industry has requested for imposition of anti dumping duty to address injury being suffered.
99. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends imposition of Anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Anti-dumping duty equal to the amount indicated in the table below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Duty Table

Sl. No.	Sub-heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
1	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	China PR	China PR	Shandong Dongyue Fluo Silicon Materials Co., Ltd.	Shandong Dongyue Fluo Silicon Materials Co., Ltd.	143.71	MT	US Dollar

2	2903 12	- do -	China PR	China PR	Zhejiang Quhua Flour-Chemistry Co. Ltd.	Zhejiang Quhua Flour-Chemistry Co. Ltd./Farmasino Holding (HK) Limited, Hong Kong/ Polychem Corporation, Taiwan/ Mercy Group Co., Ltd., Hong Kong	166.83	MT	US Dollar
3	2903 12	- do -	China PR	China PR	Shandong Liaocheng Luxi Sixth Chemical Fertilizer Co. Ltd.	Shandong Liaocheng Luxi Sixth Chemical Fertilizer Co. Ltd.	122.14	MT	US Dollar
4	2903 12	- do -	China PR	China PR	Shandong Liaocheng Luxi Sixth Chemical Fertilizer Co. Ltd.	Lu Xi Chemical (Hong Kong) Co. Ltd., Hong Kong	122.14	MT	US Dollar
5	2903 12	- do -	China PR	China PR	Shandong Liaocheng Luxi Sixth Chemical Fertilizer Co. Ltd.	Lu Xi Chemical (Hong Kong) Co. Ltd., Hong Kong and Tricon Energy Ltd., USA/Vinmar International Ltd, USA/Cosmoss VU Ltd, Hong Kong	122.14	MT	US Dollar
6	2903 12	- do -	China PR	China PR	Ningbo Juhua Chemical & Science Co. Ltd.	Ningbo Juhua Chemical & Science Co. Ltd./ HK Montage International Holding Ltd, Hong Kong/ Farmasino Holding (HK) Ltd, Hong Kong/Tricon Dry Chemicals LLC, USA	162.16	MT	US Dollar
7	2903 12	- do -	China PR	China PR	Any combination other than the combinations specified above		279.78	MT	US Dollar
8	2903 12	- do -	China PR	Any	Any	Any	279.78	MT	US Dollar
9	2903 12	- do -	Any country other than subject countries	China PR	Any	Any	279.78	MT	US Dollar

10	2903 12	- do -	Russia	Russia	Any	Any	219.00	MT	US Dollar
11	2903 12	- do -	Russia	Any	Any	Any	219.00	MT	US Dollar
12	2903 12	- do -	Any country other than subject countries	Russia	Any	Any	219.00	MT	US Dollar

***Note:** Where there is overlapping of Anti-dumping duty on the subject goods with respect to a subject country in different customs notifications, the duty applicable to that subject country shall be one imposed under the customs notification in which the said country has been specifically mentioned under the Column “Country of Origin”.

100. Subject to the above, the Authority confirms the Preliminary Findings Notification No. 14/33/2014-DGAD dated 30.10.2015.
101. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.
102. An appeal against the findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority